राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 3 सोलहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का बीसवां दिवस संख्या 6

बुधवार,
19 फरवरी 2025

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री वासुदेव देवनानी, अध्यक्ष, पदासीन)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश।)

श्री अध्यक्ष: नमस्कार। राम-राम। सभी माननीय सदस्यों से, जैसी दलों के नेताओं से बातचीत हुई है, आपसे निवेदन करता हूं कि अपनी सीटों पर विराजें। मैं व्यवस्था देता हूं। आप सीटों पर जाइये। ...(व्यवधान)... व्यवस्था सीटों पर जाने के बाद होती है, पहले नहीं होती। कोई भी व्यवस्था सीटों पर जाने के बाद होती है, जाइये अपने स्थानों पर बैठिये।

आज छत्रपति शिवाजी का जन्मदिन भी है। इस सदन की बड़ी श्रेष्ठ परम्पराएं भी रही हैं और हमेशा वित्त मंत्री जब भी अपना बजट प्रस्तुत करते हैं, वह शान्ति से होता है। आपके जो मुद्दे थे, उन पर मेरी आप सब लोगों से हुई बातचीत के अनुसार, कल जीरो आवर के बाद सरकार अपनी बात रखेगी। अब मैं आग्रह करता हूं, उप मुख्य मंत्री दिया कुमारी आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 का उपस्थापन करेंगी। श्रीमती दिया कुमारी।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 का उपस्थापन

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान प्रस्तुत कर रही हूं।

2. माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रथम वर्ष में ही प्रदेश में विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करते हुए, जनता द्वारा व्यक्त किये गये विश्वास को सही प्रमाणित किया है। मुझे सम्मानित सदन को अवगत कराते हुए अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है कि माननीय मुख्य मंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के विकास की द्योतक GSDP वर्ष 2025-26 में बढ़कर 19 लाख 89 हजार करोड़ (उन्नीस लाख नवासी हजार करोड़ रुपये से अधिक होने का

अनुमान है। हम प्रदेश में विकास की गति को इसी प्रकार निरन्तर रख वर्ष 2030 तक $ 350 Billion की अर्थव्यवस्था (Economy) का निर्माण करने के लिए कटिबद्ध हैं।

3. हमने अल्प अवधि में ही पूंजीगत व्यय में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि करते हुए 9 हजार 600 किमी. से अधिक नवीन सड़कों का निर्माण एवं 13 हजार किमी. से अधिक सड़कों का उन्नयन किया है। साथ ही, माननीय प्रधान मंत्री जी के अभूतपूर्व सहयोग से राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC - ERCP) को धरातल पर उतारने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

4. Rising Rajasthan Global Investment Summit के अन्तर्गत देश-विदेश के निवेशकों ने हमारी सरकार द्वारा स्थापित Policy Framework में विश्वास दिखाते हुए 35 लाख करोड़ (पैंतीस लाख करोड़ रुपये से अधिक राशि के MoUs हस्ताक्षरित किये हैं। हमने आमजन से किये अपने वादों की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए जन घोषणा पत्र की 58 (अट्ठावन) प्रतिशत तथा बजट घोषणा की 73 (तिहत्तर) प्रतिशत प्रगति भी सुनिश्चित की है। मैं यहां माननीय सदस्यों को आगे भी सभी वादों का तीव्र गति से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आश्वस्त करते हुए कहना चाहूंगी-

"सबकी फिंक्र में खुद को मैं मिटाती हूं।
हर वादा अपना, दिल से मैं निभाती हूं।।"

हम 'सर्वजन हिताय' की सोच के साथ इस बजट के माध्यम से प्रदेश एवं प्रदेशवासियों के सर्वांगीण विकास को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का भरसक प्रयास करेंगे।

आधारभूत संरचना (Infrastructure) :

पेयजल :

5. मैं सदन के माध्यम से माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीया केन्द्रीय वित्त मंत्री जी का जल जीवन योजना का समय वर्ष 2028 (दो हजार अट्ठाइस) तक बढ़ाकर प्रदेशवासियों हेतु संजीवनी प्रदान करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी। हमने विगत एक वर्ष में कार्य को गति देते हुए एक हजार 301 करोड़ (एक हजार तीन सौ एक करोड़) रुपये लागत के कार्यादेश तथा 41 हजार 621 करोड़ (इकतालीस हजार छह सौ इक्कीस करोड़) रुपये की लागत के कार्यों की निविदाएं जारी कर दी हैं।

आगामी वर्ष 20 लाख घरों में connections दिये जाने के साथ ही, प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधा हेतु 425 करोड़ (चार सौ पच्चीस करोड़) रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 1 देखें।)

6. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों हेतु अमृत 2.0 योजना के अन्तर्गत 183 (एक सौ तिरासी) नगरीय निकायों में पेयजल आपूर्ति के 5 हजार 123 करोड़ (पांच हजार एक सौ तेईस करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये गये हैं। अमृत योजना के साथ ही पेयजल समस्या से ग्रसित

शहरी क्षेत्रों में समयबद्ध रूप से पेयजल की समुचित व्यवस्था के लिए मैं मुख्य मंत्री जल जीवन मिशन (शहरी) प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूं।

इस योजनान्तर्गत चरणबद्ध रूप से 5 हजार 830 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 2 देखें।)

7. प्रदेशवासियों को आने वाली ग्रीष्म ऋतु में पेयजल संकट का सामना न करना पड़े, इस दृष्टि से मैं आगामी वर्ष एक हजार Tube wells व एक हजार 500 Handpumps लगाने की घोषणा करती हूं। साथ ही, Summer Contingency के अन्तर्गत माह जुलाई, 2025 तक अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने के लिए 142 करोड़ (एक सौ बयालीस करोड़) रुपये का प्रावधान करना भी प्रस्तावित है।

8. प्रदेश के कोने-कोने तक पेयजल की योजनाओं का समुचित संचालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्र के बजट में JJM हेतु उल्लिखित O&M (operation and maintenance) Policy की तर्ज पर राज्य के लिए Policy बनाये जाने के साथ ही, तकनीकी अधिकारियों/कर्मचारियों का संविदा Cadre बनाते हुए एक हजार 50 पद सृजित किये जाने की मैं घोषणा करती हूं।

ऊर्जा :

9. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर एवं Surplus State बनाने के साथ ही चहुंओर खुशहाली लाने के लिए आगामी वर्ष 6 हजार 400 Mega Watt (MW) से अधिक अतिरिक्त उत्पादन किये जाने की मैं घोषणा करती हूं। इसके साथ ही आगामी वर्ष 5 हजार 700 Mega Watt (MW) (पांच हजार सात सौ मेगावॉट) ऊर्जा उत्पादन के कार्य हाथ में लिये जाने भी प्रस्तावित हैं।

10. साथ ही, प्रदेशवासियों को बिजली की सुचारू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए-

I. रबी, 2025 हेतु विद्युत वितरण के Peak Supply में वृद्धि कर 20 हजार 700 Mega Watt (MW) (बीस हजार सात सौ मेगावॉट) बिजली Supply की जानी प्रस्तावित करती हूं।

mkd/rtm/19.02.2025/11:20/1b

II. आगामी वर्ष 50 हजार नये कृषि तथा 5 लाख domestic connections दिये जाने की मैं, घोषणा करती हूं।

III. इसके साथ ही अधिक दर पर अन्य राज्यों के साथ Banking करने की व्यवस्था को मैं, समाप्त किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

11. माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारे प्रदेश को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और आगे ले जाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के विशेष प्रयासों से, निजी क्षेत्र के माध्यम से आगामी वर्ष 10 Giga Watt (GW) ऊर्जा का उत्पादन

प्रारम्भ करने तथा 10 ही Giga Watt (GW) के ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना का कार्य हाथ में लिया जाना भी प्रस्तावित है।

12. आगामी वर्ष, 765 (सात सौ पैंसठ) केवी का एक, 400 केवी के पांच, 220 केवी के तेरह, 132 केवी के अट्ठाइस एवं 33/11 केवी के एक सौ तैंतीस GSS के निर्माण व विद्युत लाइनों के विस्तार सम्बन्धी कार्य किये जायेंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं:-

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

13. हमारा ध्येय निःशुल्क घरेलू बिजली योजना में लाभार्थी परिवारों को और अधिक लाभ देने के साथ ही, प्रदेश पर सतत् रूप से आने वाले वित्तीय भार पर नियंत्रण करना भी है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लागू की गई महत्वाकांक्षी योजना 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' को leverage कर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के लाभान्वित परिवारों को चरणबद्ध रूप से निःशुल्क Solar Plants लगाते हुए 100 Units से बढ़ाते हुए 150 Units बिजली प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूं।

श्री अध्यक्ष: बीच में बातचीत नहीं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये खत्म कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिये। भाई, दोनों ओर से कोई नहीं बोलेगा।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): इस क्रम में, जिन अल्प आय वर्ग के परिवारों के घरों पर Solar Plant हेतु पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है, उनके लिए भी सामुदायिक Solar Plants स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

सड़क :

14. हम सभी के प्रेरणास्रोत, देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष, देश उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लेकर मना रहा है। आज मैं, माननीय सदस्यों को उनका, वर्ष 2002 में कहा कथन याद दिलाना चाहूंगी-

"Today when people talk of 'Connectivity' in cities, they mean digital connectivity, faster internet, email on mobile phones etc. In contrast, in many villages, 'Connectivity' still means having a good, all weather road that will help the villagers to take their goods to the nearest market or to take the patients in their midst to the nearest hospital."

अर्थात "आज शहरों में जब लोग 'कनेक्टिविटी' की बात करते हैं, तो उनका मतलब होता है डिजिटल कनेक्टिविटी, तेज इंटरनेट, मोबाइल फोन पर ईमेल आदि। इसके विपरीत, गांवों में, 'कनेक्टिविटी' का मतलब अभी भी अच्छी सड़क से है, जो ग्रामीणों को उनके द्वारा बनाये गये उत्पादों को पास के बाजार में ले जाने तथा मरीजों को पास के अस्पताल में ले जाने में सहायक हो।"

उक्त कथन की सामयिकता से आज भी हम सभी सहमत होंगे। इसी क्रम में-

15. आगामी वर्ष, State Highways, Bypass Roads Flyovers, Elevated Roads, ROBs व RUBs, Bridges आदि के निर्माण, repair तथा उन्नयन के कार्य 5 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लागत से हाथ में लिये जाने की मैं, घोषणा करती हूं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटन पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

बहुत लम्बी है, बहुत लम्बी सूची है, अध्यक्ष महोदय। एक बार पेज तो पलटूं, बहुत सारी सड़कें हैं,सभी के लिए।

श्री अध्यक्षः सबकी हैं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 16. आगामी वर्ष प्रदेश में अर्थव्यवस्था की जीवन धारा के रूप में 2 हजार 750 किलोमीटर से अधिक लम्बाई के 9 Green Field Expressways के कार्य लगभग 60 हजार करोड़ रुपये की लागत से Hybrid Annuity Model (HAM)/BoT पर हाथ में लिए जाने की मैं, घोषणा करती हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इस पर टोल लगा रखा है।

श्री अध्यक्षः बैठिये, बैठिये। नो, डोटासरा जी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 17. प्रदेश में गत कुछ वर्षों में वर्षा के कारण सड़कें काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। अतः existing road network की स्थिति को पुनः सुधारने की दृष्टि से, लगभग 21 हजार किलोमीटर नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य 6 हजार करोड़ रुपये की लागत से चरणबद्ध रूप से किये जाने प्रस्तावित हैं। प्रथम चरण में, आगामी वर्ष प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 10-10 करोड़ रुपये की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों के कार्य करवाये जाने की घोषणा करती हूं। मरूस्थलीय क्षेत्रों में दूरियां अधिक होने के कारण यह राशि 15-15 करोड़ रुपये प्रति विधान सभा क्षेत्र प्रस्तावित है। (..व्यवधान..)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 12 महीने से सड़कें टूटी पड़ी हैं।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्य, बैठिये। आप खड़े होंगे तो ये भी खड़े होंगे, फिर मुझे मत कहना, कोई खड़ा नहीं हो।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): जी, माननीय अध्यक्ष महोदय। टूटी-फूटी सड़कें ही मिली थीं।

श्री अध्यक्षः श्रीचन्द जी आप बैठें। नो, आप बैठिये। इधर बैठाया तो उधर से।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 18. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY)-चतुर्थ चरण के अंतर्गत प्रदेश में लगभग एक हजार 600 बसावटों को चरणबद्ध रूप से आगामी 2 वर्षों में डामर सड़कों से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

19. चरणबद्ध रूप से 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में Cement Concrete के अटल प्रगति पथ के निर्माण करवाये जाने की घोषणा करती हूं। आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपये की लागत से 250 गांवों में कार्य हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं।

Bhs/Rtm/19.02.25/11.20/1c

20. प्रदेश के प्रमुख शहरों में Heavy Traffic के बढ़ते दबाव से राहत दिलाते हुए सड़क सुरक्षा तथा सुचारु आवागमन सुनिश्चित करने की दृष्टि से-

I. प्रथम चरण में बालोतरा, जैसलमेर, जालोर, सीकर, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, डीग सहित 15 शहरों में 'Ring Roads' के निर्माण का कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। इस हेतु DPR बनाने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

II. जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं अजमेर की विभिन्न सेक्टर रोड के 575 करोड़ (पाँच सौ पचहत्तर करोड़) रुपये की लागत के कार्य हाथ में लिये जाने प्रस्तावित हैं।

III. जयपुर शहर के Traffic की स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से 250 करोड़ रुपये के विभिन्न आवश्यक कार्य करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, Bus Rapid Transit System (BRTS) हेतु बनाये गये Corridor को अनुपयोगी व आवागमन में बाधक design के कारण हटाया जाना प्रस्तावित है।

21. प्रदेश में आमजन को यातायात की सुविधा सुलभ करवाने तथा यातायात के बढ़ते दबाव के प्रबन्धन की दृष्टि से-

I. Roadways के द्वारा 500 नयी बसें GCC Model पर उपलब्ध करवाये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। साथ ही, शहरी क्षेत्रों हेतु भी 500 बसें राजकीय शहरी ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन के माध्यम से GCC Model पर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

II. Jaipur Metro के Second Phase को गति देते हुए केन्द्र सरकार के साथ, Joint Venture में स्थापित Rajasthan Metro Rail Corporation के माध्यम से 12 हजार करोड़ रुपये की लागत से सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र से अम्बाबाड़ी एवं विद्याधरनगर (टोडी मोड़ तक) के कार्य को हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, जगतपुरा एवं वैशाली नगर क्षेत्रों में Metro के विस्तार हेतु DPR बनवायी जायेगी।

III. समस्त संभागीय मुख्यालयों हेतु Comprehensive Mobility Plan भी बनवाया जायेगा।

सुनियोजित विकास एवं नागरिक सुविधायें :

क्षेत्रीय एवं ग्रामीण विकास :

22. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसाकि सर्वविदित है, हमारा प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के साथ ही Regional Disparities से भी परिपूर्ण है। इस कारण हम प्रदेश के कोने-कोने में निवास करने वाले परिवारों की 'Quality of Life' improve करने के लिए प्रयासरत हैं। इसी क्रम में-

1. 'डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना' के साथ-साथ, 17 दिसम्बर, 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से प्रारम्भ की गई 'पंचगौरव योजना' को भी गति देने के लिए, आगामी वर्ष 550 करोड़ (पांच सौ पचास करोड़) रुपये के कार्य करवाये जाना प्रस्तावित करती हूँ।

II. साथ ही, डांग, मगरा, मेवात एवं बृज क्षेत्रीय विकास योजनाओं हेतु आगामी वर्ष 50-50 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 100-100 करोड़ रुपये किये जाने की भी मैं, घोषणा करती हूँ।

23. इस क्रम को और आगे बढ़ाते हुए आगामी वर्ष से प्रदेश की अन्तरराष्ट्रीय सीमा के निकट निवास करने वाले परिवारों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए 'मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम' प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये का fund स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

24. प्रदेश में अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण के साथ ही विशेष रूप से जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति की बसावटों के निवासियों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध करवाने की दृष्टि से SCSP एवं TSP Funds की राशि को आगामी वर्ष बढ़ाते हुए एक हजार 750 करोड़ (एक हजार सात सौ पचास करोड़ रुपये किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

25. देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ की गयी Aspirational Districts योजना की तर्ज पर प्रदेश में सबसे पिछड़े 35 Blocks (पैंतीस ब्लॉक्स) में विकास को गति देने के लिए आगामी वर्ष, 75 करोड़ (पचहत्तर करोड़ रुपये) का प्रावधान कर गुरु गोलवलकर Aspirational Blocks Development Scheme लागू करने की घोषणा करती हूँ।

26. ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत परिवारों को livelihood हेतु सम्बल देने की दृष्टि से आगामी वर्ष, महात्मा गांधी नरेगा (MGNREGS) योजनान्तर्गत 3 हजार 400 लाख मानव दिवसों का सृजन प्रस्तावित है।

27. स्वामित्व योजना के अन्तर्गत समस्त राजस्व ग्रामों का Drone Survey पूर्ण कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किये जाने की घोषणा करती हूँ।

नगरीय विकास :

28. प्रदेश के सुनियोजित विकास एवं Civic Amenities यथा-Parking, Renovation, Residential Flats, Bus Stands आदि के विस्तार एवं उन्नयन हेतु विभिन्न कार्य 780 करोड़ (सात सौ अस्सी करोड़) रुपये से अधिक की लागत से करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 5 देखें।)

29. प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के समावेशी विकास, पलायन की रोकथाम, Sewerage, Drainage, Sanitation तथा Waste Disposal हेतु लगभग 12 हजार 50 करोड़ (बारह हजार पचास करोड़) रुपये की लागत से 7 वर्षों की अवधि की पंडित दीनदयाल उपाध्याय शहरी विकास योजना Implement (क्रियान्वित) किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखें।)

30. नवगठित नगरीय निकायों सहित अन्य क्षेत्रों में आगामी वर्ष, महिलाओं के लिए 500 Pink Toilets का 175 करोड़ (एक सौ पचहत्तर करोड़) रुपये की लागत से निर्माण करवाया जाना प्रस्तावित है।

औद्योगिक विकास :

31. सांस्कृतिक धरोहर के साथ-साथ आज हमारा प्रदेश Economic and Commercial Activities का प्रमुख केन्द्र बन चुका है। Rising Rajasthan Summit के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों को हम समयबद्ध रूप से धरातल पर उतारना सुनिश्चित करेंगे। इस दिशा में-

I. Investment facilitation हेतु स्थापित 'Single Window - One Stop Shop' का सुदृढ़ीकरण करते हुए वर्तमान में उपलब्ध विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त Online Permissions की संख्या को बढ़ाकर 149 (एक सौ उनचास) करने की मैं, घोषणा करती हूँ।

II. इस 'Single Window' की utility तथा Efficiency में वृद्धि की दृष्टि से विभागों हेतु Competitive Index जारी किया जाना प्रस्तावित है।

III. Rising Rajasthan के अन्तर्गत हस्ताक्षरित MoUs के क्रियान्वयन को गति देने के लिए effective co-ordination/hand holding के लिए PMU का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है।

IV. निवेशकों को समयबद्ध रूप से अपना संस्थान स्थापित करने में सहयोग देने की दृष्टि से बिचून-जयपुर, भिवाड़ी-खैरथल तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में Flatted Factory की व्यवस्था लागू की जायेगी। इसके साथ ही Plug and Play Model पर भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जायेंगे।

32. प्रदेश में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन करने के साथ ही Service Sector में निवेश बढ़ाने के उद्देश्य से Global Capability Centre (GCC) Policy लाया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक निवेश के साथ-साथ राज्य में Trading Sector के विकास एवं संवर्द्धन हेतु Rajasthan Trade Promotion Policy भी लायी जायेगी।

33. प्रदेश में उद्यमियों एवं निवेशकों के लिए बेहतर औद्योगिक वातावरण तैयार किये जाने तथा औद्योगिकीकरण की गति को तीव्र करने के लिए औद्योगिक पार्क व क्षेत्रों की स्थापना सहित अन्य आधारभूत कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर रख रही हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 7 देखें।)

34. प्रदेश में नये निवेश को आकर्षित करने के साथ ही वर्तमान में स्थापित उद्योगों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना भी हमारी प्राथमिकता है। इस क्रम में-

I. पूर्व से स्थापित Industrial Areas में आधारभूत संरचना उन्नयन के लिए 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये का व्यय किये जाने की घोषणा करती हूँ।

II. Private Industrial Parks/Estates में भी CETP स्थापित करने हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।

35. प्रदेश में आधारभूत संरचना के उन्नयन के साथ ही अर्थव्यवस्था की अधिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए DMIC (Delhi Mumbai Industrial Corridor) से लिंक कर 2 Logistics Parks स्थापित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही, logistic cost में कमी लाकर समुचित planning हो सके, इस दृष्टि से 'PM Gati Shakti' updation System बनाया जायेगा।

Kas/rtm/19.02.2025/11.30/1d

पर्यटन, कला एवं संस्कृतिः

36. प्रदेश में पर्यटन की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए, पर्यटन क्षेत्र का विकास करने की दृष्टि से जहाँ एक ओर हमने Rajasthan Tourism Infrastructure and Capacity Building Fund (RTICF) से 750 करोड़ (सात सौ पचास करोड़) रुपये से अधिक राशि के आधारभूत संरचना सम्बन्धी कार्य हाथ में लिये हैं, वहीं प्रदेश को Global Centre Stage पर लाने के लिए देश-विदेश में Travel Bazar, Cultural Programmes, Rajasthan Calling जैसे events / road shows भी किये हैं। इसी कड़ी में, 8 एवं 9 मार्च, 2025 को प्रथम बार IIFA Awards का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में होने जा रहा है।

प्रदेश में पर्यटन गतिविधियों को नयी ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए आगामी वर्ष 975 करोड़ (नौ सौ पचहत्तर करोड़) रुपये के Infrastructure Development के कार्य हाथ में लिये जाने के साथ ही विभिन्न धार्मिक स्थलों पर आधारभूत संरचना व सुविधा विकसित किये जाने सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 8 देखें)

37. राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिलों में स्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा Eco-Tourism Sites-त्रिपुरा सुंदरी, मानगढ़धाम, बेणेश्वरधाम, सीतामाता अभ्यारण्य, ऋषभदेव, गौतमेश्वर मंदिर, मातृ कुण्डिया आदि को सम्मिलित करते हुए 100 करोड़ रुपये व्यय कर 'Tribal Tourist Circuit' विकसित किये जाने की घोषणा करती हूँ।

38. प्रदेश में Rural Tourism को बढ़ावा देने के लिए बरौली धाऊ (कामां)-डीग, देवमाली-ब्यावर, पिपलांत्री-राजसमंद, महनसर-झुंझुनूं, भूरी पहाड़ी (रणथम्भौर)-सवाई माधोपुर, केमला (इंदरगढ़)-बूंदी, रूसी रानी (दबकन)-अलवर, आभानेरी-दौसा, शेरगढ़-बारा एवं लापोडिया (मालपुरा)-टोंक को विकसित किया जायेगा। इस हेतु 20 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

39. वीर सैनिकों के शौर्य के प्रतीक के रूप में स्थापित War Museum-जैसलमेर में आधारभूत संरचना एवं सुविधायें विकसित किये जाने सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे।

40. प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य एवं अतिरिक्त सुविधा की दृष्टि से वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष 6 हजार वरिष्ठजन को हवाई मार्ग से यात्रा के अतिरिक्त 50 हजार (पचास हजार) वरिष्ठजन को सामान्य श्रेणी Sleeper के स्थान

पर AC Train से तीर्थ यात्रा करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

41. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा प्रयागराज-महाकुम्भ में की गयी घोषणा के क्रम में, राज्य में स्थापित विभिन्न मंदिरों के उन्नयन हेतु 101 करोड़ रुपये तथा राज्य के बाहर स्थित देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों के लिए 60 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं तथा मंदिरों में भोग की राशि को बढ़ाया जाकर 3 हजार रुपये प्रतिमाह एवं पुजारियों के मानदेय को बढ़ाया जाकर 7 हजार 500 रुपये प्रतिमाह किया जाना भी प्रस्तावित है।

42. गुलाबी नगरी के रूप में विश्वविख्यात UNESCO World Heritage City-जयपुर, वर्ष 2027 (दो हजार सत्ताइस) में अपनी स्थापना के 300 वर्ष पूर्ण कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर के दृष्टिगत जयपुर निवासियों एवं पर्यटकों को यहाँ की धरोहर, कला एवं संस्कृति से परिचित करवाने के लिए वर्ष पर्यन्त विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जयपुर के आराध्य के नाम पर गोविन्द देव जी कला महोत्सव के आयोजन की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

43. प्रदेश में पर्यटकों को Intra-state Travel सुविधा के साथ ही City Tours की व्यवस्था उपलब्ध करवायी जायेगी। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट 9 देखें)

44. आगामी वर्ष ऐतिहासिक दस्तावेजों के Digitization एवं Artificial Intelligence Based BOT से जोड़े जाने के कार्य हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हुए Gyan Bharat Mission के अन्तर्गत लाया जाना प्रस्तावित है।

युवा विकास एवं कल्याण:

45. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के भविष्य की दिशा को निर्धारित करने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। हमारी युवा शक्ति के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद जी की ये पक्तियों बहुत ही सटीक हैं-

"युवा वही होता है, जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आँखों में सपने होते हैं।"

युवाओं को असम्भव को सम्भव बनाने के लिए आवश्यक Skills एवं सम्बल देने के लिए हमारी सरकार सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए संकल्पित है। युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण, internship, apprenticeship तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए 'राजस्थान रोजगार नीति-2025 (दो हजार पच्चीस)' लाने की मैं, घोषणा करती हूँ। साथ ही, इसके समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु 500 करोड़ रुपये के विवेकानन्द रोजगार सहायता कोष की स्थापना की भी मैं, घोषणा करती हूँ। इस कोष के माध्यम से-

1. रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं Counselling की व्यवस्था,

2. Internship/ Apprenticeship कार्यक्रमों का संचालन,

3. Employee-Employer Linkage की व्यवस्था,

4. रोजगार शिविरों का आयोजन तथा

5. Examination Centres की स्थापना इत्यादि कार्य किये जा सकेंगे।

46. युवाओं को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से सरकारी विभागों एवं राजकीय उपक्रमों में, आगामी वर्ष एक लाख 25 हजार (एक लाख पच्चीस हजार) पदों पर भर्तियां करने की घोषणा करती हूँ।

इस पर तो ताली बजा देते, युवाओं का मामला है। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए। अभी चार दिन मिलेंगे आपको बोलने के लिये। ....(व्यवधान)....

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): साथ ही, रोजगार मेलों के आयोजन, Campus Interviews तथा नये निवेश में स्थानीय युवाओं के रोजगार को प्रोत्साहन देते हुए निजी क्षेत्र में भी आगामी वर्ष एक लाख 50 हजार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 14 महीनों में सफाई कर्मचारी नहीं लगे आपसे। ....(व्यवधान)....

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। ....(व्यवधान).... बैठे-बैठे नहीं बोलें। आपको तीन दिन बहस के लिये मिलेंगे, तब अपनी चर्चा में बाद में कहना।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 47. युवा अपना उद्यम स्थापित कर अपने परिवार की आजीविका सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य को भी रोजगार के अवसर प्रदान करने में सक्षम हों तथा प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ करने में भी योगदान दें, इस दृष्टि से केन्द्रीय बजट में Scheme for First Time Entrepreneurs घोषित की गई है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के 25 हजार महिला एवं SC/ST उद्यमियों को लाभ दिलवाने के साथ ही, युवाओं हेतु 'विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना' को प्रारम्भ करने की मैं, घोषणा करती हूँ। ....(व्यवधान).... इस योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत Interest Subsidy के साथ ही 5 लाख रुपये तक Margin Money उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। इस योजना हेतु 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

Msk/rtm/19.02.25/1140/1e

48. आज प्रदेश में 5 हजार से अधिक Startups के माध्यम से हमारी नयी पीढ़ी 'Gen Z' अपनी Innovative Approach का उपयोग प्रदेश के विकास में कर रोजगार के अवसर सृजित कर रही है। इन Startups से आज 36 हजार युवा जुड़ चुके हैं। आगामी वर्ष एक हजार 500 नये Startups बनाते हुए 750 से अधिक Startups को i-Start Fund/Fund of Funds के माध्यम से Funding उपलब्ध कराने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही,

प्रदेश के startups को Networking का Platform उपलब्ध कराने की दृष्टि से हैदराबाद, बैंगलुरू, दिल्ली व मुम्बई में i-Start Facilitation Desks स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैडम, अमाउंट कितना है?

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 49. प्रदेश के युवाओं को Future Ready-Industry Ready बनाने हेतु Industry Partners के सहयोग से प्रत्येक संभाग में Centre for Advanced Skilling and Career Counselling की स्थापना करने की घोषणा करती हूं। इसके साथ ही, आगामी वर्ष 50 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, कोटा में Vishwakarma Skill Institute की स्थापना 150 करोड़ रुपये की लागत से की जायेगी।

50. प्रदेश में उच्च, तकनीकी, कृषि एवं स्कूल शिक्षा के विस्तार के लिए नवीन शिक्षण संस्थानों की स्थापना के साथ ही नवीन Trades/Branches/ विषय/संकाय के साथ-साथ सीट क्षमता में वृद्धि तथा संस्थाओं की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 10 देखें)

51. प्रदेश के युवाओं तथा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के साथ ही उद्यमिता तथा नवाचार की भावना जागृत करने की दृष्टि से एक हजार 500 विद्यालयों में Atal Tinkering Labs स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूं। इसके साथ ही, अलवर, अजमेर व बीकानेर में Digital Planetariums तथा भरतपुर, कोटा, अजमेर एवं बीकानेर के Science Centres में Innovation Hubs की स्थापना की जायेगी।

श्री अध्यक्षः ...(व्यवधान)... बैठिये, बैठिये, जवाब में आ जायेगा।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 52. युवाओं को खेल गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित करने एवं खेलों के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की दिशा में खेल मैदान, Gym, Sports School की स्थापना, सुदृढ़ीकरण, ट्रैक निर्माण एवं अन्य मूलभूत सुविधा सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर रख रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 11 देखें)

53. प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से अर्जुन पुरस्कार विजेताओं के समान द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षकों को भी भूमि आवंटित किये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही, तकनीकी शिक्षण संस्थानों में भी Sports Quota लागू किया जाना प्रस्तावित है।

54. नशामुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए नशे का व्यापार करने वालों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने के साथ-साथ समस्त महाविद्यालयों में चरणबद्ध रूप से नई किरण नशा मुक्ति केन्द्र भी प्रारम्भ किये जायेंगे। साथ ही, विद्यार्थियों में पढ़ाई एवं प्रतिस्पर्धा के कारण होने वाले तनाव एवं आत्महत्या की प्रवृत्ति की रोकथाम हेतु कोटा, जोधपुर, जयपुर एवं सीकर में युवा साथी केन्द्र स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य :

55. प्रदेश में जन-जन के लिए 'पहला सुख-निरोगी काया' के ध्येय की पूर्ति करती मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य (MAA) योजना के अन्तर्गत लगभग 35 लाख (पैंतीस लाख) व्यक्तियों को चिकित्सा लाभ प्राप्त हुआ है। आगामी वर्ष इस योजना के साथ ही, आमजन की निःशुल्क जांच एवं दवा हेतु 3 हजार 500 करोड़ (तीन हजार पांच सौ करोड़) रुपये का 'MAA कोष' गठित किये जाने की मैं, घोषणा करती हूं।

MAA योजना के माध्यम से और अधिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष से-

I. Interstate Portability लागू कर प्रदेश के बाहर भी चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): यह सब पहले से हो रहा है। नयी बोतल में पुराना शरबत है।

श्री अध्यक्ष: सुन तो लो। अब बहुत सारी घोषणाएं होंगी। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नयी बोतल में पुराना शरबत है।

श्री अध्यक्ष: सुन तो लो। नहीं, नो।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): II. 70 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजन, हेतु Geriatric Care Packages, किशोरों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य के Packages, Oral Cancer हेतु Package तथा विशेष योग्यजनों हेतु Packages जोड़े जाने प्रस्तावित हैं।

III. इसके साथ ही राजकीय आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से आयुष Package भी योजना में लिये जाने प्रस्तावित करती हूं।

56. यह एक निर्विवाद तथ्य है कि 'Prevention is better than cure'. इसी दृष्टि से हमने वृहद् स्तर पर 'स्वास्थ्य शिविर' लगाकर e-Health Record बनाने का कार्य हाथ में लिया है। अब तक 92 लाख 34 हजार (बानवे लाख चौंतीस हजार) व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। इस कार्य के प्रथम चरण को माह जून, 2025 तक पूर्ण कर आगामी वर्ष-

I. प्रदेश के 70 (सत्तर) वर्ष आयु से अधिक के वृद्धजनों को आवश्यकतानुसार घर पर ही निःशुल्क दवा उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं।

II. राज्य में Type-1 Diabetes से पीड़ित मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से समस्त जिला चिकित्सालयों में Diabetic Clinics स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

III. प्रदेश को TB मुक्त बनाने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्पित है। इस दृष्टि से, प्रत्येक CHC पर Digital X-ray Machine, TRU- NAAT (ट्रू-नॉट) व CB-NAAT (CB-नॉट) Machine की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

IV. HIV संक्रमित संहित अन्य high risk prone महिलाओं की Cervical Cancer की screening की जाकर उपचार किया जायेगा।

V. ट्रक/बस ड्राइवरों तथा कामगार वर्ग यथा-कारीगर, दर्जी, बढ़ई (carpenter), नाई इत्यादि की आंखों की जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध करवाने के लिए MAA नेत्र वाउचर योजना (MAA- NVY) लागू किये जाने की घोषणा करती हूं। इस पर 75 करोड़ (पचहत्तर करोड़) रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): इनको भी चश्म दे दो, साहब।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 57. प्रदेश में Haemodialysis सुविधा का विस्तार करते हुए समस्त जिला चिकित्सालयों में 10 Beds इस हेतु उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूं। इसके साथ ही, विभिन्न गंभीर/असाध्य रोगों के उपचार के लिए Day Care Centres भी समस्त जिला चिकित्सालयों में प्रारम्भ किये जाने प्रस्तावित हैं।

58. प्रदेश में प्राथमिक चिकित्सा सुविधाओं के उन्नयन के लिए नवीन चिकित्सा संस्थानों की स्थापना के साथ ही विभिन्न चिकित्सा संस्थानों के upgradation, भवन निर्माण एवं repair व maintenance तथा आयुष चिकित्सा सुविधा सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 12 देखें)

59. हमारा प्रदेश गंभीर एवं असाध्य रोगों की चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रणी रहे एवं प्रदेशवासियों को समस्त प्रकार की चिकित्सा सुविधा प्रदेश में ही सुलभ हो, इस हेतु 'Tertiary Care System' को सुदृढ़ करने के लिए एक हजार 300 करोड़ (एक हजार तीन सौ करोड़) रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 13 देखें)

60. प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों में भी चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो सके, इस दृष्टि से आगामी वर्ष 750 चिकित्सकों तथा एक हजार 500 पैरा मेडिकल कार्मिकों के पद सृजित किये जाने की घोषणा करती हूं।

MDP/Rtm/19.02.25/1150/1f

61. प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने एवं बेहतर Life Style के लिए प्रेरित करने हेतु 'Fit India' की तर्ज पर 'Fit Rajasthan' अभियान 50 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ आरम्भ करने की मैं, घोषणा करती हूँ। इसके अन्तर्गत विभिन्न Out-door गतिविधियों के संचालन के साथ ही प्रदेशवासियों को अपनी diet में edible oil की मात्रा में न्यूनतम 10 प्रतिशत कमी करने के लिए भी प्रेरित किया जायेगा।

62. प्रदेश में नवीन आयुष नीति लायी जायेगी तथा पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पूर्णतः निरोगी होने पर गांवों को आयुष्मान आदर्श ग्राम घोषित कर 11 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

63. राज्य में खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण के लिए समस्त

जिलों में चरणबद्ध रूप से खाद्य प्रयोगशालायें स्थापित की जायेंगी। आगामी वर्ष, हनुमानगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चित्तौड़गढ़ व डूंगरपुर में खाद्य प्रयोगशालायें स्थापित किया जाना प्रस्तावित हैं।

सड़क सुरक्षा :

64. प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को रोकने की दृष्टि से Delhi-Jaipur, Jaipur-Agra तथा Jaipur-Kota Highways पर सड़क सुधार के कार्य करवाते हुए 'Zero Accident Zones' बनाये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, दुर्घटना संभावित चिह्नित लगभग 50 Black Spots के सुधार के साथ अन्य सड़क सुरक्षा कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

65. राज्य में सडक दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करने हेतु, National/State Highways पर स्थापित 20 Trauma Centres का सुदृढ़ीकरण PPP Mode पर करने हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके साथ ही, 25 Advanced Life Support Ambulances भी उपलब्ध करवायी जायेंगी।

सामाजिक सुरक्षा :

66. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है-

"Reducing disparity is India's priority. Serving the unserved and underserved is an article of faith for us."

अर्थात् "असमानता को कम करना आज भारत की प्राथमिकता है। जरूरतमंदों एवं वंचित वर्गों की सेवा करने में हमारी आस्था है।"

उक्त ध्येय की पूर्ति की दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं/एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर एक हजार 250 (एक हजार दो सौ पचास) रुपये प्रतिमाह करने की मैं, घोषणा करती हूँ।

67. बेघर, वृद्धजन एवं असहाय/निराश्रित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु स्थापित किये जा रहे स्वयंसिद्धा आश्रमों का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष 10 जिलों में 50 बेड क्षमता के आश्रम खोले जाने प्रस्तावित हैं।

68. राज्य में विशेष योग्यजनों को और अधिक सुविधा एवं संबल प्रदान करने की दृष्टि से-

I. एक लाख दिव्यांगजनों को 20 हजार रुपये तक के Artificial Limbs/Equipment उपलब्ध करवाये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस पर 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये का व्यय किया जाना प्रस्तावित हैं।

II. साथ ही, Artificial Limbs/Equipment की गुणवत्ता के सम्बन्ध में Research हेतु 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

69. विमुक्त, घुमंतू और अर्द्ध-घुमंतू समुदायों के सशक्तीकरण एवं उत्थान की दृष्टि से

'दादूदयाल घुमन्तू सशक्तीकरण योजना' प्रारम्भ करने की घोषणा करती हूँ। इस पर 60 करोड़ (साठ करोड़) रुपये का व्यय प्रस्तावित है। इसी के साथ, ऐसे परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने हेतु आगामी वर्ष में 25 हजार (पच्चीस हजार) पट्टे वितरित किया जाना भी प्रस्तावित है।

70. प्रदेश में माटी कला से जुड़े कलाकारों के उत्थान के लिए प्रारम्भ की गयी योजना को और वृहद् रूप देते हुए आगामी वर्ष 2 हजार Electric Wheels (इलेक्ट्रिक चाक) एवं मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवायी जायेंगी।

71. प्रदेश के SC/ST/OBC, EWS, सफाई कर्मचारी, दिव्यांगजन आदि को आर्थिक संबल प्रदान करने की दृष्टि से अनुजा, OBC एवं अल्पसंख्यक निगमों द्वारा दिये गये ऋणों के क्रम में One Time Settlement Scheme (OTSS) लायी जानी प्रस्तावित है।

72. हमारे द्वारा Gig Workers/Online Platform Workers को Social Security प्रदान करने के लिए गठित 'निधि' से आगामी वर्ष इन युवाओं की income में वृद्धि की दृष्टि से Language Certification Courses कराने की सुविधा निःशुल्क दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही, इस निधि का दायरा बढ़ाते हुए Unorganised Sector के अन्य श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा Coverage प्राप्त हो सके, इस हेतु 'Gig and Ünorganised Workers Development Fund' स्थापित कर 350 करोड़ रुपये का प्रावधान करने की मैं, घोषणा करती हूँ।

73. प्रदेश में जरूरतमंद परिवारों तथा वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध करा सम्बल प्रदान करने की दृष्टि से विभिन्न छात्रावास/आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं-

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 14 देखें।)

74. प्रदेश के समस्त राजकीय, अनुदानित, निजी जनसहभागिता योजनान्तर्गत वंचित वर्गों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगों के लिए संचालित आवासीय संस्थानों का मैस भत्ता बढ़ाकर 3 हजार 250 (तीन हजार दो सौ पचास) रुपये प्रति आवासी प्रतिमाह करने की. मैं, घोषणा करती हूँ।

75. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीम राव अम्बेडकर ने कहा था-

"I measure the progress of a community by the degree of progress which women have achieved."

अर्थात् "मैं किसी समुदाय की प्रगति महिलाओं की प्रगति के आधार पर मापता हूँ।"

यह हम सबका, प्रमुख दायित्व है कि, हम अपने प्रदेश में महिलाओं के उत्थान के लिए हर सम्भव प्रयास करें। इसी क्रम में-

I. बालिका गृहों में निवासरत बालिकाओं के 18 (अठारह) वर्ष पूर्ण करने के बाद भी उन्हें hand holding की आवश्यकता होने पर सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से

सभी संभागीय मुख्यालयों पर 50 Bedded सरस्वती Half Way Homes स्थापित किये जाने प्रस्तावित हैं।

II. प्रदेश में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाली बालिकाओं के लिए 10 जिला मुख्यालयों पर Girl Child Care Institutes स्थापित किये जाने प्रस्तावित्त हैं।

III. छात्राओं में आत्मरक्षा एवं स्वाभिमान की भावना जाग्रत करने के लिए 34 (चौंतीस) महाविद्यालयों में स्थापित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रों की सफलता एवं छात्राओं की रुचि को देखते हुए प्रत्येक Block पर एक उच्च माध्यमिक विद्यालय अथवा महाविद्यालय में रानी लक्ष्मी बाई केन्द्र स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूँ।

IV. बालिकाओं को शिक्षा के क्षेत्र में प्रोत्साहन दिये जाने हेतु उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा तथा कालीबाई योजना के अन्तर्गत 35 हजार Scooty वितरित किये जाने की घोषणा करती हूँ।

76. प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण व आजीविका संवर्धन हेतु राजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को लखपति दीदी की श्रेणी में लाये जाने का लक्ष्य बढ़ाकर 20 लाख किये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही-

I. राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कॉपरेटिव सोसायटी लिमिटेड का Non Banking Financial Company/Corporation के रूप में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है। इसके माध्यम से लखपति दीदी की श्रेणी में आने वाली स्वयं सहायता समूह की सदस्यों को, 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक के ऋण उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष 3 लाख लखपति दीदियों को इस योजना से लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

II. SHGs द्वारा बनाये गये उत्पादों की Branding, Packaging में सुधार एवं e-Commerce Platform विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

77. स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती महिलाओं को अन्तिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण Nutri-Kit योजना लागू किये जाने की घोषणा करती हूँ। इससे लगभग 2 लाख 35 हजार (दो लाख पैंतीस हजार) महिलायें लाभान्बित होंगी। इस पर लगभग 25 करोड़ (पच्चीस करोड़) रुपये का व्यय होगा।

78. हमारे द्वारा इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनबाड़ी पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गयी है। आगामी वर्ष से इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। इससे 200 करोड़ रुपये

से अधिक का भार आयेगा।

Ans/rtm 12.00 1g 19.02.2025

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): पिछले साल पैसा नहीं लगा ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे नहीं बोले। ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 79. प्रदेश में खाद्य सुरक्षा का लाभ वास्तविक जरूरतमंद परिवारों को प्राप्त हो सके, इस दृष्टि से 10 लाख नवीन Units NFSA लाभान्वित के रूप में जोड़ा जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार समस्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स को NFSA के अन्तर्गत राशन उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा।

80. अल्प आय वर्ग के परिवारों को भी रोजमर्रा की आवश्यकता का सामान उचित मूल्य पर मिल सके, इस हेतु 5 हजार उचित मूल्य की दुकानों पर 'अन्नपूर्णा भण्डार' खोले जाने प्रस्तावित हैं।

कानून व्यवस्था:

81. प्रदेश को खुशहाली के पथ पर अग्रसर करने के लिए आवश्यक है कि यहाँ कानून व्यवस्था सतत रूप से बनी रहे, आमजन विशेषकर हमारी बहन-बेटियाँ पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करें तथा आज के युग में प्रदेशवासियों को Cyber Crime एवं Organised Crime पर भी प्रभावी अंकुश लगाकर निर्भीक जीवन जीने का ecosystem / वातावरण मिल सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस उद्देश्य से 'SMART Policing' का मंत्र दिया है, जहाँ SMART का अभिप्राय है-

1. **S** for Strategic...
2. **M** for Meticulous
3. **A** for Adaptable
4. **R** for Reliable
5. **T** for Transparent.

इस guiding principle को आत्मसात करते हुए प्रदेश में Surveillance एवं सुरक्षा तंत्र सुदृढ़ करने के लिए मैं, 'राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम' लाने की घोषणा करती हूँ।

82. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में आज राजस्थान की पुनः एकः शान्तिप्रिय प्रदेश के रूप में पहचान हो रही है। इस पहचान को बनाये रखने के लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। संवेदनशील स्थानों पर राज्य स्तरीय अभय कमांड सेन्टर के माध्यम से पुलिस बल की त्वरित पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से 2 वर्षों में एक हजार वाहन उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, आगामी वर्ष 3 हजार 500 (तीन हजार पाँच सौ) नवीन पुलिस पद सृजित किये जाना भी प्रस्तावित है।

83.प्रदेश में कुशल प्रशासनिक व्यवस्था के साथ-साथ मजबूत कानून' व्यवस्था सुनिश्चित करने के दृष्टिगत पुलिस को विभिन्न सुविधायें उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित हैं। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 15 देखें।)

84. दृढ़ निश्चय की प्रतिमूर्ति लौहपुरूष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वें जयंती वर्ष में उनसे प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में अपराध की घटनाओं के सम्बन्ध में त्वरित कार्रवाई एवं प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने की दृष्टि से पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत Sardar Patel Centre for Cyber Control and War-Room की स्थापना 350 करोड़ रुपये व्यय कर किये जाने की घोषणा करती हूँ।

85.अपराधियों के सुधार, पुनर्वास तथा बंदी गृह उन्नयन सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 16 देखें।)

86.प्रदेश में कानून एवं न्यायिक तंत्र के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस थाने, पुलिस' कार्यालय, आधारभूत सुविधायें विकसित करने के साथ ही विभिन्न न्यायालय खोले/क्रमोन्नत किये जायेंगे। इन कार्यों का विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 17 देखें।)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कौन-कौनसे खुले?

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आपने पचास साल में नहीं खोले उतने पांच साल में ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इसका मतलब बजट का आपको पहले से पता है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये, दोनों बैठिये। दोनो विराजिये। इनका भाषण हो जाए, उसके बाद आपको चर्चा में समय मिलेगा।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री):

सुशासन

87. माननीय मुख्यमंत्री, श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सुशासन की अवधारणा को स्थापित करने के लिए दिये गये सूत्र 'P2-G2: Pro Poor Proactive Good Governance' को आधार बनाते हुए प्रदेश के कोने-कोने में प्रशासन की पहुँच सुनिश्चित करने के साथ ही नवीन तकनीक का उपयोग करते हुए विभिन्न विभागों के माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं को अन्तिम छोर पर खड़े व्यक्ति/परिवार तक पहुंचाने का कार्य कर रही है।

माननीय मुख्यमंत्री, श्री भजनलाल शर्मा जी द्वारा 25 दिसम्बर, 2024 को 'सुशासन दिवस' के अवसर पर प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर चरणबद्ध रूप से अटल ज्ञान केन्द्र बनाने की घोषणा की थी। इन ज्ञान केन्द्रों में प्रेरकों द्वारा युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण एवं e-Library की व्यवस्था के साथ-साथ आमजन को विभिन्न विभागों की सेवायें सुलभ करवाने की व्यवस्था की जायेगी। इस क्रम में, आगामी वर्ष प्रथम चरण में 3 हजार से अधिक जनसंख्या वाले पंचायत मुख्यालयों में मैं अटल ज्ञान केन्द्र स्थापित करने की घोषणा करती

हूँ।

88.माननीय प्रधानमंत्री जी ने 26 नवम्बर, 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर सम्पूर्ण देश को महाभारत के श्लोक-

'लोक-रंजनम् एवं अन्न, राज्ञाम् धर्म सनातनः।
सत्यस्य रक्षणम् चैव, व्यवहारस्य यार्जवम्।।'

अर्थात्-"प्रजा/नागरिकों को प्रसन्न रखना; सत्य और सादगी से कार्य करना-यह राज्य/राज का ध्येय होना चाहिये।"

- का स्मरण कराते हुए कहा था कि आधुनिक युग में हमारे देश के संविधान में इन सांस्कृतिक तथा नैतिक मूल्यों का समावेश है। आज संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने पर देश के साथ ही प्रदेश के समावेशी विकास हेतु भी संवैधानिक मूल्यों का महत्व सर्वविदित है। अतः महत्वपूर्ण निर्णयों में संवैधानिक मूल्यों की अनुपालना की दृष्टि से सभी Stakeholders की Capacity Building सुनिश्चित करने हेतु Dr. Bhimrao Ambedkar Law University. जयपुर के अन्तर्गत Ambedkar Institute of Constitutional Studies and Research की स्थापना किये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): इनको अर्थ तो समझाओ। ...(व्यवधान)...

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बार-बार खड़े हो रहे हैं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः यह मेरा काम है, मैं जवाब दूंगा। आप बैठिये। ...(व्यवधान)...

89. माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमारे द्वारा भी दण्ड के स्थान पर न्याय को महत्व देते हुए केन्द्र के जन विश्वास अधिनियम की तर्ज पर राज्य के अधिनियमों को de-criminalise करने तथा redundant प्रावधानों को विलोपित करने की दृष्टि से लोक विश्वास अधिनियम लाया जाना प्रस्तावित है।

90. प्रदेश के विभिन्न विभागों/अधिकारियों की कार्यकुशलता में वृद्धि

हेतु-

I. विभिन्न विभागों के कार्यों को online कर paperless करने के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों को Tablets दिये जायेंगे। इस पर 250 करोड़ (दो सौ पचास करोड़) रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपसे नाराज होकर तीन मंत्री चले गये। एक पहले और दो अब चले गये। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप बैठिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): बार-बार खड़े हो रहे हैं, यह क्या बात हुई ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्षः आप बैठिये। माननीय सदस्य, बैठिये। एक को बिठाता हूं तो दूसरा खड़ा होता है, बैठिये। आपके मंत्री जी बोल रहे हैं। आप बैठिये ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): **II.** विभिन्न विभागों हेतु 450 (चार सौ पचास) नवीन

वाहन उपलब्ध करवाये जाने प्रस्तावित हैं।

91.प्रदेश के कोने-कोने में e-Governance के माध्यम से सरकारी सेवाओं को सुलभ रूप से पहुँचाने की दृष्टि से Digital Infrastructure को और अधिक सुरक्षित एवं सुदृढ़ करने हेतु 400 करोड़ रुपये से नवीनतम तकनीक आधारित RajNET 2.0 स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूँ। RajNET 2.0 के माध्यम से Connectivity की क्षमता में दोगुनी वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, RajNET को Bharat-NET से जोड़ते हुए चरणबद्ध रूप से समस्त प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में Broadband Connectivity उपलब्ध करवायी जायेगी।

VPS-RTM-19.02.2025-12.10-1h

92. विभिन्न विभागों की सेवायें online माध्यम से निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सकें, इस दृष्टि से 500 करोड़ रुपये व्यय कर Disaster Recovery Data Centre, जोधपुर में स्थापित करना प्रस्तावित है।

93. प्रदेश में Frontier Technologies से सम्बन्धित Research and Development के लिए 300 करोड़ रुपये के प्रावधान से Brahmagupta Centre of Frontier Technologies की स्थापना किये जाने की घोषणा करती हूँ।

94. आमजन को समयबद्ध एवं संतोषजनक सेवायें प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयों के coverage के उन्नयन के लिए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की स्थापना व क्रमोन्नयन तथा भवन निर्माण सम्बन्धी कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 18 देखें।)

95. जन समस्याओं का प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में विधायक जनसुनवाई केन्द्र MLALAD योजना के अन्तर्गत 10 लाख रुपये का प्रावधान कर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): काहे की ताली बजा रहे हो? यह हमारा पैसा है। आप अलग से दो। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): आप सुनो तो सही। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: हो गया। ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): इसी क्रम में ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एम.एल.ए. लेड का पैसा हमारा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठे-बैठे न बोलें। माननीय मंत्रीजी। माननीय डोटासराजी। माननीय डोटासराजी। रोहित बौहरा। यह काम मेरा है। ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): इसी क्रम में, माननीय सदस्यगण को कार्य कुशलता

में वृद्धि की दृष्टि से Laptop उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

96. माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ गत सरकार द्वारा मात्र कागजी कार्यवाही करते हुए बिना समुचित विवेचन एवं प्रावधान के नये जिले स्थापित करने जैसे अतार्किक निर्णय लिये गये, वहीं हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजन लालजी के नेतृत्व में आमजन के कल्याण के लिए पूरा विश्लेषण कर तथा संसाधनों की व्यवस्था कर ठोस कदम उठाने में विश्वास रखती है। इसी दृष्टि से नवस्थापित 8 जिलों हेतु समस्त विभागों के जिला स्तरीय कार्यालयों की स्थापना के साथ ही, आवश्यक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री शान्ती धारीवाल (कोटा उत्तर): आठ जिलों को एक हजार करोड़ रुपये से क्या होगा? ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री):

कार्मिक कल्याण :

97. आमजन को विभिन्न सेवायें व सुविधायें उपलब्ध करवाने में सरकारी कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारी सरकार कार्मिक कल्याण एवं उनकी भविष्य की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः सजग है। इसी दृष्टि से कार्मिक कल्याण सम्बन्धी विभिन्न प्रावधान किये जायेंगे। इनका विवरण मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 19 देखें।)

98. हमारे द्वारा अग्निवीरों की देश की सीमा पर दी जा रही चुनौतीपूर्ण सेवा को ध्यान में रखते हुए इनके लिए पुलिस, जेल विभाग तथा वन विभाग की सेवाओं में आरक्षण दिये जाने की व्यवस्था की जा रही है। अब इसी क्रम में अग्निवीरों को Fire Services (अग्निशमन सेवा) में भी आरक्षण दिया जाना प्रस्तावित है।

99. सुशासन में पंचायती राज एवं नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों की महती भूमिका के दृष्टिगत इनके मानदेय में भी आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जानी प्रस्तावित है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): हाथ में दर्द हो जायेगा। ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 100. आमजन में जागरूकता का संचार करने में हमारे पत्रकार साथियों की भूमिका को देखते हुए-

I. पत्रकार कल्याण हेतु देय अधिकतम 1 लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर 3 लाख रुपये तक करने की घोषणा करती हूँ। ...(व्यवधान)...

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): मेरा यह निवेदन है कि पत्रकारों के लिए घोषणा हुई है, अब तो ताली बजा देते। ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): II. साथ ही राज्य सरकार की योजनाओं की समुचित जानकारी पत्रकारों को हो सके इस हेतु चयनित पत्रकार साथियों को क्षेत्र में Exposure Tour की सुविधा उपलब्ध करवाया जाना भी प्रस्तावित है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा के मार्गदर्शन में

हमने अथक प्रयास करते हुए प्रदेश को विकास की नयी ऊँचाइयों पर ले जाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को साकार करने के लिए लौहपुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल से प्रेरणा लेते हुए हम 24×7 कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज मैं, सदन को उनका कथन याद दिलाना चाहूँगी-

"Success comes to those who dare to dream, and work tirelessly to turn those dreams into reality."

अर्थात् "कामयाबी उन लोगों को मिलती है, जो सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए अथक परिश्रम करते हैं।"

कृषि बजट :

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अब ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कृषि मंत्रीजी कहां हैं? ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, व्यवधान न करें। माननीय, व्यवधान नहीं करें। माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य, बैठें। उनको बैठाइये न, आप तो बैठो। बैठिये। बैठिये। बैठिये। आप बैठिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): आपकी अनुमति से अब मैं, सदन के समक्ष कृषि बजट प्रस्तुत कर रही हूँ।

किसी भी देश के लिए कृषि और हमारे अन्नदाता किसान साथियों की महत्ता राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के कथन से स्पष्ट हो जाती है-

"There are people in the world so hungry, that God can not appear to them except in form of bread."

अर्थात् "दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें भूख के कारण भगवान रोटी के रूप में ही दिखायी देते हैं।"

हमारी सरकार ने किसान भाइयों को सम्बल देने व नवीन कृषि तकनीकों के प्रयोग के साथ ही, कृषि उत्पादकता में वृद्धि की दृष्टि से सिंचाई व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में भी ठोस कदम उठाये हैं।

सिंचाई : ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जनवरी में पानी बंद कर दिया। बीकानेर में किसानों को पानी नहीं मिल रहा है। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। माननीय डोटासराजी, I will name you. डोटासराजी, मैं आपका नाम लूंगा। आप बैठें। Don't disturb. तीन दिन आपको बहस के लिए मिलेंगे। आसन पाँवों पर है। आसन पाँवों पर है। बैठिये-बैठिये। आसन पाँवों पर है। बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): किसानों का पानी बंद कर दिया है, आंदोलन हो रहे हैं। ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: बैठिये। बैठिये। माननीय सदस्य, आपको तीन दिन मिलेंगे बहस के लिए, जो

कुछ आपको कहना है, आप उसमें कहना। आपने यह कमिट किया था कि डिस्टर्ब नहीं करेंगे, फिर भी आज बारबार डिस्टर्ब कर रहे हो, यह ठीक नहीं है। बैठिये। बैठिये। बैठिये। माननीय मंत्रीजी को पूरा करने दो। माननीय मंत्रीजी को पूरा करने दो। ...(व्यवधान)...

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): **सिंचाई:**

101. सम्मानित सदन को विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलालजी शर्मा के भागीरथी प्रयासों से प्रारम्भ किये गये पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी राम जल सेतु लिंक परियोजना (संशोधित PKC-ERCP) के कार्य को गति देते हुए 9 हजार 416 करोड़ (नौ हजार चार सौ सोलह करोड़) रुपये के कार्यादेश दिये जा चुके हैं, 12 हजार 64 करोड़ (बारह हजार चौसठ करोड़) रुपये की निविदायें जारी की जा चुकी हैं तथा 12 हजार 807 करोड़ (बारह हजार आठ सौ सात करोड़) रुपये की स्वीकृति जारी की गई है।

इन परियोजनाओं को और वृहद् रूप देते हुए अब मैं, 9 हजार 300 करोड़ (नौ हजार तीन सौ करोड़) रुपये से अधिक की लागत से विभिन्न कार्य करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। इन कार्यों की सूची मैं सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 20 देखें।)

SSY/RTM/19.02.2025/12.20/1j

102. प्रदेश में River Linking, Run off Water Conservation तथा Canal Systems के माध्यम से जल प्रबंधन हेतु Rajasthan Irrigation Water Grid Mission के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए ERCP Corporation का उन्नयन कर Rajasthan Water Grid Corporation स्थापित करने की घोषणा करती हूँ। आगामी वर्ष लगभग 4 हजार करोड़ रुपये के कार्य इस Corporation के माध्यम से हाथ में लिये जायेंगे। इनका विवरण मैं सदन की पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट 21 देखें)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): मैडम, इसका पैसा सिर्फ इसी में देंगी क्या?

श्री अध्यक्ष: नो, बीच में नहीं। बीच में नहीं। 3 दिन मिलेंगे तब बोलना। नहीं तो तब भी आपका नाम बोलने में नहीं रखूंगा। Please don't disturb. चलिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे कार्य हैं इसलिए थोड़ा समय लग रहा है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, नो।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ताली बजाओ।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): 103. कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने हेतु आगामी वर्ष विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से Micro Irrigation के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान करने के साथ-साथ 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में Drip एवं

Sprinkler Irrigation System के लिए अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर एक हजार 250 करोड़ (एक हजार दो सौ पचास करोड़) रुपये का व्यय होना प्रस्तावित है।

104. इसी के साथ, आगामी वर्ष 25 हजार Farm Ponds, 10 हजार डिग्गियों, 50 हजार सौर पम्प संयंत्रों तथा 20 हजार किलोमीटर सिंचाई पाइप लाइन के लिए 900 करोड़ रुपये का अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ। इन योजनाओं के माध्यम से 4 लाख से अधिक किसान साथी लाभान्वित हो सकेंगे।

कृषक कल्याणः

105. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश के विकास में किसान साथियों की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा है-

"हमारे किसान भाई-बहनों पर देश को गर्व है। ये जितना सशक्त होंगे, नया भारत भी उतना ही समृद्ध होगा। मुझे खुशी है कि PM किसान सम्मान निधि और कृषि से जुड़ी अन्य योजनाएं देश के करोड़ों किसानों को नई ताकत दे रही हैं।"

इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के किसानों के हित में PM किसान सम्मान निधि की राशि में वृद्धि की थी। आगामी वर्ष से इस राशि को और बढ़ाकर 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ।

श्री अध्यक्षः बोलिये, बोलिये।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): **106.** इसी के साथ, गेहूँ के Minimum Support Price (MSP) के ऊपर प्रति क्विंटल Bonus राशि को भी बढ़ाकर 150 रुपये की दर से उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ।

कृषि विकासः

107. हमारे देश में प्राचीन काल से ही अन्न उपजाने को अति महत्वपूर्ण माना गया है। ऋग्वेद के मण्डल 4. सूक्त 57 (सत्तावन) के मंत्र 4 में उल्लेख किया गया है-

"खेती करने वाले जन उत्तम हल आदि सामग्री, वृषभ और बीजों को इकट्ठा करके खेतों को उत्तम प्रकार से जोत कर उनमें उत्तम अन्नों को उत्पन्न करें।"

108. प्रदेश में कृषि एवं Horticulture के विकास को सुनिश्चित करने के लिए हमारे द्वारा लागू की गई राजस्थान कृषि विकास योजना (RajKVY) के अन्तर्गत आगामी वर्ष एक हजार 350 करोड़ (एक हजार तीन सौ पचास करोड़) रुपये के कार्य कराने की मैं, घोषणा करती हूँ। इस योजना के माध्यम से कृषि की नई तकनीकों, कृषि आदान, जैविक खेती एवं क्षमता विकास के कार्य करवाये जाने प्रस्तावित हैं। इन कार्यों की सूची मैं, सदन के पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 22 देखें)

109. केन्द्र सरकार द्वारा घोषित प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष राज्य के चयनित जिलों में परियोजनायें लेते हुए RajKVY से convergence हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित करती हूँ।

110. फसलों को नील गाय, जंगली जानवरों व निराश्रित पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाव व रोकथाम के लिए लगभग 75 हजार (पचहत्तर हजार) किसानों को 30 हजार किलोमीटर लम्बाई में तारबन्दी हेतु अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस पर 324 करोड़ (तीन सौ चौबीस करोड़) रुपये का व्यय होगा।

111. आगामी वर्ष 2 हजार कृषकों को उन्नत तकनीक के Green house-Polyhouse/Shednet, Plastic Mulching, Low Tunnel उपलब्ध करवाने के लिए 225 करोड़ (दो सौ पच्चीस करोड़) रुपये का अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

112. राजस्थान, बाजरा (श्रीअन्न) उत्पादन में देशभर में प्रथम स्थान पर है। श्रीअन्न की पोषण क्षमता व उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए-

I. मिड-डे-मील कार्यक्रम तथा माँ-बाड़ी केन्द्रों में Pilot Basis पर श्रीअन्न आधारित उत्पाद Introduce किये जायेंगे।

II. श्रीअन्न के उत्पाद आमजन को आसानी से उपलब्ध करवाने एवं प्रचलन में लाने हेतु प्रत्येक जिले में प्रमुख स्थानों को चिन्हित कर मिलेट्स उत्पाद Outlets खोले जायेंगे।

113. राज्य में नमो ड्रोन दीदी योजना एवं Custom Hiring Centres पर उपलब्ध Drones के माध्यम से आगामी वर्ष एक लाख हेक्टेयर में Nano Urea एवं Nano DAP का छिड़काव करने के लिए 2 हजार 500 (दो हजार पाँच सौ) रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान दिये जाने की मैं घोषणा करती हूँ।

114. भूमिहीन कृषि श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ाने हेतु एक लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 5 हजार रुपये लागत तक के कृषि यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे। इस पर लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

115. किसानों की क्षमता वृद्धि, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकों के उपयोग हेतु प्रेरित करने के उद्देश्य से Knowledge Enhancement Programme के अन्तर्गत आगामी वर्ष Farmer Producer Organizations (FPOs) के 100 सदस्य कृषकों को Israel सहित अन्य देशों में तथा 5 हजार कृषकों को राज्य से बाहर भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, आगामी वर्ष Global Rajasthan Agri-Tech Meet (GRAM) का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है।

कृषि विपणन एवं सहकारिता:

116. जैसा कि माननीय सदस्यगण को विदित है कि कृषकों को और अधिक संबल देने की दृष्टि से माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा Kisan Credit Cards की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गयी है। इसी क्रम में, ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरण के लक्ष्य में वृद्धि करते हुए मैं, आगामी वर्ष 35 लाख (पैंतीस लाख) से अधिक किसान साथियों को 25 हजार करोड़ (पच्चीस हजार करोड़) रुपये के ऋण वितरित किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस हेतु 768 करोड़ (सात सौ अड़सठ करोड़) रुपये ब्याज अनुदान पर व्यय किये जायेंगे।

117. हमारे द्वारा प्रारम्भ की गई Gopal Credit Card योजना के अन्तर्गत आगामी वर्ष संख्या बढ़ाकर 2 लाख 50 हजार (दो लाख पचास हजार) गोपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) रुपये का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है।

118. दीर्घकालीन सहकारी कृषि एवं Non-Farming Sectors हेतु 400 करोड़ रुपये के ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ।

119. वर्ष 2025 UN International Year of Cooperatives के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों को संबल प्रदान करने में ग्राम सेवा सहकारी समितियों (GSS) की भूमिका के दृष्टिगत आगामी 2 वर्षों में शेष रहे 2 हजार 500 से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर GSS स्थापित करने की मैं घोषणा करती हूँ। इस हेतु GSS स्थापना के मापदण्डों में आवश्यकता अनुसार शिथिलन (Relaxation) भी दिया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, नवीन स्थापित 8 जिलों में क्रय-विक्रय सहकारी संघों (KVSS) की स्थापना भी की जानी प्रस्तावित है।

spp/rtm/19.02.2025/12:30/1k

120. प्रदेश में कृषि मण्डियों का विस्तार करने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों/क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में भंडारण क्षमता विकसित करने तथा अन्य आधारभूत सुविधायें विकसित किये जाने की दृष्टि से विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिये परिशिष्ट 23 देखें।)

पशुपालन एवं डेयरी:

121. प्रदेश में पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना' शुरू की गयी है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित है।

122. आगामी वर्ष Sex Sorted Artificial Insemination के लिए प्रथम 2 AI पर 75 (पचहत्तर) प्रतिशत अनुदान के साथ ही शेष 2 AI तक 50 प्रतिशत अनुदान देते हुए 10 लाख पशुपालकों को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

123. वर्तमान में पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या को 138 (एक सौ अड़तीस) से बढ़ाकर 200 किये जाने की घोषणा करती हूँ। इस पर 40 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

124. प्रदेश के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण दूध व Milk Products उपलब्ध करवाने तथा Milk Plants की processing capacity बढ़ाने एवं पशुआहार संयंत्रों का विस्तार करने हेतु 540 करोड़ (पाँच सौ चालीस करोड़) रुपये के कार्य हाथ में लिये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिये परिशिष्ट 24 देखें।)

125. मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत दुग्ध संग्रहण लक्ष्य को बढ़ाकर 13 हजार लाख (तेरह हजार लाख) लीटर किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, एक हजार नवीन सहकारी समितियों/संग्रह केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

126. प्रदेश में संचालित गोशालाओं तथा नंदीशालाओं हेतु प्रति पशु देय अनुदान को आगामी वर्ष 15 प्रतिशत बढ़ाकर 50 रुपये प्रतिदिन किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ। साथ ही, शीत ऋतु में गायों के स्वास्थ्यवर्द्धन की दृष्टि से गोशालाओं को आवश्यकतानुसार अनुदान के स्थान पर बाजरा भी उपलब्ध करवाये जाने का विकल्प दिया जाना प्रस्तावित है।

127. प्रदेश में पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा लाभ उपलब्ध करवाने के लिए पशु चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार करने के साथ-साथ विभिन्न पशु चिकित्सा संस्थान खोले/क्रमोन्नत किये जायेंगे। इनका विवरण मैं सदन पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(विवरण के लिये परिशिष्ट 25 देखें।)

128. पशुपालकों को पशु चिकित्सा व पशुपालन विभाग की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलवाने हेतु 100 पशु चिकित्सा अधिकारियों व एक हजार पशुधन निरीक्षकों की भर्ती की जाने की घोषणा करती हूँ।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट की ऐतिहासिक घोषणाओं को देखते हुये मेरे विपक्ष के साथी एक-एक कर धीरे-धीरे जा रहे हैं। बैंचें खाली हो रही हैं।

श्री अध्यक्ष: बिराजें। ..(व्यवधान).. बिराजों।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): 100 डॉक्टर, 100 पशु चिकित्सक..(व्यवधान)..

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): एक हजार हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): **हरित बजट (Green Budget):**

माननीय अध्यक्ष महोदय,

आपकी अनुमति से सदन के समक्ष प्रदेश का प्रथम 'Green Budget' (हरित बजट) प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है। जैसाकि माननीय सदस्यगण को विदित है, सम्पूर्ण विश्व एवं देश के साथ ही प्रदेश को भी वर्ष 2030 तक Sustainable Development Goals का लक्ष्य प्राप्त करना है। Green Growth के महत्व एवं आवश्यकता का उल्लेख करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने कहा है-

"For us, protection of environment is an article of faith. We have natural resources because our previous generations protected these resources. We must do the same for our future generations.

We have to move towards 'Zero Defect and Zero Effect'. Zero defect in production with no adverse effect on the environment."

129. माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में सभी विभागों

में Sustainable Green प्रणाली को प्रोत्साहित करने के साथ ही 10 बिन्दुओं पर विशेष focus देने का विनिश्चय किया है, जो इस प्रकार हैं-

1. Climate Change Adaptation
2. Forest and Environment - Biodiversity/ Ecology
3. Sustainable Agriculture, Water Harvesting/Recharge
4. Sustainable land use
5. Green Energy
6. Recycling and Waste Disposal - Circular Economy
7. Clean Tech Development
8. Green Audit
9. Capacity Building-Education, Skilling
10. Green Funding

माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि वर्ष 2025-26 हेतु विभिन्न क्षेत्रों में Green Budget के अंतर्गत 27 हजार 854 करोड़ (सत्ताइस हजार आठ सौ चौवन करोड़) रुपये का प्रावधान रखा गया है, जो कि कुल Scheme Expenditure का 11.34 प्रतिशत है। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तावित किये गये विभिन्न विभागों के कार्यों में Green Growth से सम्बन्धित बिन्दुओं का समावेश किया गया है, जैसे-Renewable Energy, Sustainable Agriculture, Circular Economy-Waste Management & Recycling, E-Vehicles इत्यादि। इनके साथ ही विशेष Green Initiatives (Key Green Initiatives-KGIs) अब मैं, माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ-

1. **Climate Change Adaptation:**

I. यद्यपि Inter Govermental Panel on Climate Change (IPCC) ने पर्यावरण में वर्ष 2050 तक समुचित सुधार की अपेक्षा की है तथापि हमें माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ किये गये 'Mission LIFE' से प्रेरणा लेते हुए, इस बदलते Climatic Scenario के अनुरूप परिवेश तथा जीवनशैली को ढालना होगा। प्रदेश में कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, Desert Ecosystem एवं Land Management, ऊर्जा एवं जल के उपयोग, स्वास्थ्य, पशुपालन तथा नागरिक सुविधाओं के सम्बन्ध में कार्यप्रणाली, तकनीक एवं इनके उपयोग की पद्धति में परिवर्तन की दृष्टि से मैं, 5 वर्षीय Climate Change Adaptation Plan-2030 बनाये जाने की घोषणा करती हूँ।

II. इसके साथ ही. 150 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence for Climate Change स्थापित किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

Forest and Environment - Biodiversity/ Ecology:

I. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारम्भ किये 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान से प्रेरणा लेकर इस वर्ष प्रदेश में 7 करोड़ से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। आगामी वर्ष, मिशन हरियाळो राजस्थान के अन्तर्गत 10 करोड़ पौधे लगाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

II. समस्त कृषकों एवं अन्य Stakeholders को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने तथा वन क्षेत्र के बाहर Green Cover को बढ़ाये जाने की दृष्टि से Tree Outside Forest (ToFR) Policy तथा Agro-Forestry Policy लायी जानी प्रस्तावित करती हूँ।

III. वन एवं वन्य जीव संरक्षण की कार्ययोजना का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कार्य कराये जायेंगे। इन कार्यों की सूची मैं सदन पटल पर प्रस्तुत कर रही हूं।

(सूची के लिये परिशिष्ट 26 देखें।)

3. **Sustainable Agriculture, Water Harvesting/Recharge:**

1. Chemical Fertilizers एवं पौध संरक्षण रसायनों के दुष्प्रभाव से स्वास्थ्य पर पड़ रहे विपरीत प्रभाव की रोकथाम के लिए-

(a) National Natural Farming Mission के अन्तर्गत कृषकों को दिये जा रहे सम्बल में वृद्धि करते हुए आगामी वर्ष 2 लाख 50 हजार किसानों को अनुदान दिये जाने की घोषणा करती हूँ। इसके साथ ही, Organic Farming के लिए एक लाख ...

jyg/rtm/19.02.25/12.40/1l

कृषकों तथा Bio-Agents एवं Bio-Pesticides के लिए 2 लाख किसानों को लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है।

(b) प्रदेश में लघु एवं सीमान्त कृषकों को बैलों से खेती करवाये जाने पर प्रोत्साहन राशि के रूप में 30 हजार रुपये प्रतिवर्ष दिये जाने की घोषणा करती हूँ। साथ ही, ऐसे किसान साथियों को गोबर गैस प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी भी दी जानी प्रस्तावित है।

(c) जैविक खेती उत्पादकों को उनके उत्पाद के विक्रय हेतु कृषि उपज मण्डियों में दुकान/भूखण्ड का आवंटन करने की नीति लायी जायेगी।

II. हमारे द्वारा शुरू किये गये मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान 2.0 के अन्तर्गत आगामी वर्ष 4 हजार 700 से अधिक गांवों में Water Harvesting Structures के एक लाख 10 हजार कार्य करवाये जाने की घोषणा करती हूँ। इन पर 2 हजार 700 करोड़ (दो हजार सात सौ करोड़) रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

4. Sustainable land use:

I. विकसित राजस्थान @2047 हेतु GIS आधारित Green Land Use Perspective Plan बनाये जाने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित करती हूँ।

II. महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत भूमि विकास के कार्यों यथा-चरागाह विकास, नदी तट स्थिरीकरण एवं पहाड़ी क्षेत्रों के संरक्षण हेतु 500 करोड़ रुपये की राशि व्यय की जानी प्रस्तावित है।

III. राज्य के शहरी क्षेत्रों में Green Lungs के विकास तथा Noise Pollution के mitigation हेतु Zones का identification एवं planning कर आवश्यक सुधार हेतु

आगामी वर्ष 45 करोड (पैंतालीस करोड़) रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं।

5. Green Energy:

I. राज्य में अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में सतत् वृद्धि को सुनिश्चित करने के साथ ही 'सौर उपकरणों के निरन्तर बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए सोलर दीदी के रूप में नवीन मानदेय कैडर बनाया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में, आगामी वर्ष स्वयं सहायता समूह की 25 हजार (पच्चीस हजार) महिलाओं को सोलर दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जायेगा।

II. प्रदेश के समस्त राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के के साथ ही, अब PHED (Public Health Engineering Department) के Pumping Stations को भी Hybrid Annuity Model (HAM) पर सौर ऊर्जा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

III. राज्य में Clean Cooking को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आगामी वर्ष एक लाख लाभार्थियों को निःशुल्क Induction Cook Top-Cooking System वितरित किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

6. Recycling and Waste Disposal - Circular Economy:

I. Circular Economy के व्यापक प्रसार के लिए Rajasthan Circular Economy Incentive Scheme-2025 लायी जाने की घोषणा करती हूँ। इस Scheme के माध्यम से-

(a) Recycling/Reuse के क्षेत्र में R&D के लिए 2 करोड रुपये तक अनुदान दिया जायेगा।

(b) Circular Economy के क्षेत्र में कार्यरत MSMEs तथा Startups को विभिन्न योजनाओं में. दिये जा रहे ऋण अनुदान में 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जायेगी।

II. प्रदेश में 15 वर्ष से पुराने वाहनों का उपयोग निषिद्ध करने तथा नयी Technology के प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु Rajasthan Vehicle Scrap Policy लाया जाना प्रस्तावित है।

III. Waste Re-use और Recycle Concepts को प्रदर्शित करने, Circular Economy के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समस्त जिला मुख्यालयों पर Waste to Wealth Parks (Circularity Parks) स्थापित किये जायेंगे।

IV. ग्रामीण क्षेत्रों में भी आज Plastic के उपयोग से पर्यावरण के लिए चुनौती खड़ी हो गयी है। इस समस्या को देखते हुए ग्राम पंचायतों पर Steel के बर्तन उपलब्ध करवाते हुए 'बर्तन बैंक' बनाया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु प्रथम चरण में एक हजार पंचायतों को एक-एक लाख रुपये के बर्तन उपलब्ध करवाये जायेंगे।

7. Clean Tech Development:

I. माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित विषयों में तकनीकी दक्षता बढ़ाने हेतु 250 करोड़ (दो सौ पचास करोड़) रुपये की राशि से Clean and Green Technology Development Centre स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूँ।

II. केन्द्र की Smart City योजना की तर्ज पर बूंदी, नाथद्वारा, खाटूश्यामजी, माउंट आबू, बालोतरा, भरतपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, किशनगढ़, भिवाडी, भीलवाड़ा, मंडावा, पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को 900 करोड़ रुपये का कोष गठित कर आगामी 3 वर्षों में Clean and Green- Eco Cities के रूप में विकसित किये जाने की मैं, घोषणा करती हूँ।

8. Green Audit:

I. प्रदेश को 'हरित राजस्थान' बनाये रखने हेतु सतत् प्रगति हो, इस हेतु आगामी वर्ष सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में विषय विशेषज्ञों के माध्यम से 'Green Audit' कराने के लिए 35 करोड़ (पैंतीस करोड़) रुपये का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ।

9. Capacity Building-Education, Skilling :

I. राज्य में सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) के Implementation में आने वाली कमियों की पहचान करने तथा सतत् विकास लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक त्वरित गति से प्राप्त करने के लिए Sustainable Development Goals Coordination and Acceleration Centre (SDGCAC) स्थापित किया जायेगा।

II. हमारी नयी पीढ़ी Sustainable Development तथा Green Growth के सिद्धान्तों को आत्मसात् कर आवश्यक Skills प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से स्कूल शिक्षा में आवश्यक प्रावधान करने के साथ ही, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में नये विषय प्रारम्भ करते हुए Certification Courses भी उपलब्ध करवाये जाने के लिए 40 करोड़ (चालीस करोड़) रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

10. **Green Funding:**

I. स्थानीय निकायों तथा निवेशकों को Green Growth सम्बन्धी परियोजनाओं एवं गतिविधियों के क्रम में अतिरिक्त प्रोत्साहन उपलब्ध करवाने के लिए Carbon Credit की तर्ज पर Rajasthan Green Credit Mechanism विकसित कर Tradable Credits उपलब्ध करवाये जाने प्रस्तावित करती हूँ। साथ ही, राजकीय परियोजनाओं के लिए Green Funds एवं Instruments को leverage भी किया जायेगा।

II. प्रदेश में प्रचलित विभिन्न सामयिक मुद्दों के सम्बन्ध में Sustainable एवं Environment Friendly समाधान ढूंढने की दृष्टि से 100 करोड़ रुपये का Rajasthan Green Challenge Fund स्थापित करने की घोषणा करती हूँ।

130. माननीय सदस्य, प्राचीन पर्वतमाला 'अरावली पर्वत श्रृंखला' के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक महत्व से भली-भांति परिचित हैं। इस पर्वत श्रृंखला का हमारे देश को बरसों से आक्रमणकारियों से बचाने के साथ-साथ Desertification के प्रसार की रोकथाम तथा Bio-diversity के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान है। अरावली पर्वतमाला के संरक्षण व इसे हरित बनाये रखने के उद्देश्य से मैं, 250 करोड़ रुपये राशि की 'हरित अरावली विकास परियोजना' शुरू करने की घोषणा करती हूँ। इस परियोजना के तहत Bio-diversity को बनाये रखने के लिए वृक्षारोपण, छोटे Check Dams का निर्माण तथा स्थानीय Medicinal Plants के

विकास सम्बन्धी विभिन्न कार्य करवाये जायेंगे।

131. अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के कुशल नेतृत्व में अल्प समय में ही जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए, जनकल्याण की भावना से, हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। आगे भी हम प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए अथक प्रयास करते रहेंगे। यहाँ पर मैं, प्रसिद्ध कवि श्री गोपालदास 'नीरज' जी की पंक्तियाँ याद करना चाहूँगी-

"हैं फूल रोक़ते, काँटें मुझे चलाते,
मरूस्थल, पहाड़ चलने की चाह बढ़ाते।
सच कहता हूँ, जब मुश्किलें नहीं होती हैं,
मेरे पग तब चलने में भी शर्माते ।

मेरे संग चलने लगें हवाएँ जिससे,
तुम पथ के कण-कण को तूफान करो।
मैं तूफानों में चलने का आदी हूँ,
तुम मत मेरी मंजिल आसान करो।।"

कर-प्रस्ताव

132. माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से अब मैं कर-प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।

133. हमारी सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में किये गये संरचनात्मक सुधारों (Structural Reforms), निवेश प्रोत्साहन के लिए आवश्यक नीतिगत परिवेश बनाने, Tax Evasion को रोकने हेतु किये गये प्रयासों तथा Stamps Act के अन्तर्गतं Rate rationalisation से जहाँ एक ओर प्रदेश की Own Tax Revenue में 26 हजार 393 करोड (छब्बीस हजार तीन सौ तिरानवे करोड़) रुपये की वृद्धि अपेक्षित है, वहीं दूसरी ओर आमजन एवं व्यवसायियों को राहत देने के लिए भी हमारे द्वारा विभिन्न कदम उठाते हुए -

I. डीजल तथा पेट्रोल के मूल्य में 6 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर तक की राहत दी गई। इस सकारात्मक कदम से राज्य में पेट्रोल एवं डीजल के उपभोग में भी राष्ट्रीय औसत से क्रमशः 1.24 तथा 2.55 प्रतिशत अधिक वृद्धि दर्ज हुई।

II. VAT समय के पुराने लम्बित मामलों पर दी गई एमनेस्टी से लगभग 18 हजार व्यवहारियों को 2 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राहत प्रदान की गई।

III. अल्प एवं मध्यम आय वर्ग के 13 हजार से अधिक व्यक्तियों को स्टाम्प ड्यूटी में 75 करोड़ रुपये से अधिक की राहत दी गई।

MLS/RTM/19.02.2025/12:50/1m

134. माननीय सदस्यों को मैं महाभारत के शान्तिपर्व का श्लोक याद दिलाना चाहूंगी जहां भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को शिक्षा देते हुए कहते हैं-

'राजा को चाहिये कि परिस्थति और समय के प्रतिकूल प्रजा पर कर का बोझ न डाले। समय के अनुसार प्रजा को समझाकर उचित रीति से कर वसूल करे।'

135. हमारी सरकार का प्रारम्भ से ही प्रयास है कि कर प्रबन्धन नीति राज्य की अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, समग्र विकास एवं जनकल्याण की दृष्टि से निर्धारित हो। हम भविष्य में भी इसी रीति से कार्य करने के लिये कटिबद्ध हैं।

136. आगामी वर्ष भी हम आमजन एवं निवेशकों को राहत देने के लिये विभिन्न Amnesty योजनाएं लायेंगे। इस क्रम में -

I. वर्ष 2017 के समय VAT से हटायी गयी Commodities के लिये VAT Amnesty लाते हुए 50 लाख रुपये तक की Demand को माफ करने की घोषणा करती हूं। साथ ही इससे अधिक बकाया होने पर ब्याज एवं पैनल्टी पर शत-प्रतिशत छूट दी जानी प्रस्तावित है।

II. खनन उद्योग के सम्बन्ध में निरस्त खनिज Concessions के साथ ही प्रभावी खनिज Concessions के लिये भी एमनेस्टी स्कीम लाया जाना प्रस्तावित करती हूं।

III. साथ ही 'ई-रवन्ना' सम्बन्धी Overloading के प्रकरणों में Compounding राशि में 95 प्रतिशत तक कमी किये जाने की घोषणा करती हूं।"

IV. Stamp Act तथा Excise Act के अन्तर्गत वर्ष 2020 तक के प्रकरणों में Demand राशि 30 सितम्बर, 2025 तक जमा कराये जाने पर शत-प्रतिशत ब्याज एवं Penalty की छूट तथा वर्ष 2020 से 2022 तक के प्रकरणों में शत-प्रतिशत Penalty एवं 50 प्रतिशत ब्याज की छूट दिये जाने की घोषणा करती हूं।

V. Motor Vehicle Act के अन्तर्गत नष्ट हो चुके वाहनों पर नष्ट होने की दिनांक के बाद के समस्त कर देय पैनल्टी और ब्याज पर 30 सितम्बर, 2025 तक शत-प्रतिशत छूट प्रदान किये जाने की घोषणा करती हूं।

VI. हमारे द्वारा Rajasthan Logistics Policy-2025 लायी जाकर Warehouses को Industry का दर्जा दिया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 1 फरवरी, 2025 से पूर्व औद्योगिक क्षेत्रों में निर्मित Warehouses को Regularize किया जाना प्रस्तावित है।

VII. नगरीय क्षेत्रों में स्थित भूखण्ड एवं भवनों की 31 मार्च, 2024 तक की बकाया लीज राशि 30 सितम्बर, 2025 तक एकमुश्त जमा करायी जाने पर देय ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है।

निवेश :

137. प्रदेश को वर्ष 2030 तक $ 350 Billion economy बनाने के लक्ष्य की ओर ठोस कदम बढ़ाते हुए हमारे द्वारा 'Rising Rajasthan' के माध्यम से राजस्थान को Attractive Investment Destination के रूप में स्थापित कर प्रदेश के तीव्र विकास की

आधारशिला रखी गयी है। प्रदेश को और अधिक Competitive बनाने की दृष्टि से -

1. Rajasthan Investment Promotion Scheme (RIPS) - 2024 के अन्तर्गत-

I. केन्द्र सरकार द्वारा MSME इकाइयों की नई वृहद् परिभाषा के अनुरूप RIPS-2024 के अन्तर्गत लाभ दिये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही बड़े निवेशकों के अनुरूप ही MSME इकाइयों को RIPS-2024 के अन्तर्गत Expansion हेतु निर्धारित लाभ दिये जाने की भी घोषणा करती हूं।

II. RIPS-2022 के साथ ही RIPS-2019 के अन्तर्गत लाभान्वित इकाइयों को पात्र होने की स्थिति में शेष अवधि हेतु RIPS-2024 के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के सम्बन्ध में Transition के लिये अनुमत किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

2. RIPS-2024 के साथ ही RIPS-2022 के अन्तर्गत Turnover Linked Incentives हेतु Turnover की परिभाषा में किसी संस्थान द्वारा अपने Extended Arm (Subsidiaries इत्यादि) के साथ किये गये व्यवहार को अनुमत किया जाना प्रस्तावित है।

3. RIPS अथवा उद्यम प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत किसी कम्पनी के Director अथवा उसके परिवार के सदस्य के अन्य कम्पनी में भी Director होने से ऐसी द्वितीय कम्पनी को योजनाओं का लाभ लेने के लिये अपात्र नहीं माना जाना प्रस्तावित है।

4. Agro Processing Scheme-2019 के समय के कुछ प्रस्ताव अभी भी लम्बित हैं। ऐसे लम्बित प्रस्तावों को निस्तारित कर उक्त योजनान्तर्गत लाभ प्रदान किये जाने की घोषणा करती हूं।

5. खनन पट्टाधारकों के लिए -

I. क्वारी लाइसेंस हेतु देय फीस को 5,000 रुपये से घटाकर 3,000 रुपये करने की घोषणा करती हूं।

II. खानों के बाहर राजकीय भूमि में एकत्रित Overburden से M-Sand बनाने पर रॉयल्टी में छूट दी गयी है। अब मैं गैर सरकारी भूमि के सम्बन्ध में भी Overburden Dumps के M-Sand सहित अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग पर रॉयल्टी में 50 प्रतिशत की छूट प्रस्तावित करती हूं।

138. आगामी वर्ष में अप्रधान खनिजों के 50 प्लॉटों की नीलामी Pre-embedded Clearance के साथ की जानी प्रस्तावित है। इससे नीलामी में अधिक राजस्व प्राप्त होगा और खनिजों का उत्पादन भी अविलम्ब प्रारम्भ हो सकेगा।

आम आदमी को राहत :

139. परिवार के सदस्यों के पक्ष में पावर ऑफ़ अटॉर्नी पर स्टाम्प ड्यूटी में उपलब्ध छूट का लाभ माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, पति, पत्नी के साथ-साथ पुत्रवधू, नाती और नातिन को भी दिये जाने की घोषणा करती हूं।

140. भूमि अवाप्ति पर भूस्वामी को आवण्टित विकसित भूमि के दस्तावेज पर स्टाम्प ड्यूटी में प्रदान की जा रही छूट को राज्य सरकार के समस्त विभागों तथा राजकीय उपक्रमों

पर लागू किया जाना प्रस्तावित है।

141. उद्योगों एवं सम्पत्ति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से पत्नी के साथ संयुक्त नाम से क्रय की गयी 50 लाख तक की सम्पत्ति पर स्टाम्प ड्यूटी में 0.5 प्रतिशत की छूट दिये जाने की घोषणा करती हूं।

142. गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के सम्बन्ध में गोपालकों को और अधिक राहत देते हुए गोपाल क्रेडिट कार्ड के लिये जरूरी सभी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ करना तथा योजना के प्रावधानों को सरल किया जाना प्रस्तावित करती हूं।

Ease of Doing Business:

143. GST, VAT, MV Act, Stamps Act आदि सभी Taxation सम्बन्धी प्रकरणों में Video Conferencing के माध्यम से सुनवाई की सुविधा उपलब्ध कराये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही मुख्यालय स्तर से की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला स्तर पर Facilitation Desks के माध्यम से Document submission एवं Verification की सुविधा भी प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।

144. GST एवं VAT के अन्तर्गत बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर पंजीकरण हेतु आवेदन करने पर 7 दिवस में पंजीकरण सुनिश्चित करने की गारंटी दिया जाना प्रस्तावित है।

145. हमारे द्वारा लाये जा रहे Rajasthan Value Added Tax Bill, 2025 के अन्तर्गत Ease of Doing Business के उद्देश्य से -

I. मैं, First Point Taxation की प्रक्रिया निर्धारित करना प्रस्तावित करती हूं।

mkd/rtm/07.02.2025/13:00/1n

II. साथ ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा के अनुरूप जनविश्वास Act की तर्ज पर इस Act के प्रावधानों के उल्लंघन को De-criminalise भी किया जा रहा है।

III. अब 40 लाख रुपये तक टर्नओवर वाले व्यवसायियों को पंजीयन कराने की बाध्यता नहीं होगी तथा पंजीयन हेतु Security के प्रावधान को भी समाप्त किया जा रहा है।

IV. प्रतिवर्ष कर निर्धारण आदेश की अनिवार्यता समाप्त कर स्वःकर निर्धारण (Self Assessment) व्यवस्था लागू की जा रही है।

V. नवीन Act के प्रावधानों के अनुरूप अपील करने पर स्वतः ही स्थगन प्राप्त हो जायेगा।

146. MV Act के अन्तर्गत वाहन निर्माताओं को भी वाहनों के पंजीयन की शक्तियां दिया जाना प्रस्तावित है।

147. राज्य से बाहर ले जाये जा चुके और नष्ट हो चुके वाहनों के एकबारीय कर के रिफण्ड हेतु आवेदन की निर्धारित समयावधि को 6 माह से बढ़ाकर 2 वर्ष किये जाने की घोषणा करती हूं।

148. अन्य राज्यों से राजस्थान राज्य में लाये गये वाहनों के One Time Tax की

गणना Portal के माध्यम से करने तथा पंजीकरण की व्यवस्था को पूर्णतया ऑनलाइन करने की घोषणा करती हूं।

149. बहुमंजिला भवनों तथा रेरा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स में सम्पत्तियों के पंजीयन हेतु बार-बार मौका निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त करने की दृष्टि से प्रोजेक्ट के Approved Lay Out Plan के आधार पर Evaluation की सुविधा उपलब्ध कराई जानी प्रस्तावित करती हूं।

150. Fire NOC प्राप्त करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करने के साथ ही Fire NOC की न्यूनतम वैधता अवधि 2 वर्ष निर्धारित की जायेगी।

151. महिला सशक्तिकरण को बल देते हुए वाणिज्यिक एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिलाओं के लिए निर्धारित कार्य अवधि के सम्बन्ध में लगाये गये प्रतिबन्ध को पूर्णतया समाप्त करने की घोषणा करती हूं। साथ ही The Rajasthan Shops and Commercial Establishments Act, 1958 को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित करने हेतु नया अधिनियम लाया जाना भी प्रस्तावित है।

श्री टीकाराम जूली (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री जी सो रहे हैं।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री):

Green Growth:

152. हमारी सरकार का ध्येय औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन रखते हुए राज्य की विकास दर को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। इस लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाते हुए Green Growth Credit Policy लाये जाने की घोषणा करती हूं। इस पॉलिसी के तहत नये निवेशकों के साथ-साथ पहले से स्थापित उद्योगों को Ecomark आधारित Green Technology/Goods के उपयोग/उत्पादन पर Interest Subvention, Stamp Duty & Electricity Duty Exemption, TDR (Transferable Development Rights) तथा Startup Funds आदि के रूप में छूट दी जानी प्रस्तावित है।

संस्थागत सुदृढ़ीकरण:

153. राज्य में वर्तमान में पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर 10 मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय सफलतापूर्वक संचालित किये जा रहे हैं। आगामी वर्ष 50 अतिरिक्त उप-पंजीयक कार्यालयों का मॉडल उप-पंजीयक कार्यालय के रूप में उन्नयन करने की घोषणा करती हूं।

154. प्रदेश की अर्थव्यवस्था में खनिजों के महत्व के दृष्टिगत Research and Development, Interpretation एवं Capacity Building हेतु 60 करोड़ रुपये की लागत से जयपुर में Centre of Excellence for Mines and Minerals स्थापित किये जाने की घोषणा करती हूं। साथ ही उदयपुर में Institute of Mines तथा जोधपुर स्थित MBM University में Petro Campus स्थापित किये जाने भी प्रस्तावित हैं।

155. उद्योगों में गैस के प्रयोग को प्रोत्साहित करने तथा आम आदमी तक पाइपलाइन के माध्यम से इसकी पहुंच सुनिश्चित करने की दृष्टि से राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन

पॉलिसी, 2025 लाया जाना प्रस्तावित करती हूं। साथ ही आगामी वर्ष में 1 लाख 25 हजार घरों को Piped Gas Supply से जोड़ा जायेगा।

156. हमने कर संग्रहण में Efficiency एवं Transparency लाने की दृष्टि से वाणिज्यिक कर विभाग, आबकारी विभाग तथा परिवहन विभाग में Faceless Management की व्यवस्था तथा विभागों के पुनर्गठन करने का कार्य प्रारम्भ किया है। आगामी वर्ष खनन विभाग में भी इसी अनुरूप व्यवस्था की जानी प्रस्तावित है।

157. खनिजों की खोज एवं अन्वेषण हेतु राज्य सरकार के उपक्रम RSMML की सहायक कम्पनी के रूप में 'Rajasthan Mineral Exploration Limited' के गठन की घोषणा करती हूं।

Additional Resource Mobilization (A.R.M.):

158. मुझे माननीय सदस्यों को अवगत कराते हुए अत्यन्त हर्ष का अनुभव हो रहा है कि पचपदरा बालोतरा स्थित 'HPCL. Rajasthan Refinery Limited' का निर्माण अन्तिम चरण में है, जो माह अगस्त, 2025 से चरणबद्ध रूप से उत्पादन प्रारम्भ कर देगी। इसके फलस्वरूप बाड़मेर-बालोतरा क्षेत्र में विकास एवं रोजगार के अवसरों का सृजन तो हो ही रहा है, साथ ही आगामी वर्ष Petroleum उत्पादों पर VAT के रूप में लगभग 2 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व (A.R.M.) भी प्राप्त होगा।

साथ ही, Land Pooling, Land Aggregation, InvITs के माध्यम से Asset Monetization किया जाना भी प्रस्तावित है। इस प्रकार 4 हजार 750 करोड़ रुपये का A.R.M. सम्भावित है।

159. इन कर-प्रस्तावों के अतिरिक्त कुछ अधिनियमों के प्रावधानों में भी संशोधन (Amendments) प्रस्तावित है। इन संशोधनों के सम्बन्ध में विस्तृत उद्देश्य और प्रयोजन वित्त विधेयक में वर्णित हैं।

160. इन प्रस्तुत कर-प्रस्तावों और घोषणाओं की क्रियान्विति के लिये तथा अन्य प्रयोजनार्थ इनके साथ कुछ अधिसूचनाएं जारी की जा रही हैं।

अब मैं माननीय सदन में वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान एवं बजट अनुमान 2025-26 प्रस्तुत कर रही हूं-

161. वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों का विवरण इस प्रकार है-

1.	राजस्व प्राप्तियां 2 लाख 62 हजार 618 करोड़ 28 लाख रुपये (दो लाख बासठ हजार छः सौ अठारह करोड़ अट्ठाईस लाख रुपये)
2.	राजस्व व्यय 2 लाख 94 हजार 557 करोड़ 43 लाख रुपये (दो लाख चौरानवे हजार पांच सौ सत्तावन करोड़ तियालीस लाख रुपये)
3.	राजस्व घाटा 31 हजार 939 करोड़ 15 लाख रुपये (इकतीस हजार नौ सौ उन्तालीस करोड़ पन्द्रह लाख रुपये)
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां 2 लाख 36 हजार 335 करोड़ 87 लाख रुपये

	(दो लाख छत्तीस हजार तीन सौ पैंतीस करोड़ सत्तासी लाख रुपये)
5.	पूंजी खाते में व्यय 2 लाख 4 हजार 289 करोड़ 79 लाख रुपये (दो लाख चार हजार दो सौ नवासी करोड़ उन्यासी लाख रुपये)
6.	राजकोषीय घाटा 70 हजार 90 करोड़ 84 लाख रुपये (सत्तर हजार नब्बे करोड़ चौरासी लाख रुपये)

162. वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमानों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-

1.	राजस्व प्राप्तियां 2 लाख 94 हजार 536 करोड़ 49 लाख रुपये (दो लाख चौरानवे हजार पांच सौ छत्तीस करोड़ उन्चास लाख रुपये)
2.	राजस्व व्यय 3 लाख 25 हजार 545 करोड़ 90 लाख रुपये (तीन लाख पच्चीस हजार पांच सौ पैंतालीस करोड़ नब्बे लाख रुपये)
3.	राजस्व घाटा 31 हजार 9 करोड़ 41 लाख रुपये (इकतीस हजार नौ करोड़ इकतालीस लाख रुपये)
4.	पूंजी खाते में प्राप्तियां 2 लाख 42 हजार 647 करोड़ 54 लाख रुपये (दो लाख बयालीस हजार छः सौ सैंतालीस करोड़ चौवन लाख रुपये)
5.	पूंजी खाते में व्यय 2 लाख 11 हजार 523 करोड़ 4 लाख रुपये (दो लाख ग्यारह हजार पांच सौ तेईस करोड़ चार लाख रुपये)
6.	राजकोषीय घाटा 84 हजार 643 करोड़ 63 लाख रुपये (चौरासी हजार छः सौ तियालीस करोड़ तिरेसठ लाख रुपये)

163. विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन (Prudent Fiscal Management) एवं राजकोषीय समेकन (Fiscal Consolidation)

I. हमारे द्वारा राज्य में व्यापक स्तर पर Economic Development हेतु Fiscal Macro Consolidation का विस्तृत Road-map प्रस्तुत किया गया है, जिसके लिए हमने Fiscal Parameters को अनुमत सीमा में रखते हुए समुचित संसाधनों (Resources) की व्यवस्था की है। बजट अनुमान 2025-26 में राज्य के राजकोषीय मानकों (Fiscal Parameters) का विवरण निम्न प्रकार है-

मानक	बजट अनुमान	विशेष विवरण
राज्य सकल घरेलू उत्पाद (GSDP)	19 लाख 89 हजार 835 करोड़ रुपये (उन्नीस लाख नवासी हजार आठ सौ पैंतीस करोड़ रुपये)	वर्ष 2025-26 में GSDP की वृद्धि दर इस वर्ष की तुलना में 16.75% (सोलह. सात पांच प्रतिशत) है जिसकी गणना 15वें वित्त आयोग के फॉर्मूले के अनुसार की गई

		है।
राजकोषीय घाटा (GSDP के प्रतिशत के रूप में)	4.25% (चार. दो पाँच प्रतिशत)	अनुमत FRBM सीमा - 4.25% (चार. दो पांच प्रतिशत)
ऋण एवं अन्य दायित्व (GSDP के प्रतिशत के रूप में)	36.50% (छत्तीस. पांच शून्य प्रतिशत)	अनुमत FRBM सीमा- 38.20% (अड़तीस. दो शून्य प्रतिशत)
पूंजीगत परिव्यय	53 हजार 686 करोड़ 15 लाख रुपये (तिरेपन हजार छः सौ छियासी करोड़ पन्द्रह लाख रुपये)	गत वर्ष से 40.22% (चालीस. दो दो प्रतिशत) की वृद्धि अनुमानित

Bhs/Rtm/19.02.25/13.10/1o

II . Consolidated Sinking Fund (CSF): हमारे द्वारा किये गये वित्तीय नवाचारों से RBI द्वारा प्रदान की गई Ways and Means Advance (WMA) एवं Special Drawing Facility (SDF) का Optimum manner में उपयोग कर Fund Flow/ Liquidity management से राज्य को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में लगभग 5 सौ करोड़ रुपये (पांच सौ करोड़ रुपये) की बचत होना अनुमानित है। इसी कड़ी में हमने गत सरकार द्वारा बढ़ाये गये अत्यधिक ऋण भार के Risk Management के लिए RBI द्वारा संचालित Consolidated Sinking Fund (CSF) को भी Subscribe किया है। इसके अन्तर्गत राज्य को रेपो रेट से 2 प्रतिशत कम ब्याज दर अर्थात् 4.25% (चार. दो पाँच प्रतिशत) पर संसाधन उपलब्ध होंगे जो कि बाजार दर से लगभग 3 प्रतिशत कम है। फलस्वरूप राज्य पर ब्याज भुगतान के भार में कमी आयेगी।

III. Special Assistance Scheme for Capital Investment (SASCI):

केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में पूंजीगत निवेश बढ़ाने हेतु SASCI योजना के अन्तर्गत राज्य को 50 Year Interest Free Loan उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना से राज्य में सड़क, जलापूर्ति, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों के विकास के साथ ही अर्थव्यवस्था का समग्र विकास होगा। इस योजनान्तर्गत परिवर्तित बजट 2024-25 में 7 हजार 8 सौ करोड़ रुपये (सात हजार आठ सौ करोड़ रुपये) का प्रावधान रखा गया था। हमारे द्वारा त्वरित Compliance तथा योजनान्तर्गत पूंजीगत कार्यों के बेहतर Pace of Expenditure के आधार पर 10 हजार 500 करोड़ रुपये (दस हजार पाँच सौ करोड़ रुपये) प्राप्त होने संभावित हैं। साथ ही वर्ष 2025-26 में भी लगभग 15 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त संसाधन उपलब्ध होना संभावित है।

IV. Asset Monetisation हमारी सरकार विकास को गति देने और सम्पत्तियों के सर्वोत्तम उपयोग के लिए भारत सरकार की नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अनुरूप सड़क, परिवहन, ऊर्जा, खनन और शहरी बुनियादी ढ़ांचे जैसे क्षेत्रों में एसेट मोनेटाइजेशन के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों को leverage कर Efficient Resource Mobilization सुनिश्चित करेगी।

V. Power Sector Reforms: केन्द्रीय बजट में राज्य को Power Sector Reforms हेतु हमारे प्रस्तावों को मंजूरी देने के फलस्वरूप राज्य को वर्ष 2025-26 में भी GSDP की 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी। इसके लिए हम FRBM Act, 2005 की धारा 6 में भी संशोधन प्रस्तावित कर रहे हैं। इस प्रावधान से राज्य को लगभग 9 हजार 9 सौ 49 करोड़ रुपये (नौ हजार नौ सौ उनचास करोड़ रुपये) अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी, जिससे राज्य ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेगा।

कृषि बजट (Agriculture Budget):

164. कृषि बजट के अन्तर्गत कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु Budgetary and Extra Budgetary प्रावधानों का योजनावार एवं बजट मदवार विवरण बजट खण्ड 4 द में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कृषि बजट के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 में समेकित निधि (Consolidated Fund), राज्य की स्वायत्तशासी, सहकारी एवं अन्य संस्थाओं के स्वयं के संसाधनों सहित कुल राशि 1 लाख 10 हजार 9 सौ 81 करोड़ 40 लाख रुपये (एक लाख दस हजार नौ सौ इक्यासी करोड़ चालीस लाख रुपये) का कृषि विकास एवं कृषकों के कल्याण हेतु प्रावधान किया गया है। कृषि बजट में से राशि 65 हजार 2 सौ 32 करोड़ 4 लाख रुपये (पैंसठ हजार दो सौ बत्तीस करोड़ चार लाख रुपये) समेकित निधि से व्यय की जानी प्रस्तावित है जो राज्य के कुल बजट का 12.15% (बारह . एक पाँच प्रतिशत) है। कृषि बजट में गत वर्ष से 14.67% (चौदह . छः सात प्रतिशत) की वृद्धि अनुमानित है तथा कृषि बजट GSDP का 5.58% (पाँच. पाँच आठ प्रतिशत) है।

ग्रीन बजट (Green Budget):

165. प्रदेश में दीर्घकालीन सतत् विकास सुनिश्चित करने, सभी विकास योजनाओं में ग्रीन ग्रोथ के सिद्वान्त का समावेश करने तथा पर्यावरण संरक्षण के साथ ही प्रदेश को 'हरित राजस्थान' बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2025-26 में प्रथम ग्रीन बजट नवीन बजट खण्ड 4 य में प्रस्तुत किया जा रहा है। ग्रीन बजट में 27 हजार 8 सौ 54 करोड़ रुपये (सत्ताईस हजार आठ सौ चौवन करोड़ रुपये) का बजट प्रावधान किया गया है, जो योजनाओं पर व्यय का 11.34% (ग्यारह . तीन चार प्रतिशत) है तथा कुल बजट का 5.18% (पाँच. एक आठ प्रतिशत) है। इसके अतिरिक्त राज्य के राजकीय उपक्रमों तथा स्वायत्तशासी संस्थाओं यथा- विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, शहरी एवं ग्रामीण स्थानीय निकायों, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इत्यादि द्वारा भी स्वयं के संसाधनों से पर्यावरण संरक्षण एवं ग्रीन ग्रोथ हेतु राशि व्यय की जाती है।

166. अब मैं वर्ष 2025-26 का वार्षिक वित्तीय विवरण सभा पटल पर रख रही हूँ। साथ

ही, राजस्थान राजवित्तीय उत्तरदायित्त्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (Rajasthan Fiscal Responsibility And Budget Management Act, 2005) की अपेक्षानुसार मध्यमकालिक राजवित्तीय नीति विवरण (Medium Term Fiscal Policy Statement), राजवित्तीय नीति युक्ति विवरण (Fiscal Policy Strategy Statement) एवं प्रकटीकरण विवरण (Disclosure Statement) मैं सभा पटल पर रख रही हूँ। अन्य बजट पत्रों के साथ अनुदान की मांगें भी प्रस्तुत की जा रही हैं।

167. मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारी सरकार द्वारा जनकल्याण के लिए उठाये जा रहे कदमों से आमजन में आशा का संचार हुआ है। हम जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप भविष्य में भी इसी सार्थक भाव के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ मैं कहना चाहूँगी-

जन-जन हर्षित, हर मन गर्वित
आशा का नया सवेरा आया है,
हर गाँव, शहर और डगर-डगर,
विकास ध्वज लहराया है।

शिक्षा, न्याय और सुशासन से,
हर पल और आगे बढ़ना है,
आत्मनिर्भरता और प्रगति से,
स्वावलम्बी राजस्थान बनाना है।

पर्यावरण संरक्षण करते हुए,
कल्याण समाज का हो पायेगा,
हम सबकी भागीदारी से,
विकास राजस्थान का हो जायेगा।
विकास राजस्थान का हो जायेगा ।।

168. इन्हीं भावनाओं के साथ मैं बजट प्रस्तावों को स्वीकृत करने की संस्तुति के साथ माननीय सदन के विचारार्थ व अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करती हूं। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दिया कुमारी, उप मुख्य मंत्री आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 सदन की मेज पर रखेंगी।

श्री जोगाराम पटेल (संसदीय कार्य मंत्री): ...(व्यवधान)... एक लाइन जोड़ देते ...(व्यवधान)... विपक्ष में बिखराव आया।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2025-26 का उपस्थापन करती हूं एवं इसे सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती दिया कुमारी, उप मुख्य मंत्री राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगी।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान वित्त विधेयक, 2025

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करती हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

प्रभारी मंत्री विधेयक को पुर:स्थापित भी करेंगी।

सुश्री दिया कुमारी (उप मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान वित्त विधेयक, 2025 को पुर:स्थापित करती हूं।

श्री अध्यक्ष: सदन की बैठक गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2025 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 13:19 बजे गुरुवार, दिनांक 20 फरवरी 2025 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

परिशिष्ट 1

पैरा संख्या 5 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	ग्रामीण पेयजल परियोजना/कार्य का नाम	लागत
1.	गजनेर लिफ्ट परियोजना व कोलायत लिफ्ट परियोजना के अंतिम छोर के ग्रामों में पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य (कोलायत) - बीकानेर	58 करोड़ 4 लाख रुपये
2.	लूणकरणसर क्षेत्र के 7 ग्रामों को नहरी पेयजल से लाभान्वित करने का कार्य-बीकानेर	23 करोड़ रुपये
3.	कोलायत कस्बे व आसपास के गांवों में पेयजल योजना के सुदृढ़ीकरण का कार्य-बीकानेर	11 करोड़ 11 लाख रुपये
4.	ग्रामीण जल योजना बासनी सेजा, दोतोलाई एवं लुणीयास तहसील को पेयजल सप्लाई का कार्य तथा भूनास में पाइप लाइन व जलाशय का कार्य (मेड़ता)-नागौर	9 करोड़ 11 लाख रुपये
5.	मारवाड़ जंक्शन के फुलाद बांध पर rapid gravity जल शोधन संयंत्र, स्वच्छ जलाशय, पम्प हाउस एवं राईजिंग पाइप लाइन का निर्माण कर ग्राम पंचायत फुलाद के 6 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य-पाली	5 करोड़ 90 लाख रुपये
6.	बाड़ा, ढाणी कुम्हारान, सेहूवा, कालवास, खरतवासिया, बुचावास, अलायला, देवगढ़, पंडरेउ ताल, नेठवा में पाइप लाइन व उच्च जलाशय निर्माण का कार्य (तारानगर, सुजानगढ़)-चूरू	27 करोड़ 9 लाख रुपये
7.	पाडीहारा तथा लोहा ग्रामीण जल योजनाओं के पुनर्गठन का कार्य (रतनगढ़)-चूरू	1 करोड़ 62 लाख रुपये
8.	पीसांगन, तबीजी, मसूदा में पाइप लाइन व उच्च जलाशय निर्माण का कार्य-अजमेर, ब्यावर	9 करोड़ 16 लाख रुपये
9.	वनस्थली ग्रामीण पेयजल योजना के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य-टोंक	8 करोड़ 69 लाख रुपये
10.	जोधपुर शहर की पेरिफेरी में स्थित 36 गांवों की पेयजल आपूर्ति हेतु DPR	2 करोड़ रुपये
11.	राजीव गांधी लिफ्ट नहर आधारित देचू एवं लोहावट ब्लॉक के 79 गांवों को पेयजल आपूर्ति-जोधपुर	229 करोड़ रुपये

12.	गुढा ऐंदला-किरवा में फिल्टर प्लांट व 11 गांवों को पेयजल आपूर्ति हेतु जवाई पाइप लाइन से जुड़वाने एवं पेयजल सुधार - पाली	21 करोड़ 25 लाख रुपये
13.	महादेव वाली (खाजूवाला), हापासर, हंसेरा (लूणकरणसर) में पाइप लाइन व उच्च जलाशय निर्माण-बीकानेर	6 करोड़ 33 लाख रुपये
14.	करमीसर व गेमना पीर रोड, सुजानदेसर में पानी की टंकी व पाइप लाइन के कार्य-बीकानेर	5 करोड़ रुपये
15.	पाली के 10 व रानी के 2 गांवों को गुन्दोज ऑफटेक में सोडरवास फिल्टर प्लांट से जोड़कर पेयजल सुधार कार्य (सुमेरपुर)-पाली	8 करोड़ 43 लाख रुपये

परिशिष्ट 2

पैरा संख्या 6 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	शहरी पेयजल परियोजना/कार्य का नाम	लागत
1.	बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना स्टेज-द्वितीय (फेज-II) के अन्तर्गत common intake well with raw water transmission line, जल शोधन संयंत्र मय clear water transmission line एवं स्वच्छ जलाशय का निर्माण व अन्य सम्बन्धित कार्य (जयपुर व अजमेर)	1 हजार 986 करोड़ 68 लाख रुपये
2.	जयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर सहित 18 शहरों में जलापूर्ति के कार्य	1 हजार 650 करोड़ रुपये
3.	पाली, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, टोंक, झुंझुनूं, कुचामन सहित 11 शहरों में सतत् जलापूर्ति के गुणात्मक संवर्धन कार्य	275 करोड़ रुपये
4.	उदयपुर, चूरू, दूदू, बगरू, नसीराबाद, गुलाबपुरा, मुण्डावर, खैरथल, बहरोड़ सहित 51 शहरों में जलापूर्ति के सर्विस लेवल, सप्लाई अन्तराल व प्रेशर में सुधार सम्बन्धी कार्य	1 हजार 200 करोड़ रुपये
5.	निवाई, डिग्गी व लांबा हरिसिंह शहरी पेयजल योजनाओं के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य तथा पाईप एवं टैंक स्कीम जादमों की ढाणी को पाईप स्कीम में बदलना (मालपुरा) - टोंक	92 करोड़ 15 लाख रुपये
6.	शहरी जल योजना श्रीडूंगरगढ़ के सुदृढ़ीकरण का कार्य-बीकानेर	80 करोड़ रुपये
7.	बगरू नगर पालिका के सम्पूर्ण क्षेत्र को पेयजल योजना से जोड़ने का कार्य - जयपुर	58 करोड़ 74 लाख रुपये
8.	ग्रामीण योजना लूणकरणसर को शहरी जल योजना में क्रमोन्नत करने का कार्य (लूणकरणसर) - बीकानेर	40 करोड़ 64 लाख रुपये
9.	Zero Point Headworks पर स्वच्छ जलाशय का निर्माण कार्य-बाड़मेर	31 करोड़ 88 लाख रुपये
10.	जल योजना नापासर के सुदृढ़ीकरण का कार्य (लूणकरणसर) - बीकानेर	27 करोड़ रुपये
11.	अलवर शहर की विभिन्न कॉलोनियों में जल प्रदाय	25 करोड़ रुपये

	सुविधा विकसित करने का कार्य - अलवर	
12.	बालोतरा एवं सिवाना के लिए बफर स्टोरेज का निर्माण कार्य (पचपदरा एवं सिवाना) - बालोतरा	19 करोड़ 70 लाख रुपये
13.	शहरी जल योजना भावरी तहसील पिण्डवाड़ा के पुनर्गठन का कार्य (पिण्डवाड़ा आबू) - सिरोही	18 करोड़ 68 लाख रुपये
14.	बीसलपुर जयपुर पेयजल परियोजना के अन्तर्गत अमामीशाह पम्प हाउस पर 15 ML क्षमता के स्वच्छ जलाशय के निर्माण एवं इंटरकनेक्शन का कार्य (सिविल लाईन्स, हवामहल, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, किशनपोल) - जयपुर	17 करोड़ 69 लाख रुपये
15.	सोजत रोड पर 2.8 MLD का rapid gravity जल शोधन संयंत्र, स्वच्छ जलाशय एवं राईजिंग पाईप लाईन का निर्माण कर कंटालिया बांध से सोजत रोड की जलापूर्ति का कार्य - पाली	15 करोड़ 76 लाख रुपये
16.	बंध बारैठा से मलाह हैड वर्क्स भरतपुर तक पुरानी 600 एमएम जीआरपी पाइप लाइन के स्थान पर डीआईके-7 पाइप लाइन बदलने का कार्य - भरतपुर	67 करोड़ 73 लाख रुपये
17.	मारवाड़ जंक्शन को जाडन से जवाई बांध का पानी उपलब्ध करवाने का कार्य - पाली	13 करोड़ 8 लाख रुपये
18.	भरतपुर में SPZ योजना में जल आपूर्ति का कार्य	10 करोड़ रुपये
19.	शहरी जल योजना तारानगर में पुरानी व जर्जर पाइप लाइनों एवं पुराने पम्प सैट बदलने का कार्य (तारानगर) - चूरू	1 करोड़ 22 लाख रुपये
20.	शहरी जल योजना नगर परिषद् नागौर की सीमा क्षेत्र से बाहर बसी आबादी को पेयजल सप्लाई से लाभान्वित करने के लिए जल योजना - नागौर	17 करोड़ 94 लाख रुपये
21.	देशनोक में पेयजल व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का कार्य (कोलायत) - बीकानेर	9 करोड़ रुपये
22.	नावां शहर के नहरी पेयजल से अलाभान्वित/वंचित क्षेत्र में नहरी पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य (नावां) - डीडवाना कुचामन	26 करोड़ 3 लाख रुपये
23.	गढ़ी में पेयजल वितरण प्रणाली विस्तार संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य (गढ़ी) - बांसवाड़ा	19 करोड़ 84 लाख रुपये
24.	टोडारायसिंह व मालपुरा शहर में स्मार्ट वॉटर मीटर	7 करोड़ 55 लाख रुपये

	लगाने का कार्य (मालपुरा) - टोंक	
25.	आंवली-रोझड़ी व नयागांव को अकेलगढ़ हैडवर्क्स से जोडने का कार्य (रामगंज मण्डी) - कोटा	2 करोड़ 48 लाख रुपये
26.	तकली बांध से रामगंज मण्डी शहरी पेयजल योजना एवं खुडीयाला रीको के संवर्धन तथा सुदृढ़ीकरण का कार्य (रामगंज मण्डी) - कोटा	110 करोड़ 79 लाख रुपये
27.	सांगोद में अतिरिक्त जल शोधन संयंत्र का कार्य - कोटा	8 करोड़ रुपये
28.	शहरी क्षेत्रों में Highrise Buildings में भी PHED द्वारा connections दिये जाने की व्यवस्था	-

परिशिष्ट 3

पैरा संख्या 12 में उल्लिखित विवरण

क्र. सं.	जीएसएस निर्माण/ क्रमोन्नयन
1	765 केवी जीएसएस-नागौर
2	400 केवी जीएसएस आमेर जयपुर देचूं फलौदीः बांसवाड़ा, सवाई माधोपुरः डेहरा (लाडपुरा) कोटा
3	220 केवी जीएसएस-बबलू (लूणकरणसर) बीकानेर, ग्राम भोपा जैसलमेर, बालेसर (शोरगढ़)-जोधपुर 220 केवी जीएसएस में क्रमोन्नयन-पलाना-बीकानेर, पोकरण-जैसलमेर; हेमड़ा-झालावाड़ः लांबा जाटान (मेड़ता) नागौर सहित 13 GSS
4	132 केवी जीएसएस-हाथीभाटा अजमेर, भोजपुरा, कठूमर अलवर, बावडीकला (बौहटन) अगासड़ी (शिव) बाड़मेर, आरपीएल नगर-भीलवाड़ा; गेमनापीर रोड बीकानेरः निदानी (दूदू) कानोता-जयपुर जाखल (नवलगढ़), छावसरी (उदयपुरवाटी) झुंझुनूं, कापरडा सेज (बिलाडा) जोधपुर, घंटियाली फलौदी; चेचट (रामगंजमडी) कोटा, रावला (अनूपगढ़) श्रीगंगानगर सहित 28 GSS
5	33/11 केवी जीएसएस-तिलोरा (पुष्कर) अजमेर, बरडिया बालाजी, छजावा (अटरू), भुवाखेडी (छबडा), टांचा (छीपाबड़ौद), दुर्जनपुरा, सिमलोद-बारा, तारातरा मठ, मुकने का तला (चौहटन), खोखसर, केशुम्बला (बायतू), गांगापुरा (शिव) बाड़मेर, अन्नपूर्णा माताजी होड्र (सिवाना) बालोतरा, खजूरा कोटडा. कुशलगढ़ नगर, पनासी छोटी-बांसवाड़ा, मैरथा, विनऊआ (बयाना), लालपुर, धानोता, गगवाना (नदबई). बछामदी, माडौनी, अघापुर (सेवर), बारहमाफी (उच्चैन) भरतपुर बढ़ेसरा मोरोली, लहरवाडा (नगर)-डीग, गोविन्दपुरा (आसींद) रेडवास (जहाजपुर), जलीन्द्री (मांडलगढ़) भीलवाड़ा, डेलवा, हेमासर-फांटा (डूंगरगढ़), तख्तपुरा, सत्तासर (खाजूवाला) बीकानेर, सहेला (रतनगढ़), लुहारा (सुजानगढ़), कंवलासर, सोनपालसर (सरदारशहर), नेठवा (तारानगर) चूरू, टुडियाना, समलेटी (महुवा), भाण्डारेज, श्यालावास (सिकराय) दौसा, सागवाडा, दिवडा छोटा, करावड़ा-डूंगरपुरः जारह-धौलपुरः गाढ़ौता (दूदू), धौला, गुवारडी (जमवारामगढ़) जयपुर, मोरवा, जगदीशपुरा-कोटपूतली बहरोड़, खेतासर-फांटा व बादरिया (पोकरण), हाबुर, उगबा जैसलमेर; ओसाव (पिडावा), धतूरिया कलां (झालरापाटन) झालावाड़; मुकुन्दगढ़-झुंझुनूं; ताली (मासलपुर), महस्वा (टोडाभीम) करौली; मांझी, निम्बोलाकलां (डेगाना), टालनियाऊ, गौरव (जायल), कालियास, मोजास (खीवसर) नागौर, डेडा. गुड़ा ऐंदला (सुमेरपुर)-पाली; धासरिया, जालपा (भीम) राजसमंद, जूनी बढ़ावली. गींगला सलूम्बर; मामडोदा, सांवराद डीडवाना कुचामन, जाजुसन (सांचौर) जालोर, थड़ी, चूली (गंगापुरसिटी) सवाई माधोपुरः शिश्यू (दांतारामगढ़) सीकर, चैनपुरा (निवाई) टोंक सहित 133 GSS

परिशिष्ट 4

पैरा संख्या 15 में उल्लिखित सूची

I. State Highways व अन्य सड़क निर्माण कार्य-

क्र.सं.	State Highways/सड़कें	लागत
1.	डेरा से सपडावली वाया जामडोली सड़क (10 किमी.) (राजगढ़ -लक्ष्मणगढ़)-अलवर	10 करोड़ रुपये
2.	रैणी से माचाड़ी सड़क (14 किमी.) (MDR-151) (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)-अलवर	14 करोड़ रुपये
3.	हल्दीना-निठारी-जमालपुर-खेड़ला-रामपुरा-खेड़ली पिचानोत-खारेडा-बीजवाड़-मोहब्बतपुर-कल्याणपुरा- अलापुर से NH-248A (37.5 किमी.)-अलवर	40 करोड़ रुपये
4.	शेरपुर से गैलपुर वाया जोडिया, चावण्डी, भौंकर सड़क (MDR-199) (10 किमी.) (किशनगढ़बास-तिजारा) - खैरथल-तिजारा	17 करोड़ 50 लाख रुपये
5.	खैरथल से शेखपुर वाया बघेरी कलां, बीबीरानी, जोडिया सड़क (MDR-318) (41 किमी.) (किशनगढ़बास-तिजारा)-खैरथल-तिजारा	61 करोड़ 50 लाख रुपये
6.	नीमराना (SH-111A) से बीघाना जाट, हरियाणा सीमा तक वाया सलारपुर, घीलोठ, माढण, रायसराना सड़क (MDR-332) (28.62 किमी.) (मुण्डावर, बहरोड़)- कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल तिजारा	49 करोड़ 30 लाख रुपये
7.	रामपुरा से बालोतरा (SH-68) वाया अजीत, समदड़ी, जेठन्तरी कनाना रोड (49 किमी.) (सिवाना, पचपदरा)-बालोतरा	57 करोड़ 50 लाख रुपये
8.	थलकला से भोरण चौराहा वाया सरथला, ठिठोडा जागीर, खैरूणा सड़क (MDR-279) (15 किमी.) (माण्डलगढ़, जहाजपुर)- भीलवाड़ा	27 करोड़ रुपये
9.	सांगानेर-ढिकोला (MDR-165) (कायड चौराहा से डूंगरी चौराहा) (12 किमी.) (शाहपुरा)-भीलवाड़ा	21 करोड़ 50 लाख रुपये
10.	कादिसहना से मालाखेड़ा वाया मीनों का झोपड़ा सड़क मय पुलिया (4 किमी.) - भीलवाड़ा	4 करोड़ रुपये
11.	NH-11 से NH-911 (बाप-बीकमपुर सड़क) वाया मण्डाल चारणान, गड़ियाला, गिराजसर, नगरासर, सेवड़ा सड़क	61 करोड़ 80 लाख रुपये

	(MDR-365) (61.80 किमी.) (शाहपुरा)-भीलवाड़ा	
12.	भामटसर से सुरपुरा सड़क (MDR-411) (10 किमी.) (नोखा) - बीकानेर	11 करोड़ 50 लाख रुपये
13.	अरनोद-गौतमेश्वर-सालमगढ़-बड़ी घण्टाली-पीपलखूंट-दानपुर-माहीडेम सड़क (MDR-290) (17 किमी.) (प्रतापगढ़, घाटोल)-प्रतापगढ़	20 करोड़ रुपये
14.	बीलवाडी (NH-248A) से ढोढसर (NH-57) वाया राडावास सड़क (MDR-188) (38.5 किमी.) (शाहपुरा, चौमूं)- जयपुर	35 करोड़ रुपये
15.	साण्डेराव मोकलसर सड़क (MDR-203) (49 किमी.) (आहोर, भाद्राजून)-जालोर	65 करोड़ रुपये
16.	सुनेल से गैलानी, कोटडी, पिड़ावा एमपी सीमा तक (MDR-378) (15.60 किमी.) (झालरापाटन)-झालावाड़	24 करोड़ 18 लाख रुपये
17.	गैलानी (MDR-179) से रायपुर, झूमकी, खानपुरिया, कलमण्डी कलां, किशनपुरिया, झालावाड़ खाण्डिया NH-52 तक (MDR-379) (37 किमी.) (झालरापाटन) - झालावाड़	57 करोड़ 35 लाख रुपये
18.	सुनेल से गोविन्दपुरा, करावन वाया धतुरिया एमपी सीमा तक (MDR-377) (10.35 किमी.) एवं सबमर्सिबल पुल का निर्माण कार्य (झालरापाटन, डग)-झालावाड़	40 करोड़ रुपये
19.	उनी, तुरकाड़िया, बरडावदा, बिन्दा, देवरीकला, मदनपुरा (MDR-380) (18.30 किमी.) (मनोहरथाना)- झालावाड़	28 करोड़ 36 लाख रुपये
20.	फलौदी-जांबा-मोटाई चाखु-चिमाणा ढाढरवाला जिला सीमा मदनपुरा (MDR-282) (53 किमी.)-फलौदी	55 करोड़ 65 लाख रुपये
21.	NH-148D से बामनगांव-करवर, आंतरदा (SH-34) तक (MDR-410) (33 किमी.) (हिण्डोली, केशोरायपाटन) बूंदी	80 करोड़ रुपये
22.	मणाई से एकलखोरी वाया मथानियाँ, माण्डियाई खुर्द (MDR-383) (67 किमी.) (लूणी, ओसियाँ)-जोधपुर	98 करोड़ रुपये
23.	केलवा (NH-8) से आमेट सड़क (MDR-77) (18 किमी.) (राजसमंद, कुम्भलगढ़)- राजसमंद	30 करोड़ रुपये
24.	मादरी (SH-12) से लासानी ताल NH-8 वाया आमेट देवगढ़ (SH-56) सड़क (40 किमी.)- राजसमंद	40 करोड़ रुपये
25.	देवल से नगर वाया लाम्बाहरिसिंह, मौरला, थड़ी (MDR-308) (25.43 किमी.) (मालपुरा)-टोंक	58 करोड़ 50 लाख रुपये
26.	गोगुन्दा से रामपुरा वाया मजावद, धार (MDR-148) (39 किमी.) (गोगुन्दा, बड़गांव, गिर्वा)-उदयपुर	65 करोड़ 25 लाख रुपये

27.	बगरू से रीको औद्योगिक क्षेत्र-कुंजबिहारीपुरा तक सम्पर्क सड़क का निर्माण-जयपुर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
28.	सांवलता से जीवन्द कलां तथा खारडा से जीवन्द कलां सड़क-पाली	6 करोड़ 62 लाख रुपये
29.	जीवन्द कलां से ढ़ाणी रामदेवजी मन्दिर नदी पर पुल निर्माण-पाली	4 करोड़ 25 लाख रुपये
30.	बालावाला लाखना से चन्दलाई वाया वाटिका सेक्टर रोड-जयपुर	50 करोड़ रुपये
31.	भरतपुर-मथुरा सड़क फोरलेन निर्माण कार्य (रेलवे स्टेशन) से मथुरा बाईपास left out portion (SH-01) (3 किमी.)-भरतपुर	25 करोड़ रुपये
32.	हीरादास सर्किल से सुभाष नगर गौशाला होते हुए मथुरा-बाईपास तक फोरलेन सड़क निर्माण कार्य (2.50 किमी.)-भरतपुर	20 करोड़ रुपये
33.	भरतपुर-अछनेरा सड़क फोरलेन निर्माण कार्य (पार्ट ए मानसिंह सर्किल से बझेरा upto अपना घर तक) (10 किमी.)- भरतपुर	75 करोड़ रुपये
34.	खेमकरण तिराहा से जघीना तक चौड़ाईकरण का कार्य (5 किमी.) - भरतपुर	15 करोड़ रुपये
35.	सरसों अनुसंधान केन्द्र से चामड माता मंदिर तक सिक्सलेन निर्माण कार्य (1.50 किमी.)- भरतपुर	25 करोड़ रुपये
36.	बंध बारैठा से उच्चैन वाया खेरिया मोड सड़क (SH-43) चौड़ाईकरण एवं नवीनीकरण कार्य (23.50 किमी.)- भरतपुर	158 करोड़ 81 लाख रुपये
37.	NH-21 से SH-01 से उच्चैन वाया अटारी-बछामदी सड़क (16 किमी.)- भरतपुर	35 करोड़ रुपये
38.	अलवर में कृषि भूमि पर बसी हुई स्वीकृत कॉलोनियों में सीसी सड़क निर्माण कार्य-अलवर	10 करोड़ रुपये
39.	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र एवं विद्याधर नगर में विभिन्न सड़कों का कार्य-जयपुर	55 करोड़ रुपये
40.	खोह से उत्तर प्रदेश सीमा (बरसाना) वाया सेऊ धमारी - नाहराचौथ-डीग	21 करोड़ 30 लाख रुपये
41.	भूगोर तिराहे से हनुमान चौराहे तक (86/800 किमी. से 92/400 किमी.) के NH 248-A को टू लेन सड़क से फोरलेन करना (5.6 किमी.) (अलवर शहर)-अलवर	50 करोड़ रुपये

42.	गगवाना NH 8 से प्रसिद्ध खोडा गणेश मंदिर तक डबल लेन सड़क (11.5 किमी.) (पुष्कर) अजमेर	20 करोड़ रुपये
43.	ढाकपुरी से हल्दीना तक सड़क (2.5 किमी.) अलवर	1 करोड़ रुपये
44.	बैरावास खुर्द से जोडीया तक सड़क (1.3 किमी.) - अलवर	68 लाख रुपये
45.	पाली से स्कूल से ग्राम परबैणी तलाई तक डामर सड़क (4 किमी.) - (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)-अलवर	1 करोड़ 50 लाख रुपये
46.	अम्बेडकर नगर से परबैणी तक डामर सड़क (4 किमी.) (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़)-अलवर	2 करोड़ रुपये
47.	हलैना से बड़ौदामेव सड़क (32 किमी.) (कठूमर)-अलवर	40 करोड़ रुपये
48.	महुआ-पलखडी-सावडी NH-248A सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण (7 किमी.) - अलवर	5 करोड़ रुपये
49.	सिणधरी से सिवाना मोकलसर डबल लाइन सड़क (18 किमी.) (सिवाना)-बालोतरा	18 करोड़ रुपये
50.	मोटी टिम्बी से गडुली वाया भोंगापुरा तक सड़क (10 किमी.) - बांसवाड़ा	10 करोड़ रुपये
51.	बोरी से बिलोदा वाया चन्दनपुरा सड़क चौड़ाईकरण (6 किमी.) (गढ़ी)-बांसवाड़ा	9 करोड़ रुपये
52.	नालपाडा-मस्का-कसारवाडी तक सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण (6 किमी.) (कुशलगढ़)-बांसवाड़ा	9 करोड़ रुपये
53.	कोहनी से गणेशपुरा तक सड़क (3 किमी.) (छबड़ा)-बारां	2 करोड़ 40 लाख रुपये
54.	छबड़ा में पावर हाउस से गुगोर तिराहे तक डिवाइडर मरम्मत कार्य-बारां	5 करोड़ रुपये
55.	छीपाबड़ौद से झनझनी उमरिया वाया पीथपुर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (18.5 किमी.) (छबड़ा)-बारां	25 करोड़ रुपये
56.	NH 27 बालाचार से निवाड़ी, खटका, गणेशपुरा, सेमली फाटक, धतुरिया से पहाड़ी, राजपुर तक सड़क का चौड़ाईकरण व डबल लेन (22.5 किमी.) (किशनगंज)-बारां	45 करोड़ रुपये
57.	बसई वंशी पहाड़पुर से रूपवास तक, छउआ मोड़ से सिंघनिया तक (13 किमी.), महलपुर चूरा से वंशी पहाड़पुर तक सड़क (1 किमी.) (बयाना)- भरतपुर	13 करोड़ 40 लाख रुपये
58.	राजा खैमकरण चौराहे से न्यू रीको औद्योगिक क्षेत्र तक सड़क चौड़ाईकरण (4 किमी.)-भरतपुर	15 करोड़ रुपये
59.	राजड़ाल से खेड़ाल ग्रेवल सड़क का डामरीकरण (4 किमी.)	1 करोड़ 60 लाख

	(शिव)-बाड़मेर	रुपये
60.	सतपुलिया ज्योतिबा सर्कल से देलवाड़ा तक सिक्सलेन सड़क का चौड़ाईकरण (2 किमी.) - ब्यावर	4 करोड़ रुपये
61.	ब्यावर से अजगर बाबा का थान सेन्दडा रोड ब्यावर तक सिक्सलेन सड़क का चौड़ाईकरण (3 किमी.) - ब्यावर	6 करोड़ रुपये
62.	पेच की बावड़ी से पगारा वाया महादेव मंदिर तक सड़क सुदृढ़ीकरण (9 किमी.) (हिण्डोली) बूंदी	17 करोड़ रुपये
63.	बडला से सोपुरा (जाटों को) तक सड़क (3.5 किमी.)-भीलवाड़ा	1 करोड़ 90 लाख रुपये
64.	सबलपुरा से मंगरोप बाईपास बनाते हुए मंगरोप तक सड़क (7 किमी.) (माण्डल)- भीलवाड़ा	10 करोड़ रुपये
65.	रघुनाथपुरा से शम्भुगढ़ वाया आसीन्द (19 किमी.) विद कॉजवे का कार्य (आसीन्द)-भीलवाड़ा	8 करोड़ 10 लाख रुपये
66.	सेनुण्दा से गोरर्धनपुरा रघुनाथपुरा रूपपुरा गौराणा नारेली रामपुरिया चाडो का बाडिया व किडिमाल हाईवे तक (30 किमी.) (माण्डल)-भीलवाड़ा	40 करोड़ रुपये
67.	ठुकरियासर से लिखमादेसर वाया कुंतासर, धीरदेसर, चोटियान होते हुए कितासर भाटीयान तक सड़क (22.80 किमी.) (डूंगरगढ़)-बीकानेर	23 करोड़ रुपये
68.	NH 11 नकोदेसर-जालबसर उदरासर आडसर-1 मोमासर, लाछडसर जिला सीमा SH 06 तक सड़क (51 किमी.) (डूंगरगढ़)-बीकानेर	51 करोड़ रुपये
69.	रायसर से रामदेवरा मंदिर नोखा रोड़ वाया दासनू सोमलसर-घट्टू-माडिया डामर सड़क (20 किमी.) (नोखा)-बीकानेर	24 करोड़ रुपये
70.	मुकाम मुख्य द्वार से समराथल धोरा तक सड़क को फोरलेन डिवाईडर सड़क (3.5 किमी.) बीकानेर	6 करोड़ रुपये
71.	कुचौर आथूणी से SH 20B फांटा होते हुए खेराज भौमिया गौशाला तक डबल लाईन डामर सड़क (6 किमी.) बीकानेर	6 करोड़ 30 लाख रुपये
72.	बिग्गा बास रामसरा से रुस्तम धोरा तक सड़क (8.5 किमी.) (डूंगरगढ़)-बीकानेर	1 करोड़ रुपये
73.	नेशनल हाइवे 62 रासीसर से सोवा तक (14 किमी.)-बीकानेर	5 करोड़ 40 लाख रुपये
74.	अनगढ़ बावजी से सोहनखेड़ा तक सड़क (3.5 किमी.) (कपासन) - चित्तौड़गढ़	1 करोड़ 50 लाख रुपये

75.	पालछा से उदपुरा बरसिंग का गुढा गढ़वाड़ा घराणा घटियावली केलझर महादेव नेतावल गढपाछली तक सड़क (30 किमी.) - चित्तौड़गढ़	40 करोड़ रुपये
76.	जयसिंहपुरा (काटून्दा रावतभाटा रोड़) में बामनहेडा चेंची बाईपास होते हुए सेमलिया-धामंचा एमपी तक सड़क (10 किमी.) (बेगू)-चित्तौड़गढ़	28 करोड़ रुपये
77.	आकोला से फलासिया तक सड़क (17 किमी.) चितौड़गढ़	22 करोड़ रुपये
78.	बड़ी सादड़ी क्षेत्र में मिसिंग लिंक सड़कों का कार्य - चित्तौड़गढ़	17 करोड़ रुपये
79.	तारानगर क्षेत्र की सड़कों के कार्य (तारानगर) चूरू	15 करोड़ रुपये
80.	कृषि महाविद्यालय खासोली तक सड़क (8.5 किमी.) चूरू	3 करोड़ 50 लाख रुपये
81.	उडवाला से लुहारा होते हुए परावा तक सड़क (14 किमी.) (सुजानगढ़)-चूरू	4 करोड़ रुपये
82.	हरपालु से रामपुरा वाया भोजान तक सड़क का चौड़ाईकरण (23 किमी.) (सादुलपुर)-चूरू	21 करोड़ रुपये
83.	हमीरवास से रामपुरा वाया बेवड़ सड़क चौड़ाईकरण (15 किमी.) (सादुलपुर)-चूरू	14 करोड़ रुपये
84.	चांदगोठी से रामपुरा वाया भैंसली सड़क चौड़ाईकरण (19 किमी.) (सादुलपुर)-चूरू	18 करोड़ रुपये
85.	ढाणी पांचेरा से फोगा मिसिंग लिंक सड़क कार्य (8 किमी.) (सरदारशहर)-चूरू	2 करोड़ 80 लाख रुपये
86.	SH-22 से करीरी जिला सीमा तक (4 किमी.) (3.50 करोड) (महुवा)-दौसा	3 करोड़ 50 लाख रुपये
87.	SH-22 से करीरी-भैरोजी वाया पथवारी जोधपुर गाय तक सड़क (10 किमी.) (महुवा) दौसा	6 करोड़ रुपये
88.	SH 24 से हेमल्यावाला वाया भयपुर का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (17 किमी.) (लालसोट)-दौसा	20 करोड़ रुपये
89.	कल्लावास से सोनड चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (15 किमी.) (लालसोट)-दौसा	15 करोड़ रुपये
90.	लालसोट शहरी गौरव पथ (ODR-21) का सीसी सड़क उन्नयनीकरण कार्य (2 किमी.) (लालसोट) दौसा	8 करोड़ रुपये
91.	भाडीती से बस्सी वाया लालसोट तूंगा किमी. 49/000 से 69/100 चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (SH-24) (16.60	13 करोड़ 28 लाख रुपये

	किमी.) (लालसोट) - दौसा	
92.	बासबुर्जा से डीग सड़क तक वाया गोविंदगढ पडलवास - ककडा-पान्हौरी, (42 किमी.) (नगर)- डीग	51 करोड़ रुपये
93.	गोवर्धन ड्रेन की पटरी पर तालफरा से डिडवारी होते हुए कॉरेर बाईपास तक सड़क (6 किमी.) (कुम्हेर)-डीग	3 करोड़ रुपये
94.	समोला पोखर से खरगपुरा रोड़ तक पक्की सड़क (2 किमी.) -धौलपुर	1 करोड़ रुपये
95.	मोरेड (मकराना) से बंडू (परबतसर) तक क्षतिग्रस्त एवं जर्जर सड़क का नवीनीकरण / डामरीकरण (10 किमी.)- डीडवाना कुचामन	1 करोड़ 80 लाख रुपये
96.	रामसिया से मोडी चारण तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (5 किमी.) - डीडवाना-कुचामन	1 करोड़ 50 लाख रुपये
97.	चौमूं में मोहन झाझड़, कलालियों की ढ़ाणी, नाडीवाली ढ़ाणी सरसर डेयरी, प्रभुदयाल जीतरवाल के मकान तक सीसी रोड़ (2 किमी.) (चौमूं)-जयपुर	1 करोड़ 10 लाख रुपये
98.	सीतारामपुरा सड़क किनारे नाला (चौमूं)- जयपुर	1 करोड़ 20 लाख रुपये
99.	भोपावास मोड़ से नाटाणी वाली तिवारी तक डामर सड़क (3 किमी.) (चौमूं)-जयपुर	1 करोड़ 5 लाख रुपये
100.	कचौलिया रोड़ गणपति डिस्ट्रीब्यूटर्स से शाहीबाग गार्डन, गणेश विहार रोड़, सी.एम. चौपड़ा हॉस्पिटल, जयपुर रोड़ की ओर पानी निकास प्रबंधन मय नाला (2) किमी.) (चौमूं) जयपुर	1 करोड़ 50 लाख रुपये
101.	राजपुरवास ताला से शाहपुरा तहसील सीमा तक, कांकरेल मोड भानपुर कलां सड़क से जमवारामगढ़ तक, नाभावाला से नीमला तक, मानोता से सन्नाटा घाटी चावंडिया-धामस्या तक, नकटी घाटी से दौसा तक सड़क (52 किमी.) (जमवारामगढ़)-जयपुर	62 करोड़ रुपये
102.	बस्सी से सांभरिया तक सड़क का चौड़ाईकरण (10 किमी.) जयपुर	9 करोड़ रुपये
103.	चाकसू से भादरवास तक, SH-02 से तितरिया वाया थली करेडाखुर्द सदारामपुरा देवकिशनपुरा तक व पुराना NH-12 से SH-02 तक वाया आजमनगर कल्याणपुरा करेडाखुर्द तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण, पदमपुरा से खाजलपुरा	70 करोड़ 50 लाख रुपये

	तक रोड का सुदृढ़ीकरण (47 किमी.) (चाकसू)-जयपुर	
104.	दौसा से कुचामन वाया लवान-तुंगा-चाकसू-फागी-दूदू सांभर सड़क (SH-02) कि.मी. 93/3 से 96/0, 101/0 से 103/0, 106/0 से 109/0 एवं 130/0 से 133/025 सड़क का सुदृढ़ीकरण (10.13 किमी.) (दूदू)-जयपुर	32 करोड़ 66 लाख रुपये
105.	नगर-ईटाखोई-धांधोली- रेहलाना गागरड़ू-हरसोली पड़ासोली - साली- गहलोता-बुहारू सड़क का सुदृढ़ीकरण कि.मी. 10/0 से 14/0, 16/0 से 17/0 (MDR-280) (5 किमी.) (दूदू)-जयपुर	7 करोड़ 50 लाख रुपये
106.	जोबनेर क्षेत्र की सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण कार्य-जयपुर	25 करोड़ रुपये
107.	चौमूं रेनवाल सड़क बस स्टैण्ड मण्ढा भिण्डा से हस्तेडा (8 किमी.)- जयपुर	10 करोड़ 70 लाख रुपये
108.	आष्टी कलां से लालसर (5.30 किमी.) (चौमू)- जयपुर	7 करोड़ रुपये
109.	खिजूरियां, करणसर बस स्टैण्ड से पूनाना, आमेर सीमा तक सड़क कार्य (6 किमी.) (झोटवाड़ा)- जयपुर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
110.	चौमूं से महला सड़क के उन्नयन/चौड़ाईकरण की DPR - जयपुर	2 करोड़ रुपये
111.	विरोल से गुजरात बोर्डर तक सड़क (3.5 किमी.) (सांचौर)-जालोर	1 करोड़ 40 लाख रुपये
112.	सिलू ग्राम से गुजरात बोर्डर तक सड़क (3.5 किमी.) (सांचौर)-जालोर	1 करोड़ 40 लाख रुपये
113.	हरियाली से अरणाय तक सड़क (4 किमी.) (सांचौर)-जालोर	1 करोड़ 60 लाख रुपये
114.	गोलासन उकाजी की ढाणी गुजरात बोर्डर तक सड़क (4.5 किमी.) (सांचौर)-जालोर	1 करोड़ 80 लाख रुपये
115.	सांचौर में विभिन्न नवीन सड़कें जालोर	10 करोड़ रुपये
116.	भाटकी से गुजरात बोर्डर तक सड़क (4.5 किमी.) (सांचौर) जालोर	2 करोड़ 80 लाख रुपये
117.	गुड़ाहेमा से सातपालिया मंदिर बाड़मेर सरहद तक सड़क (6 किमी.) (सांचौर) जालोर	3 करोड़ रुपये
118.	ग्राम सिराणा से जिला सीमा सांचौर ग्राम रंगाला सरहद तक मिसिंग लिंक सड़क (8 किमी.)-जालोर	3 करोड़ 20 लाख रुपये

119.	मुख्य सड़क वासन से धोरेश्वर महादेव मंदिर तक मिसिंग लिंक सड़क (2 किमी.) जालोर	70 लाख रुपये
120.	विभिन्न मिसिंग लिंक सड़कों का निर्माण एवं उन्नयन (झालरापाटन) - झालावाड़	25 करोड़ रुपये
121.	झागुका की ढाणी-जाखल तिराह- धींवा की जोहड़ी इसरोट बालाजी मंदिर गाड़ोदिया की ढाणी मुण्डों की ढाणी-मीणा की ढाणी, जोहड झरड़ावली ढाणी चरणदास जी मंदिर से भिखाली जोहड़ी-भगेरा से बुगाला गिरानी जोहड़ी (सोटवारा)। (33 किमी.) (नवलगढ़)-झुंझुनूं	10 करोड़ 62 लाख रुपये
122.	मेहाड़ा-गौरीर-दूधवा शिमला-रवाँ पचेरी सड़क (11 किमी.) (खेतड़ी)-झुंझुनूं	18 करोड़ 70 लाख रुपये
123.	हाई-वे 13 बबाई से कालोटा-माधोगढ़-पदेवा दलेलपुरा - सेफरागुवार-चिंचडोली तक सड़क (27 किमी.) (खेतड़ी)-झुंझुनूं	43 करोड़ 20 लाख रुपये
124.	मण्डावा में MDR 25 बी से कमालसर से दिलोई दक्षिण से श्यामपुरा से सिरियासर खुर्द से SH 37 तक सड़क चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण (34 किमी.) (मण्डावा)- झुंझुनूं	25 करोड़ रुपये
125.	देचू में 85 मील से चाँदसमा तक सड़क चौड़ाईकरण (10 किमी.)-फलौदी	11 करोड़ रुपये
126.	दासनिया-उंटवालिया-चांदसमा होते हुए लवां बार्डर तक सड़क (47 किमी.)-फलौदी	50 करोड़ रुपये
127.	पुनासर से चाडी सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (8 किमी.) (लोहावट)-फलौदी	10 करोड़ रुपये
128.	जाखण-बापिणी-बेदू-पल्ली-लोहावट सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (46 किमी.) (लोहावट)- फलौदी	45 करोड़ रुपये
129.	देचू डामर सड़क से इडियों की ढाणी वाया प्राथमिक विद्यालय, रामदेव की ढाणी शहीद गोपाल नगर होते हुए भेड सरहद तक (4 किमी.)-फलौदी	1 करोड़ 34 लाख रुपये
130.	नौसर से चौतीणा बेरा पूनियों की ढाणी डामर सड़क चौराहा से पातावत भारताणी मेघवालों की ढाणी (4.5 किमी.) फलौदी	1 करोड़ 50 लाख रुपये
131.	लूणी की बोरानाड़ा से सालावास, बासनी सर से दुन्दाड़ा से जिला सीमा तक, गुढ़ा से भाण्डू कलां वाया मोगड़ा सालावास नन्दवान हिरखेड़ा सड़कों के निर्माण (लूणी)-जोधपुर	30 करोड़ रुपये
132.	वारे वाले हनुमान जी से नसीर पर्वत की तलहटी होते हुए	16 करोड़ रुपये

	टोंका-नंदे भूमिया-देवनारायण मंदिर-सोना भूमिया फूले की झोपड़ी से परीता तक सड़क (12 किमी.) - करौली	
133.	ऐंड कलाँ से गुर्जा तक सड़क मय पुलिया निर्माण (5 किमी) करौली	3 करोड़ 50 लाख रुपये
134.	बुचारा बांध से बुड़लकिया की ढाणी तक गोपी मीणा के मकान तक (1.5 किमी.) कोटपूतली बहरोड़	2 करोड़ रुपये
135.	हरसौरा-छिपारी-भूरियावास सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण (11 किमी.) (बानसूर)-कोटपूतली बहरोड़	14 करोड़ रुपये
136.	अजबपुरा-चाँदपुरी सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (8.5 किमी.) (बानसूर)-कोटपूतली-बहरोड़	12 करोड़ रुपये
137.	200 फीट सड़क घीलोठ औद्योगिक क्षेत्र कुतिना से मोहनपुर (हरियाणा सीमा) तक सड़क (8 किमी.) कोटपूतली बहरोड़	8 करोड़ रुपये
138.	बानसूर से फतेहपुर सड़क चौड़ाईकरण व नवीनीकरण (5 किमी.)-कोटपूतली बहरोड़	5 करोड़ रुपये
139.	अलवर-बहरोड़ किमी. 108/0 से 182/0 को 2 लेन से 4 लेन (84 किमी.) का DPR कार्य-कोटपूतली-बहरोड़	2 करोड़ 50 लाख रुपये
140.	अलवर-भिवाड़ी मेगा हाईवे (SH-25) से किशनगढ़बास-कोटकासिम (SH-109) तक वाया भिण्डूसी-गहनकर-गोठडा किमी. 0/0 से 6/0 सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण-खैरथल-तिजारा	13 करोड़ रुपये
141.	तितरका (MDR-319) से बाघोडा (MDR-200) तक वाया डोटाना, बेरला जैरोली, थोंस किमी. 0/0 से 14/0 सड़क चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण (तिजारा)- खैरथल तिजारा	22 करोड़ रुपये
142.	बीबीरानी करवड-उदयपुर-ढाकी-शंकर का तिबारा बारका श्यामों की ढाणी, तिजारा तक सड़क का चौड़ाईकरण (13.5 किमी.) (किशनगढ़बास)- खैरथल तिजारा	22 करोड़ रुपये
143.	डामर रोड मेन रोड सोरखा खुर्द से जिदोली की ओर (3 किमी.) (मुण्डावर) - खैरथल तिजारा	70 लाख रुपये
144.	देवनारायण मन्दिर, मूंडिया से भोलू की कोठी वाया हररूप का बेडा (4 किमी.) करौली	2 करोड़ रुपये
145.	RSVPN कार्यालय से तालछी पुलिया तक सड़क का चौड़ाईकरण एवं डिवाईडर (2 किमी.) (सांगोद)-कोटा	12 करोड़ रुपये
146.	रामगंजमण्डी जुल्मी सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण (8) किमी.) (रामगंजमण्डी)-कोटा	15 करोड़ रुपये

147.	अमझाट-खेड़ली-चेचट-मदनपुरा, गोयन्दा मध्य प्रदेश सीमा तक MDR-253, किमी. 15/0-33/500 सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (18.5 किमी.) (रामगंजमण्डी)-कोटा	35 करोड़ रुपये
148.	कुराड़ ढोटी-कन्दाफल-मण्डाप-श्यामपुरा-सांगोद सड़क (MDR-178) का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण (32.60 किमी.) (सांगोद)-कोटा	45 करोड़ रुपये
149.	कोटा में विभिन्न सड़कों के कार्य	25 करोड़ रुपये
150.	डेह (NH-58) से गेनाना (NH-458) वाया खेड़ा छापड़ा-रोटू गोराऊ सांडास मालगांव सड़क का सुदृढीकरण (37 किमी.) (जायल)-नागौर	35 करोड़ रुपये
151.	खरनाल-बरणगांव बासनी-सिंगड़-गोगानाडा अलाय-कालडी - जखानिया-श्रीबालाजी-बुकर्म सोता-बायाजी का रोहिड़ा-सेवड़ी-बोरडी का कुआं-पिंपासर-रोहिणी सड़क का चौड़ाईकरण व सुदृढ़ीकरण (96 किमी.)-नागौर	52 करोड़ रुपये
152.	NH-62 जीएसएस से SH-87 से NH-62 खींवसर बाईपास (15 किमी.)-नागौर	65 करोड़ रुपये
153.	लसाड़िया से फिला, शेषपुर मोड़ से घोलागिरखेड़ा महादेव जी तक सड़क का डामरीकरण (37 किमी.) (धरियावद)-प्रतापगढ़	40 करोड़ रुपये
154.	छोटीसादड़ी से गणेशपुरा रोड़ वाया कण्डेला मार्ग (3 किमी.) (निम्बाहेड़ा)-प्रतापगढ़	2 करोड़ 36 लाख रुपये
155.	देवाणा से बडारड़ा नदी पर कॉजवे मय सड़क (2.5 किमी.) - राजसमन्द	3 करोड़ रुपये
156.	चारभुजा सेवन्त्री सड़क डामरीकरण (10 किमी.) (कुम्भलगढ़) - राजसमन्द	6 करोड़ रुपये
157.	बड़ारडा पुठिया से सायड़ा भील बस्ती नहर होते हुए फरारा महादेव तक सड़क का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ाईकरण (6 किमी.) - राजसमन्द	7 करोड़ 80 लाख रुपये
158.	सलूम्बर से अग्गड तक सड़क का डामरीकरण व उन्नयन (20 किमी.) - सलूम्बर	25 करोड़ रुपये
159.	हमीर सर्किल से गणेशधाम सर्किल तक सड़क का उन्नयन - सवाईमाधोपुर	15 करोड़ रुपये
160.	पांचोलास से फलौदी सड़क मार्ग एवं आरसीसी कल्वर्ट ऑन कल्याणपुरा नाला विद् अप्रोच सीसी रोड (14.5 किमी.)	14 करोड़ 50 लाख रुपये

	(खण्डार) - सवाईमाधोपुर	
161.	खण्डार से सांवटा वाया नायपुर तलावड़ा ODR 18 सड़क (17 किमी.) (खण्डार)- सवाईमाधोपुर	18 करोड़ रुपये
162.	शहरी व ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों के निर्माण कार्य एवं उन्नयन-सवाई माधोपुर	20 करोड़ रुपये
163.	ईसरदा से माधोराजपुरा वाया सोलपुर तक सड़क (8.5 किमी.) (खण्डार)- सवाईमाधोपुर	8 करोड़ रुपये
164.	गुर्जरबडोदा मोड़ (श्योसिंहपुरा से सुरगढ़ तक) वाया नेहरी के बालाजी तक (नदी ब्रिज 400 मीटर) (3.5 किमी.)- सवाई माधोपुर	5 करोड़ रुपये
165.	रिवाली (MDR 219) से वाया घोलादांता ढाणी तक सड़क का चौड़ाईकरण (3.5 किमी.)- सवाई माधोपुर	2 करोड़ 50 लाख रुपये
166.	मेगा हाईवे (MDR 247) गढ़मोरा रोड से MDR-219 भांवरा तक वाया राघोपुरा, मीनाकोलेता नानेटाघाटी सड़क का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण (13 किमी.) सवाईमाधोपुर	19 करोड़ रुपये
167.	पालावास-तासर-आडा दरा तक सड़क (3.5 किमी.) (धोद) - सीकर	1 करोड़ 50 लाख रुपये
168.	सामोता की ढाणी (कोटडी लुहारवास) से आभावास वाया भैरा, सुखपुरा, गोकुल का बास, सुरपूरा, झुफा, जानकीपुरा, गोल्डी जोहडी, विजयपुरा, साथलिया, लाखनी, तपीपल्या सड़क (66 किमी.) (खण्डेला)-सीकर	35 करोड़ रुपये
169.	अजीतगढ़ से रींगस तक (वाया-श्रीमाधोपुर) टू लेन सड़क with paved shoulder (36 किमी.) (श्रीमाधोपुर)- सीकर	50 करोड़ रुपये
170.	नेछवा मुख्य स्टेण्ड से उपखण्ड कार्यालय नेछवा एवं बालाजी स्टेण्ड तक सड़क (4.50 किमी.) - सीकर	4 करोड़ 50 लाख रुपये
171.	बीटी सड़क खुरी छोटी (NH-52) से सांवलोदा लाडखानी तक सड़क कार्य (5.5 किमी.) - सीकर	1 करोड़ 65 लाख रुपये
172.	पालावास से श्यामपुरा के मध्य तेतरवालों की ढाणी के श्मशान से श्यामपुरा जीजीपी तक मिसिंग लिंक सड़क (2.5 किमी.) (घोद)-सीकर	1 करोड़ रुपये
173.	कृष्णागंज-सियाकरा-सानपुर सड़क मय पुलिया का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (16 किमी.) - सिरोही	21 करोड़ रुपये
174.	बागसिन-वान-कैलाशनगर सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण (18 किमी.)-सिरोही	18 करोड़ रुपये

175.	गंगकेनाल के साधुवाली हैडवर्क से शिवपुर हैडवर्क तक डामर सड़क (10 किमी.) (सादुलशहर)-श्रीगंगानगर	7 करोड़ रुपये
176.	SH-117 से जेबाडिया मय वेन्टेड कॉजवे (2.05 किमी.) (निवाई)-टोंक	5 करोड़ रुपये
177.	SH-37A पर गुर्जर की थड़ी से रिण्डल्या रामपुरा-पन्द्रोडा होते हुए बावड़ी तक सड़क (20.5 किमी.) (मालपुरा) - टोंक	47 करोड़ 50 लाख रुपये
178.	दहलोद दतवास से सीपुरा, कुरवाडा से लुनेरा आश्रम, बड़ी ढाणी लुनेरा से गोरधनपुरा, सीपुरा से केरली धाम, श्रीरामपुरा से केरली धाम, चुराडा से जैतपुरा तक सड़क (10.90 किमी.) (निवाई)-टोंक	9 करोड़ 57 लाख रुपये
179.	MDR 36, भारोड़ी से पलानाकलां वाया छोटी खेड़ी मोटी खेड़ी होते हुए मानसोल NH तक सड़क (8 किमी.) (मावली)-उदयपुर	16 करोड़ रुपये
180.	सिरवल से सुमेरपुर वाया भीमाणा-दानवरली-बीजापुर सुमेरपुर सड़क MDR-413 का सुदृढ़ीकरण व चौड़ाईकरण (11 किमी.) (कोटड़ा)-उदयपुर	19 करोड़ 80 लाख रुपये
181.	भीण्डर से पाणुन्द फिला, भमरासिया से कुराबड MDR सड़क का पुनर्निर्माण व चौड़ाईकरण (35 किमी.) (वल्लभनगर)-उदयपुर	70 करोड़ रुपये

II. State Highways की DPR का कार्य-

क्र.सं.	State Highways/सड़कें	लागत
1.	सांचोर (NH-15) रानीवाड़ा-मण्डार-आबू रोड (SH-11) (107 किमी.)	1 करोड़ 60 लाख रुपये
2.	सलूम्बर-बांसवाड़ा (SH-32) का अनुभाग (93 किमी.)	1 करोड़ 40 लाख रुपये
3.	रोहिट (NH-65 के जंक्शन) से आहोर (NH-325 के जंक्शन) (SH-64) (82 किमी.)	1 करोड़ 20 लाख रुपये
4.	SH-02 का फागी से दूदू अनुभाग (40 किमी.)	60 लाख रुपये
5.	विजयनगर (NH-48 के जंक्शन) से ब्यावर (NH-58 के जंक्शन) SH-39 का अनुभाग (42 किमी.)	60 लाख रुपये

III. ROB/RUB/ Flyover/Elevated Road सम्बन्धी कार्य-

क्र सं.	ROB/RUB/Flyover/Elevated Road निर्माण	लागत
1.	सीकर में फतेहपुर सड़क से नवलगढ़ सड़क तक 6.5 किमी. फोरलेन सड़क व 2 रेलवे ओवरब्रिज का	250 करोड रुपये

	निर्माण	
2.	श्रीगंगानगर में LC-119 पर RUB का कार्य	30 करोड़ रुपये
3.	जयपुर में ओटीएस चौराहे पर Flyover	80 करोड़ रुपये
4.	रिद्धि-सिद्धि चौराहे पर Elevated Road-जयपुर	185 करोड रुपये
5.	अपैक्स सर्किल से जगतपुरा बालाजी तिराहा तक Elevated Road (2.40 किमी.)- जयपुर	130 करोड़ रुपये
6.	झोटवाड़ा RoB से खातीपुरा RoB तक Elevated Road-जयपुर	65 करोड़ रुपये
7.	जोधपुर में डीजल शेड लोको रोड से सालावास रोड की तरफ चौराहे पर Flyover की DPR का कार्य	1 करोड़ 50 लाख रुपये
8.	उदयपुर में बलिचा तिराहे पर फोरलेन फ्लाईओवर का निर्माण कार्य	50 करोड़ रुपये
9.	नारायण सर्किल से पुराना रामगढ़ मोड़ तक, खानियां से बगराना आगरा रोड तथा अरण्य भवन से ट्रांसपोर्ट नगर तक एलिवेटेड रोड की DPR का कार्य-जयपुर	3 करोड़ 50 लाख रुपये
10.	NH 27 अन्ता से सीसवाली तिराहे तक 4 लेन सड़क मय ROB का सुदृढ़ीकरण (अन्ता टाउन पोर्शन)-बारां	65 करोड़ रुपये
11.	चूना फाटक पर RUB मय LA हनुमानगढ़	35 करोड़ रुपये

IV. Bridges निर्माण कार्य-

क्र.सं.	उच्च स्तरीय पुल	लागत
1.	कुराड-ढोटी-कंदाफल खेड़ली-आमली-मंडाप-सांगोद सड़क (MDR-178) के पास कालीसिंध नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण (सांगोद)-कोटा	70 करोड़ रुपये
2.	घटियावली से खोर सड़क (3 किमी.) के मध्य गंभीरी नदी पर पुलिया निर्माण-चित्तौड़गढ़	27 करोड़ रुपये
3.	जालोर-रेवतड़ा-सायला-बागोड़ा ब्रिज किमी. 33/00 में (SH 16B)-जालोर	25 करोड़ रुपये
4.	सम्पर्क सड़क काद्गन के किमी. 3/800 अरू नदी पर पुलिया निर्माण कार्य (सांगोद)-कोटा	4 करोड़ 50 लाख रुपये

V. शहरी क्षेत्रों में सुनियोजित विकास के कार्य-

क्र.सं.	विकास कार्यों का विवरण	लागत

1.	सीकर के सबलपुरा स्टैण्ड से भढ़ाढर तिराहे तक विद्यमान टू-लेन सड़क से फोरलेन सड़क निर्माण एवं अन्य कार्य (5 किमी.)	15 करोड़ रुपये
2.	जैसलमेर में अम्बेडकर चौराहे से जी.एस.एस. जोधपुर सड़क व अम्बेडकर चौराहे से यूनियन चौराहे तक सड़क के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य	25 करोड़ रुपये
3.	भीलवाड़ा शहर में सीए सर्किल से पटेल नगर विस्तार योजना के सेक्टर-09, मुख्य सड़क का नवीनीकरण कार्य	1 करोड़ 45 लाख रुपये
4.	भीलवाड़ा में रिंग रोड बालाजी से गर्ग डिपार्टमेंटल स्टोर होते हुए सीए सर्किल तक सड़क का नवीनीकरण कार्य (पटेल नगर योजना)	65 लाख रुपये
5.	भीलवाड़ा में पटेल नगर योजना सेक्टर-07 में बापूनगर एवं पटेल नगर को जोड़ने वाली सड़क का नवीनीकरण कार्य	74 लाख रुपये
6.	सांगानेर, जगतपुरा, झोटवाड़ा, घाट की गूणी की सड़कों के उन्नयन सम्बन्धी कार्य-जयपुर	135 करोड़ रुपये
7.	भरतपुर में सूरजपोल चौराहे से मडरपुर चौराहे तक डामरीकरण	4 करोड़ रुपये
8.	भरतपुर विकास प्राधिकरण की योजना संख्या 13 व 14 में सड़कों/पार्कों एवं अन्य विकास कार्य	95 करोड़ रुपये
9.	इन्द्रोली से उदाका तक दिल्ली बाईपास सड़क (कामा बाईपास का DPR का कार्य) (10 किमी.) (कामां) डीग	50 लाख रुपये
10.	बोहेडा एवं निकुम्भ में बाईपास सड़क (6.50 किमी.) (बड़ीसादड़ी)-चित्तौड़गढ़	6 करोड़ 75 लाख रुपये
11.	रावतसर में बाईपास का DPR कार्य (10 किमी.) (पीलीबंगा) - हनुमानगढ़	80 लाख रुपये
12.	बाझडोली बाईपास (3 किमी.) (सूरजगढ़) - झुंझुनूं	1 करोड़ 94 लाख रुपये
13.	टोडारायसिंह बाईपास की DPR (7.50 किमी.) (मालपुरा) - टोंक	50 लाख रुपये
14.	गंगरार बाईपास व बेगूं बाईपास निर्माण (18 किमी.) (बेगूं) - चित्तौड़गढ़	51 करोड़ 5 लाख रुपये
15.	रिंग रोड निर्माण (6 किमी.) (कुचामन सिटी)-	20 करोड़ रुपये

	डीडवाना - कुचामन	
16.	मेगा हाइवे बाईपास से भांडियावास एवं भांडियावास से बालोतरा तक रिंग रोड़ निर्माण की DPR (11.5 किमी.) (पचपदरा)-बाड़मेर	3 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 5

पैरा संख्या 28 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	निर्माण कार्यों का विवरण	लागत
1.	पूनम स्टेडियम, जैसलमेर में भूमिगत पार्किंग, किला पार्किंग तक हेरिटेज वॉक-वे एवं सौन्दर्याकरण के कार्य	70 करोड़ रुपये
2.	भरतपुर में शीशम तिराहे से काली बगीची चौराहे तक बी.टी. सड़क चौड़ाईकरण/सुदृढ़ीकरण एवं ड्रेनेज का निर्माण कार्य	13 करोड़ रुपये
3.	भरतपुर में हीरादास चौराहे से काली बगीची चौराहे तक बी.टी./सी. सी. सड़क चौड़ाईकरण/ सुदृढ़ीकरण एवं ड्रेनेज का निर्माण कार्य	17 करोड़ 83 लाख रुपये
4.	स्वर्ण जयन्ती पार्क (विद्याधर नगर)- जयपुर को Oxygen Zone के रूप में विकसित किया जायेगा तथा रामगिरी पहाड़ी बड़गाँव, उदयपुर को Oxygen Hub बनाते हुए पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु DPR	15 करोड़ रुपये
5.	भरतपुर में SPZ योजना में विद्युतीकरण का कार्य	25 करोड़ रुपये
6.	प्रतापनगर आवासीय योजना, जयपुर में 400 Flats की योजना	325 करोड़ रुपये
7.	इंदिरा गांधी नगर आवासीय योजना, जयपुर में 144 Flats की योजना	50 करोड़ रुपये
8.	मानसरोवर आवासीय योजना, जयपुर में 160 Flats की योजना	35 करोड़ रुपये
9.	पानेरियों की मादड़ी आवासीय योजना, उदयपुर में 200 Flats की योजना	20 करोड़ रुपये
10.	जोधपुर में विवेक विहार पाली रोड पर ट्रांसपोर्ट हब का निर्माण	50 करोड़ रुपये
11.	द्रव्यवती नदी का पर्यटन की दृष्टि से upgradation कार्य-जयपुर	50 करोड़ रुपये
12.	सार्वजनिक पुस्तकालय का उन्नयन, शहर के लिए प्रवेश द्वार/प्लाजा का कार्य-अजमेर	10 करोड़ रुपये
13.	अनूपगढ़-श्रीगंगानगर; शाहपुरा-भीलवाड़ा;	14 करोड़ रुपये

	गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर में ऑडिटोरियम का निर्माण तथा कुचामन सिटी-डीडवाना कुचामन में सिटी पार्क	
14.	बयाना-भरतपुरः अटरू-बारां; सलूम्बरः पुष्कर, केकड़ी-अजमेर; हनुमानगढ़, गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर; कैलादेवी-करौली; सिवाना, बालोतरा, पचपदरा बालोतरा; थानागाजी अलवर; डीग, जुरहेड़ा-डीग; बांदीकुई-दौसा; बगरू, शाहपुरा-जयपुरः सांचौर-जालोर; खींवसर-नागौर; कोटपूतली, विराटनगर-कोटपूतली बहरोड़ः मुण्डावर खैरथल तिजारा; दीगोद-कोटा; सांडेराव, सोजत-पाली; आबूरोड, शिवगंज-सिरोही; कोटड़ा, झाडोल-उदयपुर; लाडनूं-डीडवाना कुचामन; बूंदी में Roadways Bus Stands सम्बन्धी कार्य	30 करोड़ रुपये
15.	अलवर शहर में हनुमान चौराहे के पास PPP पर नया बस स्टैण्ड बनाने का कार्य	60 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 6
पैरा संख्या 29 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	कार्य का विवरण	लागत
1.	Solid Waste सम्बन्धी कार्य- - समस्त संभाग मुख्यालयों के साथ ही चाकसू फुलेरा, दौसा, अजीतगढ़, बिलाड़ा, केशोरायपाटन सहित 32 शहरों में Solid Waste Management सम्बन्धी कार्य - नगरीय निकायों के dumping sites पर पड़े लगभग 55 लाख टन पुराने कचरे का निस्तारण - राज्य की सभी 52 नगर परिषदों में घर-घर कचरा संग्रहण वाहनों पर Vehicle Tracking System लगाने तथा Control Command Centre का निर्माण कर उन्हें राज्य स्तरीय Command Centre से जोड़ा जाना - नगरीय निकायों में ठोस कचरा संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण हेतु GCC model पर 4 हजार हूपर - आगामी 3 वर्षों में नवगठित 65 नगरीय निकायों में waste processing plants एवं FSTP की स्थापना - 30 नगर परिषदों में Mechanised Transfer Stations की स्थापना - जिला स्तर की 41 नगरीय निकायों में मृत पशुओं के अपशिष्ट के निस्तारण की व्यवस्था हेतु Incinerator Plants एवं Boiler Plants, Viability Gap Funding के आधार पर निर्माण - अलवर, पाली, भीलवाड़ा, दौसा, हनुमानगढ़ व झुंझुनूं में निर्मित /निर्माणाधीन Solid Waste Processing Plants, जिनसे कम्पोस्ट/खाद का उत्पादन होता है, का संचालन	3 हजार 650 करोड़ रुपये
2.	Waste Water Management तथा Treated Water सम्बन्धी कार्य- - 296 शहरों में Waste Water Management तथा इससे Treated Water का उद्योगों, कृषि आदि में पुनः उपयोग - कुम्हेर, सांगोद, श्रीगंगानगर, बीकानेर 65 नगरीय निकायों के जल भराव क्षेत्रों में drainage एवं grey water treatment का कार्य	4 हजार 230 करोड़ रुपये

	- जयपुर में मास्टर drainage का कार्य - डेलावास STP, जयपुर के उपचारित जल को उपयोग में लेने का कार्य (HAM-Hybrid Annuity Model) पर - हिंगौनिया गौशाला-जयपुर को 20 MLD आवश्यक पानी STP के उपचारित जल से पहुंचाने का कार्य	
3.	Sewerage एवं Drainage सम्बन्धी कार्य- - जयपुर, अजमेर, विराटनगर, बयाना, कामां, बांदीकुई, बसवा, सूरजगढ़, नाथद्वारा, लक्ष्मणगढ़-अलवर, कोटा, खींवसर, सांचौर, पुष्कर, हनुमानगढ़ व संभागीय मुख्यालयों सहित 75 शहरों में Sewerage Gap को चरणबद्ध रूप से कवर करने का कार्य - चूरू शहर में Sewerage Treatment एवं Storm Water Drainage Project तथा STP निर्माण कार्य -शहरों के आधारभूत ढांचे व सफाई व्यवस्था को बनाये रखने की दृष्टि से 2 हजार किलोमीटर पुरानी Sewerage Lines का आगामी 4 वर्षों में rehabilitation का कार्य - सीवर लाइनों के अन्दर Closed Circuit Television on Survey (CCTV) के द्वारा Condition Assessment करवाकर क्षतिग्रस्त भाग को बिना सड़क की खुदाई करे Trenchless method से बदलने का कार्य; प्रथम चरण में जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बीकानेर व भरतपुर में कार्य - सीवरेज/मेन हॉल सफाई में होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु 100 अत्याधुनिक Robotic three-in-one सीवरेज सफाई मशीनें उपलब्ध कराना, - सफाई मित्रों की सुरक्षा हेतु Digital Gas Detector उपकरण - नगर निगमों में चरणबद्ध रूप से Super Sucker Machines - सीकर के पिपराली चौराहे के क्षेत्र, झुंझुनूं बाईपास के दोनों ओर, गोकुलपुरा, सांवली चौराहे के दोनों ओर, धोद चौराहा एवं पालवास चौराहे के आस-पास क्षेत्र में सीवरेज एवं बरसाती पानी निकासी का कार्य - अलवर न्यास योजना अरावली विहार फेज प्रथम, द्वितीय	3 हजार 450 करोड़ रुपये

	एवं अम्बेडकर नगर ब्लॉक एम.एन. में सीवर लाइन एवं नाले का निर्माण कार्य - नवरत्न कॉलोनी, उदयपुर में सीवरेज लाईन एवं कनेक्शन का कार्य - भरतपुर-मथुरा बाईपास पर सेवर तिराहे से कंजौली तक नाली निर्माण कार्य (7 किमी.)- भरतपुर - अलवर में 200 फीट बाइपास, तिजारा रोड एवं दिल्ली रोड पर नाला निर्माण, ड्रेनेज का कार्य	
4.	अन्य विविध कार्य- - NCR और NCAP शहरों के लिए Anti smog gun, Smog Tower on Heavy Traffic Area, Gobbler Machine, Mechanical Roads Sweeper, Air Quality Monitoring Station सम्बन्धी कार्य - वायु प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण व वायु गुणवत्ता के सुधार हेतु प्रदेश के 50 शहरी क्षेत्रों में Water Sprinkler, Mechanical Sweepers उपलब्ध करवाये जाने तथा Plantation के कार्य - पाली, बालोतरा, जोधपुर, भिवाड़ी और भीलवाड़ा स्थित प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रदूषित जल एवं hazardous chemicals के अवैध निर्वहन और Dumping की निगरानी के लिए IoT based system - जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर, उदयपुर, चूरू, पाली सहित 14 उच्च शहरीकृत शहरों एवं इनके 42 Satellite Towns में पर्यटन, Heritage, Command Control Centre व बाढ़ प्रबंधन सम्बन्धी कार्य - प्रदेश के समस्त शहरों में 50 हजार Street Lights लगवायी जायेंगी।	720 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 7

पैरा संख्या 33 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	औद्योगिक पार्क/क्षेत्र एवं आधारभूत कार्य
1.	Eco Crafting Opportunity/Weaving a Sustainable Future/Green Textile के तहत हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए आकोला-चित्तौड़गढ़ में Hub का निर्माण (5 करोड़ रुपये)
2.	कोटा में Toy Park, निम्बाहेडा-चित्तौड़गढ़ व बूंदी में Stone Parks, सोनियाणा-चित्तौड़गढ़ में Ceramic Park, DMIC के अन्तर्गत Pharma Park की स्थापना, भीलवाड़ा में Textile Park का विस्तार तथा सांगानेर-जयपुर में Block Printing Zone की स्थापना
3.	नवीन औद्योगिक क्षेत्र केकड़ी अजमेर, कठूमर अलवर, रूपवास (बयाना). वैर-भरतपुर, पीपलूद व पंडेर (शाहपुरा), रेडवास-भीलवाड़ा, श्रीडूंगरगढ़-बीकानेर, समलेटी (महुवा) दौसा, मोहनपुरा (फागी), बांसखोह (बरसी) जयपुर, सरनाऊ (सांचौर) जालोर, गोपालपुरा-कोटा, जैतारण ब्यावर, सोजत पाली, दत्तवास (निवाई)-टॉक, डीडवाना-डीडवाना कुचामन, टोडाभीम करौली

परिशिष्ट 8
पैरा संख्या 36 में उल्लिखित सूची

क्र.सं	पर्यटन विकास सम्बन्धी कार्य
1.	Heritage Tourism को बढ़ावा देने के उद्देश्य से Iconic Tourist Destinations के रूप में जैसलमेर किला, शेरगढ़ किला-बारां, खण्डार किला-सवाई माधोपुर, नाहरगढ़ एवं आमेर-जयपुर, आभानेरी-दौसा, किशोरी महल-भरतपुर सहित 10 Sites का विकास
2.	प्रदेश में Night Tourism को बढ़ावा देने हेतु जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, बीकानेर एवं अलवर के प्रमुख पर्यटन स्थलों एवं Heritage स्मारकों पर आवश्यक आधारभूत संरचना के उन्नयन के साथ विभिन्न गतिविधियों का आयोजन (100 करोड़ रुपये)
3.	शेखावाटी क्षेत्र में स्थित ऐतिहासिक कलात्मक हवेलियों के संरक्षण हेतु शेखावाटी हवेली संरक्षण योजना एवं Heritage Walk
4.	कायलाना झील, जोधपुर में Musical Fountain, Water Screen, Light and Sound Show सम्बन्धी कार्य (11 करोड़ 50 लाख रुपये)
5.	प्रदेश में Water Sports हेतु कोटा बैराज, बीसलपुर, जयसमंद, सिलीसेढ़, पिछोला, आनासागर तथा Desert Adventure Tourism की दृष्टि से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर एवं बीकानेर में PPP Mode पर आवश्यक कार्य
6.	प्रदेश को Wedding Destination के रूप में नयी ऊँचाइयों तक ले जाने के लिए आवश्यक Infrastructure तथा Connectivity (125 करोड़ रुपये)
7.	पर्यटन तथा कला व संस्कृति के क्षेत्र में Travel Mart की अहम भूमिका को देखते हुए जयपुर के अलावा उदयपुर एवं जोधपुर में भी Travel Marts का आयोजन
8.	लोक गायकों एवं संगीतकारों हेतु बीकानेर में गवरी देवी कला केन्द्र की स्थापना
9.	जयपुर स्थित अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के उन्नयन हेतु 25 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।
10.	प्रदेश के गांवों एवं उनके मंदिरों के अतुलनीय इतिहास को रिकॉर्ड कर नागरिकों तक पहुंचाने के लिए संस्कृति पोर्टल
11.	Hospitality के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं को आवश्यक Skill Upgradation की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए संभाग स्तर पर Hospitality Skill Centres (35 करोड़ रुपये)
12.	विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र-जयपुर में JECC की तर्ज पर Concert and Convention MICE Centre तथा अजमेर में Convention Hall का निर्माण
13.	मूसी महारानी की छतरी-अलवर, आमेर/जयपुर परकोटा क्षेत्र की बावडियों का

	पुनरुद्धार व जीर्णोद्धार का कार्य-जयपुर, रणथम्भौर प्रवेश द्वार का सौन्दर्यीकरण व जोगीमहल गेट पर पार्किंग, शिल्पग्राम की स्थापना-सवाई माधोपुर
14.	वरुण सागर झील व चौरसियावास तालाब-अजमेर, जैतसागर झील व नवल सागर झील-बूंदी, सूरसागर झील-बीकानेर, प्रेम सागर सरोवर (आसींद)-भीलवाड़ा, जयनिवास उद्यान, पौण्ड्रिक उद्यान, ताल कटोरा-जयपुर, कुशाल झील (गंगापुरसिटी)-सवाई माधोपुर के सौन्दर्यीकरण, जीर्णोद्धार व अन्य विकास कार्य

II. **धार्मिक स्थलों पर आधारभूत संरचना सम्बन्धी कार्य**

1.	पुष्कर-अजमेर, रणथम्भौर त्रिनेत्र गणेश जी-सवाई माधोपुर, जीण माता-सीकर, तनोट माता मंदिर व रामदेवरा-जैसलमेर, दाऊ मदनमोहन-भरतपुर व देशनोक-बीकानेर आदि धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं हेतु विभिन्न सुविधायें (95 करोड़ रुपये)
2.	बेणेश्वर धाम, रामेश्वर घाट एवं बीगोद संगम को त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित किये जाने सम्बन्धी कार्य (65 करोड़ रुपये)
3.	सांगानेर-जयपुर में स्थित पुरातनकालीन मंदिरों जैसे-सांगा बाबा मंदिर, त्रिपोलिया बालाजी, संघी जी जैन मंदिर को धार्मिक पर्यटन सर्किट में शामिल कर मंदिर क्षेत्र में आधारभूत एवं यात्री विकास कार्य (50 करोड़ रुपये)
4.	श्रीमथुराधीश जी मंदिर-कोटा, मेहंदीपुर बालाजी मन्दिर- दौसा में आने वाले श्रद्धालुओं तथा आसपास के क्षेत्रों के लोगों को अत्यधिक भीड़ तथा यातायात सम्बन्धी समस्या से राहत दिलाने के लिए वैकल्पिक मार्ग हेतु Feasibility Report एवं DPR
5.	गरबा जी मंदिर, लालदास जी मन्दिर-अलवर, रामदेवजी की जन्मस्थली रामदेरिया काश्मीर-बाड़मेर, लक्ष्मीनाथ जी मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, हनुमान मंदिर, शीतला माता मंदिर-बीकानेर, श्री बालानंद जी-भरतपुर, मालासेरी-भीलवाड़ा, वामनदेव मंदिर (मनोहरपुर), खेड़ापति बालाजी मंदिर, भोमियाजी मंदिर (माधोराजपुरा)-जयपुर, दलहनपुर मठ मंदिर एवं छतरियां (मनोहरथाना)- झालावाड, नाडा बालाजी मन्दिर, पगलियाधाम मंदिर (नावा)- डीडवाना कुचामन, रेहनावाली माताजी एवं लाठ बाली माता मंदिर (राजाखेडा)-धौलपुर, साड़ू माताजी (ताम्बेश्वर) की बावडी, सवाई भोज मंदिर, गढ़गोठा, वडनगर, श्री अन्नधन जी (भादरा) -हनुमानगढ़, डोवा रामजी महाराज तीर्थ बालरई (रानी)-पाली, भूतेश्वर नाथ मन्दिर-टोडारायसिंह, सिंधौलिया माताजी मंदिर (मालपुरा), बद्रीनाथ मंदिर (निवाई)-टोंक, श्री तेजानन्द बिहारी जी -सलूम्बर, माणा बाबा धाम लाखणी व सुन्दरदास धाम बामरडा (खण्डेला)-सीकर, सारणेश्वर महादेव मंदिर, चामुण्डा माता जी मंदिर-सिरोही, श्री जगत शिरोमणि जी-उदयपुर के धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य (57 करोड़ रुपये)
6.	पैनोरमा-बैंगटी-फलौदी में हड़बूजी, रेवासा धाम-सीकर

7.	गोगाजी मंदिर, गोगामेड़ी-हनुमानगढ़, श्रीमहावीर जी मंदिर में प्रतिवर्ष आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था एवं सुविधा के दृष्टिगत Barricading व शेड निर्माण सहित विभिन्न कार्य
8.	600 मंदिरों पर दीपावली, होली एवं रामनवमी जैसे प्रमुख त्योहारों पर विशेष साज-सज्जा व आरती के कार्यक्रमों का आयोजन (13) करोड़ रुपये)

परिशिष्ट 9

पैरा संख्या 43 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	पर्यटन सुविधाओं सम्बन्धी कार्य
1.	केन्द्र सरकार की महती उड़ान योजना के अन्तर्गत पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों को हवाई सेवा से जोड़ा जाना प्रस्तावित है।
2.	कोटा Airport के निकट Aero City
3.	हमीरगढ़-भीलवाडा, झुंझुनूं, तलवाड़ा-बांसवाड़ा, परिहारा-चूरू, कुम्हेर-डीग, प्रतापगढ़, नून-जालोर, फलोदी, सिरोही, चकचैनपुरा-सवाई माधोपुर, कोलाना-झालावाड, तारपुरा-सीकर एवं विश्नोदा-धौलपुर सहित 29 हवाई पट्टियों की मरम्मत, रखरखाव एवं उन्नयन कर चरणबद्ध रूप से बड़े हवाई जहाज उतरने के योग्य बनाया जायेगा। (105 करोड़ रुपये)
4.	प्रतापगढ़, झालावाड़ एवं झुंझुनूं में Flying Training Organisation (FTO) माउंट आबू-सिरोही में Aero Sports Activities शुरू की जायेगी।
5.	जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में Hop-on Hop-off बस सेवा

परिशिष्ट 10

पैरा संख्या 50 में उल्लिखित सूची

I. तकनीकी एवं अभियांत्रिकी संस्थान सम्बन्धी कार्य

क्र.सं.	ITIs/ पॉलिटेक्निक/अभियांत्रिकी महाविद्यालय
1.	**नवीन ITIs-** भरतपुर, मूंड़वां-नागौर, बड़ौद-कोटपूतली बहरोड़, कापरेन-बूंदी, नीमकाथाना - सीकर, झोटवाड़ा-जयपुर, सुमेरपुर-पाली, मोडक-कोटा **ITIs का आधुनिकीकरण-** 36 ITIs के नवीनीकरण, उपकरण, मशीनरी तथा सुदृढ़ीकरण (39 करोड़ रुपये) **ITIs में नवीन Trades-** औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर (ITI) में Additive Manufacturing Technician (3D Printing), महिला आईटीआई, जयपुर में Multimedia, Animation and Special Effects तथा आईटीआई भिवाड़ी, बालोतरा, धौलपुर, प्रतापगढ़, सूरतगढ़, नागौर एवं सांगोद में Mechanic, Electric Vehicle
2.	**नवीन पॉलिटेक्निक महाविद्यालय**- टपूकड़ा-खैरथल तिजारा, सीकर एवं भीलवाड़ा **पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नवीन Branches-** धौलपुर, सिरोही एवं बाड़मेर में सिविल; हनुमानगढ़ तथा अजमेर (महिला) में कम्प्यूटर साइंस, झालावाड़ में केमिकल तथा चूरू में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ब्रांच **पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में नवीन सीट क्षमता वृद्धि** - पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, झालावाड़ में Electrical, बाड़मेर में Chemical, अजमेर में Automobile, Instrumentation, Printing, जयपुर में RAC. बागीदोरा व पाली में Mechanical तथा जालोर में Mechanical व Civil Branch की सीटों में वृद्धि **पॉलिटेक्निक तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की मरम्मत एवं आधुनिकीकरण-** पॉलिटेक्निक तथा अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की मरम्मत, आधुनिकीकरण, upgradation, खेल Infrastructure एवं अन्य सुविधायें विकसित करने हेतु प्रथम चरण में 40 करोड़ रुपये का व्यय

II. उच्च एवं स्कूली शिक्षण संस्थान सम्बन्धी कार्य

क्र.सं.	राजकीय महाविद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय/विद्यालय
1.	**नवीन महाविद्यालय**-कुम्हेर, खोह-डीग, केरू (लूणी)-जोधपुर, अकलेरा-झालावाड़, गोटन-नागौर, धोद, श्रीमाधोपुर सीकर, कानोड़-उदयपुर, सांगानेर-जयपुर, घड़साना-श्रीगंगानगर, जसवंतपुरा-जालोर **कन्या महाविद्यालय**-बिजयनगर, मसूदा ब्यावर, तिजारा खैरथल तिजारा, डाबी-बूंदी, कोटखावदा-जयपुर, कैथून, सुकैत कोटा, सोजत रोड़-पाली, आबू रोड-सिरोही **कृषि महाविद्यालय**-मांडलगढ़-भीलवाड़ा, गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर, **महाविद्यालय भवन निर्माण-** भिनाय- अजमेर, रामगढ़-अलवर, डूंगरपुर
2.	**UG से PG महाविद्यालय में क्रमोन्नयन-** बयाना-भरतपुर, आसींद-भीलवाड़ा,

	महुवा-दौसा, जयसिंहपुरा खोर-जयपुर, नैनवां-बूंदी
3.	**महाविद्यालयों में नवीन संकाय/विषय-** विज्ञान संकाय-जहाजपुर, आसींद-भीलवाड़ा, कुचेरा-नागौर, वाणिज्य संकाय-भीम-राजसमंद, नवीन विषय-जायल-नागौर, सराड़ा-सलूम्बर, शाहपुरा-जयपुर, रेवदर-सिरोही, बाली-पाली,
4.	जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में वैदिक गुरुकुल एवं वैदिक पर्यटन केन्द्रों की स्थापना
5.	225 प्रवेशिका विद्यालयों का वृरिष्ठ उपाध्याय में क्रमोन्नयन 17 शास्त्री संस्कृत महाविद्यालयों का आचार्य स्तर पर क्रमोन्नयन
6.	मिर्जेवाला-श्रीगंगानगर में सैनिक स्कूल तथा अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना
7.	**विद्यालयों का क्रमोन्नयन**-: 50 प्राथमिक विद्यालयों का 8वीं कक्षा तक, 100 विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में upgradation
8.	**विद्यालयों में नवीन विषय/संकाय-** 100 विद्यालयों में नवीन विषय/संकाय
9.	**विद्यालयों में आधारभूत संरचना के कार्य-** Class-rooms, Labs, Computer Lab एवं toilets का निर्माण (225 करोड़ रुपये) कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में डाइनिंग हॉल व्यवस्था (65 करोड़ रुपये) विद्यार्थियों की सुविधा हेतु लगभग 4 हजार नव क्रमोन्नत विद्यालयों में फर्नीचर छात्र-छात्राओं को सुरक्षित वातावरण देने की दृष्टि से राज्य के 15 हजार विद्यालयों में CCTV कैमरों की स्थापना (75 करोड़ रुपये)
10.	**विद्यालयों के भवनों का निर्माण/मरम्मत-** 175 भवनविहीन/जर्जर विद्यालयों के नवीन भवनों का निर्माण (200 करोड़ रुपये) 2 हजार विद्यालयों के भवनों की मरम्मत (175 करोड़ रुपये)

परिशिष्ट 11

पैरा संख्या 52 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम/विवरण
1.	**खेल मैदान/Gyms/खेल स्टेडियम**-- 5 हजार से अधिक आबादी वाली 3 हजार 500 ग्राम पंचायतों में 35 करोड़ रुपये व्यय कर Open Gyms एवं खेल मैदान बालोतरा, कोलायत-बीकानेर, बागीदौरा-बांसवाड़ा, आसींद-भीलवाड़ा, शेरगढ़- जोधपुर, सपोटरा-करौली, मेड़ता, खींवसर-नागौर, लोहावट-फलौदी, धरियावद- प्रतापगढ़, तख्तगढ़-पाली, सलूम्बर, सांचौर-जालोर, गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर में खेल स्टेडियम
2.	**Sports Schools/Complex-** कोटा, बीकानेर, उदयपुर, भरतपुर व अजमेर संभाग में Para Sports के लिए Special Sports Complex, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, पाली, चूरू शैक्षिक संभागों में Sports Schools सम्बन्धी कार्य सार्दुल Sports School, बीकानेर के सुदृढ़ीकरण, नवीन छात्रावास निर्माण के साथ शूटिंग एवं तीरंदाजी प्रारम्भ
3.	**Academy/Range/Rings**- SMS Stadium, जयपुर में Badminton Academy तथा उदयपुर में Lacrosse Academy, जयपुर में Shooting Range मय आवासीय सुविधा तथा 5 जिलों में Boxing Rings की स्थापना
4.	**सिंथेटिक ट्रैक/Halls-** जयपुर के. चित्रकूट व विद्याधर नगर स्टेडियम, हनुमानगढ़, नागौर, नीमकाथाना-सीकर में Synthetic Tracks का निर्माण बांगड स्कूल स्टेडियम-पाली तथा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स-आबू रोड में विभिन्न खेलों के Courts, Halls तथा Running Tracks, झालावाड़ व अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में Indoor Halls का निर्माण पाली, झुंझुनूं, नागौर, करौली एवं सवाई मानसिंह स्टेडियम-जयपुर में grass grounds
5.	**उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्य-** सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में Seating Capacity में वृद्धि चन्द्रबरदाई खेल स्टेडियम व पटेल स्टेडियम-अजमेर का उन्नयन गंगासिंह स्टेडियम-श्रीगंगानगर का उन्नयन माउंट आबू Golf Course व Polo Ground का revival
6.	खेल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मेलों में मलखंभ, खो-खो, थंगटा, रस्साकसी एवं कबड्डी आदि पारम्परिक खेलों का आयोजन
7.	एक हजार खिलाड़ियों को मानदेय पर Part Time प्रशिक्षक की भूमिका

परिशिष्ट 12

पैरा संख्या 58 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन- डीग
2.	**सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उप जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन-** पुष्कर-अजमेर, कोटड़ी-भीलवाड़ा, विराटनगर-कोटपूतली बहरोड़, आहोर-जालोर, भवानीमंडी-झालावाड़, आऊ-जोधपुर, रायपुर-ब्यावर, गोगुंदा-उदयपुर देसूरी-पाली, समदड़ी-बालोतरा, समरानियां, केलवाड़ा-बारां, **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन-** सुनेल-झालावाड़ **शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से सैटेलाइट चिकित्सालय में क्रमोन्नयन- नवीन सैटेलाइट चिकित्सालय**-हरमाड़ा-जयपुर
3.	**प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन-** किशोरी (थानागाजी) अलवर, बमोरी कलां (अंता) - बारां, चांदरवाड़ा (आनन्दपुरी)-बांसवाड़ा, मौकलसर (सिवाना) - बालोतरा, कांकला (सहाड़ा), रायला-भीलवाड़ा, बायं (तारानगर)- चूरू, हस्तेड़ा (चौमूं), बधाल (फुलेरा)-जयपुर, रामदेवरा-जैसलमेर, पादरली (आहोर), बड़गांव (रानीवाड़ा) जालोर, नाथडाऊ, (शेरगढ़)-जोधपुर, खैरवा, (सुमेरपुर)-पाली, भीकमकोर (लोहावट)-फलौदी, लाम्बाहरिसिंह-टोंक
4.	नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-सोनियाणा (भदेसर)- चित्तौड़गढ़
5.	**उप स्वास्थ्य केन्द्रों से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नयन-** मुहामी, तबीजी-अजमेर, मौलिया, सोंखरी (कठूमर), खेड़ा-महमूद, चिड़वाई (रामगढ़), दिवाकरी, रूपबास-अलवर, चौखला (बागीदौरा), आमजा, सागवाड़िया, आसोड़ा (गढ़ी)- बांसवाड़ा, भीलखेड़ाडांग (शाहबाद), झनझनी, सेमली (छबड़ा)-बारां, आसोतरा (पचपदरा)-बाड़मेर, राजासर, धीरेरा (लूणकरणसर), श्रीरामसर, स्वरूपदेसर-बीकानेर, बरौलीरान, सुनारी-भरतपुर, परमदरा (नगर), हेलक-डीग, मलसीसर, सारोढ़ियां (सुजानगढ़)-चूरू, केलझर (बस्सी) - चित्तौड़गढ़, सालमपुर (महुवा)-दौसा, डेचा, कराड़ा (सागवाड़ा), मांडली (सीमलवाड़ा)- डूंगरपुर, रासलाना (भादरा)-हनुमानगढ़, कुहाड़ा, रामपुरा (विराटनगर)-कोटपूतली-बहरोड़, सावरदा (दूदू), नटाटा, सायपुरा (जमवारामगढ़), जोरपुरा, हाथोज-जयपुर, मूलाना, तेजमालता-जैसलमेर, सामरिया, कनाडी-झालावाड़, चुई, बिखरनिया कला (डेगाना), मुंदियाड, देऊ (खींवसर), धांधलास (मेड़ता) - नागौर, बस्सी (परबतसर)-डीडवाना कुचामन, भांवरी-पाली, आत्मा, सांगठकला-राजसमंद
6.	**नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र-** कैलूरी (नदबई), धौर गांव-भरतपुर, करनीनगर, खारिया (पोकरण)-जैसलमेर, देऊ, बोजास, दांतिणा, माडपुरा, ईश्वरनावड़ा, रिया

	श्यामदास, भावण्डा, भाटियों की ढाणी (लोहावट)- जोधपुर, बिंठवाल, पारासरा (खींवसर)-नागौर, गौरियां, मोहनपुरा (दांतारामगढ़) - सीकर, मरेवड़ा रामपुरिया (आसींद) - भीलवाड़ा
7.	**बेड क्षमता में वृद्धि- जिला चिकित्सालय**-निम्बाहेड़ा-चित्तौड़गढ़, महुवा-दौसा, राजसमंद, हनुमानगढ़, **उप जिला चिकित्सालय**-नावां-नागौर **सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र**-राशमी-चित्तौड़गढ़, करौली, पीलीबंगा-हनुमानगढ़, सायला-जालोर, जाँखल (नवलगढ़), बगड़, सुल्ताना-झुंझुनूं, खाचरियावास-सीकर, पीपलू (निवाई)-टोंक, सराड़ा-सलूम्बर, कापरेन-बूंदी, मुण्डावर-खैरथल तिजारा **भवन निर्माण कार्य** उप जिला चिकित्सालय-सरदारशहर-चूरू, लाडनूं-डीडवाना कुचामन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-भिनाय-अजमेर मसूदा ब्यावर, राशमी-चित्तौड़गढ़, शिवाड़-सवाई माधोपुर, रामसर-बाड़मेर
8.	ट्रोमा सेंटर-जोबनेर, कांवटिया, हरमाड़ा-जयपुर, मंडाना (लाडपुरा)-कोटा, बाप-फलौदी, गोगुंदा-उदयपुर, रायसिंहनगर-श्रीगंगानगर, नीमकाथाना-सीकर, नवलगढ़-झुंझुनूं, भरतपुर
9.	शहरी क्षेत्रों हेतु मुगसारार अलवर, धरणीधर-बीकानेर, बगरू-जयपुर सहित 148 Urban Ayushmaan Aarogya Mandir (UAAM) की स्थापना
10.	आयुर्वेद औषधालय-जायल-नागौर, नवलगढ़-झुंझुनूं का क्रमोन्नयन
11.	होम्योपैथिक औषधालय-बावड़ी खुर्द-फलौदी
12.	मातृ शिशु स्वास्थ्य विंग (MCH Wing)-भरतपुर

परिशिष्ट 13

पैरा संख्या 59 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान/कार्य
1.	मरीजों को उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए मेडिकल कॉलेजों से सम्बद्ध चिकित्सालयों में- (a) आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध रूप से 200 करोड़ रुपये व्यय कर नवीन उपकरण उपलब्ध करवाने के साथ-साथ वर्तमान उपकरणों का upgradation (b) रोगियों एवं उनके परिजनों को OPD प्रतीक्षा क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्निर्माण (c) सवाई मानसिंह चिकित्सालय-जयपुर में आगामी 2 वर्षों में भवन उन्नयन, parking, underground pathway तथा sky-walks आदि के लिए 150 करोड़ रुपये का व्यय, तथा जेके लोन, जयपुरिया, जनाना सहित SMS Medical College से सम्बद्ध समस्त अस्पतालों का उन्नयन (85 करोड़ रुपये) (d) पीबीएम चिकित्सालय-बीकानेर के Vitreo Retina Surgery Unit का उन्नयन (e) जेएलएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल-अजमेर के भवन का जीर्णोद्धार तथा उन्नयन के कार्य (50 करोड़ रुपये) राजस्थान डिज़िटल हैल्थ मिशन के अन्तर्गत IT based Queue Management System, Case History, Online Referral, Call Centre/Mobile App based Appointment की सुविधाओं हेतु 25 करोड़ रुपये का व्यय
2.	मेडिकल कॉलेज-बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा में 120 बैड क्षमता के Spinal Injury Centres की क्षमता वृद्धि मेडिकल कॉलेज-कोटा में Cancer Unit एवं Cottage Ward हेतु 195 करोड़ रुपये
3.	समस्त संभाग मुख्यालयों पर Ultra Advanced Burn Care Centres वरिष्ठ नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं सुलभ कराने हेतु RIMS जयपुर के अधीन Geriatric Healthcare Resource and Training Centre सभी संभाग मुख्यालयों के जिला अस्पतालों में Dedicated Geriatric Centres (रामाश्रय) का उन्नयन दिव्यांगजनों की चिकित्सा सुविधा हेतु संभागीय स्तर के Rehabilitation Centres का उन्नयन
4.	Non-Alcoholic Fatty Lever Disease की जांच हेतु संभाग स्तरीय अस्पतालों में Fibro Scan Machines की स्थापना तथा Screening हेतु अभियान
5.	Critical Care, ICU, SNCU, Labour Room, Operation Theatre आदि हेतु Specialized Nursing Cadre प्रदेश में Master in Physiotherapy Course प्रारम्भ

6.	केन्द्र सरकार के सहयोग से विभिन्न चिकित्सा संस्थानों में स्थापित Oxygen Plants का operation and maintenance (35 करोड़ रुपये)
7.	Rajasthan Institute of Medical Sciences (RIMS)- जयपुर के उन्नयन हेतु आगामी वर्ष 500 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

परिशिष्ट 14

पैरा संख्या 73 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	छात्रावास/आवासीय विद्यालय/अन्य आधारभूत सुविधायें
1.	रामगंज मण्डी-कोटा, पीसांगन एवं नसीराबाद-अजमेर, सुन्दरावली-डीग में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण (90 करोड़ रुपये)
2.	बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारां, भीलवाड़ा, हनुमानगढ़, बाड़मेर, दूदू, डीग, डीडवाना, अनूपगढ़, केकड़ी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, शाहपुरा, सलूम्बर एवं सिरोही में विद्यालय स्तरीय सावित्री बाई फुले छात्रावास (50 करोड़ रुपये)
3.	- अनूपगढ़, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, नदबई, डीडवाना-कुचामन, दूदू, डूंगरपुर, गंगापुर सिटी, केकड़ी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, नीमकाथाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर एवं शाहपुरा में महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास (82 करोड़ 45 लाख रुपये) -पाली एवं बांसवाड़ा में आर्थिक कमजोर वर्ग महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास - घुमन्तू अर्द्ध घुमन्तू समुदाय के बच्चों के लिए केशवाना-जालोर में छात्रावास - अटरू-बारां में सहरिया बालिका छात्रावास तथा झलाई (सीमलवाड़ा)-डूंगरपुर में जनजाति आश्रम छात्रावास
4.	अम्बेडकर छात्रावास खेड़ली-अलवर, बानसी व बेंगू-चित्तौड़गढ़, लूणकरणसर व डूंगरगढ़-बीकानेर, बिलाड़ा व पीपाड़ शहर-जोधपुर, बूसी-पाली, सिरोही, बूंदी, बेरिसल-कोटपूतली-बहरोड़, कुशलगढ़-बांसवाड़ा, बामनवास-सवाई माधोपुर तथा सावित्री बाई फुले छात्रावास बेगूं-चित्तौड़गढ़ के नकारा/अनुपयोगी/जर्जर/भवन विहीन छात्रावास भवनों का पुनर्निर्माण (54 करोड़ 30 लाख रुपये)
5.	681 छात्रावासों एवं 37 आवासीय विद्यालयों हेतु अनावर्तक सामग्री यथा-पलंग, गद्दा, तकिया, कम्बल, बेडशीट, खैश, तकिया कवर इत्यादि की सुविधा (7 करोड़ 18 लाख रुपये)

परिशिष्ट 15

पैरा संख्या 83 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	सुविधायें
1.	पुलिस की विभिन्न इकाइयों के लिए replacement basis पर 500 वाहन
2.	किशनगढ़, बीकानेर, जैसलमेर व जयपुर सिविल एयरपोर्ट पर Bomb Detection and Disposal Squads हेतु 150 पद सहित विभिन्न तकनीकी शाखाओं/ इकाइयों के लिए 531 पदों का सृजन
3.	नवीन न्याय संहिताओं की आवश्यकताओं हेतु कम्प्यूटर, कैमरों सहित विभिन्न सुविधायें (100 करोड़ रुपये)
4.	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर के Cyber Forensic Divisions का विस्तार एवं उन्नयन (25 करोड़ रुपये)

परिशिष्ट 16

पैरा संख्या 85 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	कार्य/सुविधायें
1.	अपराधों में संलिप्त रहे किशोर बालकों में सुधार हेतु जयपुर में किशोर सुधार गृह
2.	जयपुर, भरतपुर, कोटा व बीकानेर स्थित किशोर सुधार गृहों में बाल मनोवैज्ञानिक उपलब्ध करवाये जाने की सुविधा
3.	न्यायिक प्रकरणों, जेल आधिक्य की समस्या के त्वरित निस्तारण तथा नवीन कानूनों के क्रियान्वयन हेतु राज्य के कारागृहों में निरुद्ध विचाराधीन बंदियों की माननीय न्यायालय में पेशी Video Conference (VC) के माध्यम से करवाये जाने के लिए प्रथम चरण में 400 VC Nodes की स्थापना
4.	खुला बंदी शिविर-सांगानेर में 250 बंदियों हेतु 35 करोड़ रुपये की लागत से नवीन आवास
5.	कारागार में अवैध मोबाइल सिग्नल रोकने हेतु 7 केन्द्रीय कारागृहों में T-HCBS प्रणाली
6.	• सलूम्बर, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, कोटपूतली-बहरोड, बालोतरा, ब्यावर व डीग के उप कारागृहों का जिला कारागृहों में क्रमोन्नयन • खैरथल-तिजारा. में नवीन जिला कारागृह, तथा • कोटा, जालोर में नवीन कारागृह का निर्माण
7.	कारागृहों में निरुद्ध सजायाफ्ता बंदियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान
8.	अवैध रूप से Overstay करने वाले विदेशियों एवं अवैध प्रवासियों के लिए 100 बंदी क्षमता का 10 करोड़ रुपये की लागत से Detention Centre
9.	जेल विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु कारागार प्रशिक्षण संस्थान-अजमेर का Rajasthan Institute of Correctional Administration and Research के रूप में क्रमोन्नयन (10 करोड़ रुपये)
10.	उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनूं में खुला बंदी शिविर (पेट्रोल पम्प)

परिशिष्ट 17
पैरा संख्या 86 में उल्लिखित विवरण

I. पुलिस इकाई/कार्यालय सम्बन्धी कार्य	
क्र.सं.	पुलिस कार्यालय/थाने/पुलिस चौकी/आधारभूत संरचना क कार्य
1.	**अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय**-शाहपुरा-जयपुर, रींगस-सीकर
2.	**पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय**-रायपुर-ब्यावर, खाटूश्यामं जी-सीकर
3.	**पुलिस थाने**-नारायण विहार, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर
4.	**नवीन साईबर पुलिस थाने**- ब्यावर, बालोतरा, डीडवाना-कुचामन, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़. फलौदी, सलूम्बर
5.	**पुलिस चौकी से पुलिस थाने में क्रमोन्नयन** खोरा बीसल-जयपुर, अखेपुरा-अलवर, जंसनगर (मेड़ता)- नागौर
6.	**नवीन पुलिस चौकी**-खेतसिंह की प्याऊ-बाड़मेर, पाटन (आसींद) - भीलवाड़ा, बेगस (बगरू), हाथोज (कालवाड़), जयसिंहपुरा (भांकरोटा), गढ़गणेश (नाहरगढ़), टाटियावास (चौमूं). गोविन्दपुरा (सांगानेर), महला (दूदू)-जयपुर, झालामंड-जोधपुर, पलासली-खैरथल-तिजारा
7.	पुलिस कार्यालय इकाइयों के निर्माण/मरम्मत कार्य- मौजमाबाद (दूदू)-जयपुर थाना निर्माण कार्य
II. न्यायालय सम्बन्धी विभिन्न कार्य-	
क्र.सं.	**न्यायालयों की स्थापना/उन्नयन**
1.	**जिला एवं सैशन न्यायालय**-ब्यावर, सलूम्बर, फलौदी, डीडवाना-कुचामन, डीग, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, बाड़मेर
2.	**अतिरिक्त जिला एवं सैशन न्यायालय**- नदबई-भरतपुर, चाकसू-जयपुर, बर-ब्यावर, धौरीमन्ना (गुड़ामालानी)- बाड़मेर
3.	**वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय**-व्यावर, सलूम्बर, फलौदी, खैरथल-तिजारा, कोटपूतली-बहरोड़, डीडवाना-कुचामन, बालोतरा, डीग
4.	**सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट**-भिनाय-अजमेर
5.	**विशेष न्यायालय (पोक्सो एक्ट)**- हनुमानगढ़ः जोधपुर मेट्रो, सवाई माधोपुर व बीकानेर
6.	**विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)** - झुंझुनूं, प्रतापगढ़, टोंक
7.	विभिन्न न्यायिक कार्यालय भवनों तथा आवास निर्माण से सम्बन्धित कार्यों हेतु 350 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।

परिशिष्ट 18

पैरा संख्या 94 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	इकाइयों / कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन
1.	ऊर्जा विभाग- जहाजपुर-भीलवाड़ा, भादरा-हनुमानगढ़ में अधिशाषी अभियंता (विद्युत) मसूदा-ब्यावर, बाड़मेर ग्रामीण, धनाऊ (चौहटन)-बाड़मेर, झिनझियाली-जैसलमेर, सांकड़ा (पोकरण)-जैसलमेर, विवेक विहार (कुड़ी भगतासनी)-जोधपुर, खातोली-कोटा, रानौली (दांतारामगढ़) - सीकर, करड़ा-जालोर में सहायक अभियंता (विद्युत) जालूकी (नगर)-डीग में कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग- पलसाना-सीकर, पूगल-बीकानेर, राशमी-चित्तौड़गढ़ में सहायक अभियंता कार्यालय चौहटन-बाड़मेर में अधिशाषी अभियंता कार्यालय
3.	खनिज विभाग-डीडवाना-डीडवाना कुचामन में सहायक अभियंता (खनिज)
4.	वन विभाग-नदबई-भरतपुर में रेंजर कार्यालय
5.	मिनी सचिवालय-कोटा
6.	नवीन नगर पालिका भवन-नावां-डीडवाना कुचामन, सायला-जालोर
7.	अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय- अनूपगढ़-श्रीगंगानगर, केकड़ी-अजमेर, दूदू-जयपुर, नीमकाथाना-सीकर, सांचौर-जालोर, शाहपुरा-भीलवाड़ा, गंगापुरसिटी-सवाई माधोपुर को यथावत
8.	भवन निर्माण एवं जीर्णोद्धार- • भवन विहीन 20 उप तहसीलों, 10 तहसीलों तथा 7 उपखण्ड कार्यालयों के भवनों का निर्माण • पुराने जीर्ण-शीर्ण ग्राम पंचायत भवन, पंचायत समिति भवन एवं जिला परिषद् भवनों का पुनर्निर्माण (55 करोड़ रुपये)
9.	परिवहन विभाग- अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में जिला परिवहन कार्यालय, धौरीमन्ना-बाड़मेर में उप जिला परिवहन कार्यालय
10.	जयपुर सहित विभिन्न जिला मुख्यालयों पर कर्मचारी/अधिकारियों हेतु अतिरिक्त आवास व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए 180 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

परिशिष्ट 19

पैरा संख्या 97 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	कार्मिक कल्याण सम्बन्धी बिन्दु
1.	आगामी वर्ष में ऐसे कार्मिक, जिन्होंने अभी तक पदोन्नति हेतु एक बार भी अनुभव व सेवा अवधि में छूट का लाभ नहीं लिया हो, उन्हें 2 वर्ष की छूट दिये जाने की घोषणा करती हूँ। उक्त छूट का लाभ Contractual Hiring to Civil Posts Rules के अन्तर्गत नियोजित कार्मिकों को भी दिया जाना प्रस्तावित है।
2.	मंत्रालयिक कार्मिक, जेल प्रहरी, स्कूल व्याख्याता एवं प्रबोधकों आदि केडरों का पुनर्गठन कर, उनके पदोन्नति के अवसरों में वृद्धि हेतु कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है।
3.	समस्त मानदेय कर्मियों यथा-मिनी आंगनबाड़ी/आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ-बाड़ी कार्यकर्ता, Mid-Day Meal Cook cum Helper, लांगरी, Homeguards, REXCO एवं शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं इत्यादि के मानदेय में आगामी वर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही, इनकी सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त Gratuity का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है।
4.	अंशकालिक कार्मिक जैसे ग्राम प्रतिहारी, कुक आदि एवं एजेन्सी के माध्यम से नियोजित संविदा कार्मिकों के पारिश्रमिक में भी वृद्धि की जानी प्रस्तावित है। इसके साथ ही, प्रदेश में NFSA राशन वितरण का कार्य संभाल रहे Dealers के कमीशन में भी 10 प्रतिशत वृद्धि की जायेगी।
5.	Placement Agencies के माध्यम से कार्मिकों को संविदा पर नियोजित किये जाने की व्यवस्था को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर कार्मिक विभाग के अधीन राजकीय संस्था का गठन किया जाना प्रस्तावित करती हूँ।
6.	सहकारी बैंक के अधिकारी/कर्मचारियों को समर्पित अवकाश एवं सेवानिवृत्ति पर अनुपयोगी उपार्जित अवकाश का नकद भुगतान के रूप में लाभ दिया जाना प्रस्तावित है।
7.	सरकारी कर्मचारियों को एक अप्रैल, 2024 से बढ़ी हुई Gratuity का लाभ देय है। अब यह लाभ केन्द्र सरकार के अनुरूप एक जनवरी, 2024 से दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ।
8.	न्यायिक सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को भी राज्य सरकार के अन्य पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के अनुरूप 70 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिया जाना प्रस्तावित करती हूँ।

परिशिष्ट 20

पैरा संख्या 101 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	परियोजना/कार्य का नाम	लागत
1.	राणा प्रताप सागर बांध-ब्राह्मणी नदी से बीसलपुर बांध में जल अपवर्तन लिंक के कार्य हाथ में लिये जायेंगे तथा इनको आगे बढ़ाते हुए बीसलपुर बांध से बाणगंगा एवं रूपारेल नदी को चरणबद्ध रूप से जोड़े जाने सम्बन्धी कार्य की DPR-जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, डीग, अलवर	6 हजार 100 करोड़ रुपये (अनुमानित)
2.	पार्वती एवं बैथली नदी को जोड़ने के साथ ही, केलवाड़ा एवं समरानिया क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु DPR-बारां	4 करोड़ 50 लाख रुपये
3.	मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना, बकानी क्षेत्र में मोरी रिजर्वायर, किशन नगर, भेसाझर माइक्रो सिंचाई परियोजना, धरोनिया, कचराखेड़ी, गुराडिया, कोडिझर एवं नानागरदा MST तथा गोरेश्वर महादेव एनिकट का निर्माण कार्य- झालावाड़	2 हजार 250 करोड़ रुपये
4.	धौलपुर लिफ्ट परियोजना तथा कालीतीर परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु प्रावधान	950 करोड़ रुपये

परिशिष्ट 21

पैरा संख्या **102** में उल्लिखित विवरण

I. नदी बेसिन सहित विभिन्न परियोजनाओं की **DPR**/निर्माण कार्य-		
क्र.सं.	**परियोजना का विवरण**	**लागत**
1.	सोम-कमला-अम्बा बांध से मानसून के अधिशेष जल को अपवर्तन हेतु मोरेन नदी बेसिन/लोडेश्वर बांध तक उच्च स्तरीय रिचार्ज नहर का निर्माण करने हेतु DPR **लाभान्वित क्षेत्र**-आसपुर व सागवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न तालाबों/बांधों, यथा-बोडीगामा, पुंजपुर, गडाझुमजी, लोडेश्वर आदि तालाबों में जल अपवर्तन किया जाकर लगभग 5 हजार हेक्टेयर कमाण्ड की जल उपलब्धता	50 लाख रुपये
2.	डूंगरपुर जिले में Catch the Rain के अन्तर्गत सम्पूर्ण मोरन नदी को पुनर्जीवित करते हुए खड़गदा गांव का विकास, गौरेश्वर महादेव एवं नीलकण्ठ महादेव जी मंदिरों का सौन्दर्गीकरण करने हेतु DPR	50 लाख रुपये
3.	डूंगरपुर जिले में माही बेसिन/नदी पर वमासा एवं पादरडी एनिकटों का निर्माण कर लगभग 50 MCFT जल भंडारण के कार्य, हनुमानवाला, वगेरी एवं भुवासा एनिकटों पर सौर ऊर्जा आधारित सूक्ष्म सिंचाई परियोजना **लाभान्वित क्षेत्र**-डूंगरपुर जिले के काण्ठल क्षेत्र के साथ लगभग 20 गांवों के एक हजार 500 हेक्टेयर भूमि में कमाण्ड क्षेत्र/सिंचित क्षेत्र	150 करोड़ रुपये
4.	भीखाबाई सागवाड़ा नहर में मुख्यतः deep cutting क्षेत्र में जल भराव, aquaduct की स्थिति क्षतिग्रस्त/leakage, deep cutting क्षेत्र में मिट्टी/slope ढहने की स्थिति तथा माही नदी में विद्यमान साईफन से अत्यधिक रिसाव आदि समस्याओं का निस्तारण व जीर्णोद्धार कार्य हेतु DPR	50 लाख रुपये
5.	**Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project (RWSLIP)-Phase-III** 36 सिंचाई उप परियोजनाओं के सिंचाई सम्बन्धी कार्य से एक लाख 40 हजार हेक्टेयर क्षेत्र लाभान्वित	342 करोड़ रुपये
6.	कानोता, चन्दलाई तथा नेवटा बांधों- जयपुर से सिंचाई/पेयजल उपयोग के लिए गुणवत्ता सुधार, पर्यावरण एवं पर्यटन वृद्धि हेतु DPR	90 लाख रुपये

7.	भरतपुर जिले में बाणगंगा, गम्भीरी एवं रूपारेल नदियों से निकलने वाले Feeder Systems, Head Regulator एवं अन्य संरचनाओं के जीर्णोद्धार एवं नवीनीकरण के कार्य कराये जाने हेतु DPR तथा प्रथम चरण के कार्य	100 करोड़ रुपये
II इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से सिंचाई सम्बन्धी कार्य-		
क्र.सं.	**कार्य का विवरण**	**लागत**
1.	संगरिया, टिब्बी, रावतसर, हनुमानगढ़, पीलीबंगा के एक लाख 7 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण-हनुमानगढ़	590 करोड़ रुपये
2.	बरसलपुर शाखा नहर प्रणाली क्षेत्र के 72 हजार 246 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों के जीर्णोद्धार की DPR व निर्माण कार्य (कोलायत)-बीकानेर	250 करोड़ रुपये
3.	रायसिंह नगर, अनूपगढ़, घड़साना, रावला, श्रीविजय नगर के 44 हजार हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र में पक्के खालों का पुनर्निर्माण-श्रीगंगानगर	200 करोड़ रुपये
4.	धोधा वितरिका एवं दांतौर वितरिका शाखा नहर प्रणाली क्षेत्र के 65 हजार 113 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों की DPR व निर्माण कार्य (खाजूवाला)-बीकानेर	230 करोड़ रुपये
5.	मुख्य नहर की आरडी 961 से 1050 के मध्य से निकलने वाली चारणवाला ब्रांच प्रणाली, गोगड़ियावाला माईनर एवं बीकमपुर माईनर के 44 हजार 250 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिग्रस्त खालों की DPR व जीर्णोद्धार कार्य (कोलायत)-बीकानेर, फलौदी, (पोकरण)-जैसलमेर	150 करोड़ रुपये
6.	गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर प्रणाली के रिमॉडलिंग का कार्य (कोलायत)-बीकानेर, फलौदी, (पोकरण) - जैसलमेर	100 करोड़ रुपये
7.	इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 620 से 1 हजार 458 तक नहर के दोनों पटड़ों के सुदृढ़ीकरण का कार्य (कोलायत, लूणकरणसर)-बीकानेर, फलौदी, (पोकरण)-जैसलमेर, श्रीगंगानगर	75 करोड़ रुपये
8.	बाबा रामदेव ब्रांच की आरडी 35 से 231 के मध्य निकलने वाली नहरों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण का कार्य-जैसलमेर	75 करोड़ रुपये
9.	बाबा रामदेव ब्रांच की आरडी 0 से 302 के मध्य जीर्णोद्धार का कार्य-जैसलमेर	65 करोड़ रुपये

10.	कोलायत वितरिका नहर का पुनरूद्धार कार्य (कोलायत)-बीकानेर	35 करोड़ रुपये
11.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना-द्वितीय चरण की गुरु जम्भेश्वर लिफ्ट नहर के शेष रहे क्षेत्र में स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा विकसित करने का कार्य-फलौदी	35 करोड़ रुपये
12.	खिदरत वितरिका नहर का पुनरूद्धार कार्य (कोलायत)-बीकानेर, फलौदी	25 करोड़ रुपये
13.	चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट नहर के RD 34.00 से 36.850 के मध्य Balancing Reservoir का निर्माण (नोहर) हनुमानगढ़	25 करोड़ रुपये
14.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना-द्वितीय चरण में बीकानेर तथा जैसलमेर में मुख्य नहर हेतु Balancing/Storage Reservoir के निर्माण कार्य हेतु DPR	10 करोड़ रुपये
15.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना-द्वितीय चरण की आरडी 620 से 1 हजार 458 के मध्य कमाण्ड क्षेत्र के विभिन्न चकप्लान, बाराबंदी खतौनी एवं सरकारी भूमि खातों के Digitization कार्य की DPR	15 करोड़ रुपये
16.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना-द्वितीय चरण की सभी लिफ्ट नहरों के pump house में उपयोग होने वाली बिजली उपयोग कम किये जाने हेतु सोलर पार्क बनाये जाने की DPR (कोलायत, लूणकरणसर)-बीकानेर, फलौदी, (पोकरण)-जैसलमेर	15 करोड़ रुपये
III	**भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की नहरों, वितरिका एवं माईनर के कार्य-**	
क्र.सं.	**कार्य का विवरण**	**लागत**
1.	मम्मडखेड़ा वितरिका (एमएमके) (लगभग 37 किमी. लम्बाई, 28 हजार 221 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र)	40 करोड़ 86 लाख रुपये
2.	मोरजण्डा वितरिका (एमजेडी) व लालगढ़ माईनर (एलएलजी) (लगभग 49 किमी. लम्बाई, 38 हजार 779 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र)	51 करोड़ 14 लाख रुपये
3.	लोंगेवाला वितरिका (एलजीडब्ल्यू), खरलिया वितरिका (केएल), लाखासर वितरिका (एलकेएस) (लगभग 47 किमी. लम्बाई, 12 हजार 970 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र)	34 करोड़ 74 लाख रुपये
4.	जोडकिया वितरिका (लगभग 26.61 किमी. लम्बाई, 9 हजार 544 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र)	18 करोड़ रुपये

5.	लिंक जीजीआर सब ब्रांच ऑफटेकिंग आईजीएफ आरडी 644.200 R/S से टेल एसजीसी आरडी 54.700 तक (लगभग 16.67 किमी. लम्बाई, 40 हजार 821 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र)	23 करोड़ रुपये
6.	न्यू फतेहगढ़ माईनर (लगभग 9.25 किमी. लम्बाई, 2 हजार 32 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र)	6 करोड़ रुपये
7.	श्रीनगर माईनर (लगभग 5.95 किमी. लम्बाई, 1 हजार 566 हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र)	4 करोड़ रुपये
	IV. सिंचाई सम्बन्धी अन्य कार्य-	
क्र.सं.	**कार्य का विवरण**	**लागत**
1.	देवरी माता एनिकट (नसीराबाद), सीताराम एनिकट, मसानिया-अजमेर, मेज नदी पर नेगढ़ एनिकट (केशोरायपाटन), ऐरू नदी पर गुडा, पिपलदा, कूरेल नदी पर वनखेड़ा गांव, चेता के एनिकट (हिण्डोली)-बूंदी; पुरैनी (किशनगंज), अंधेरी नदी पर फूलबड़ौद व घाघोनिया ग्राम के पास (छबड़ा), पचेल कला गांव में खाड़ी पर एनिकट (अंता), होडापुरा गांव, कांकदडा में धोबीघाट के पास, सायगढ़ (किशनगंज)-बारां; उदयपुरा, रतनपुरा (रामगढ़ पचवारा)-दौसा, वमासा, पाडलिया (सागवाड़ा)- डूंगरपुर, चन्द्रावला (सांगोद)-कोटा, कालीसिंध नदी पर हीचड (खानपुर), आहु नदी पर हरनावदागाजा के पास (झालरापाटन)-झालावाड़; चौरायता-प्रतापगढ़, ऊंडिया, दातो का देव (भीम)- राजसमंद, गीगला, लिमजिया पंडेर-सलूम्बर, करोटी, वाडका (रेवदर)-सिरोही, बाणिया का टुंकडा (कुम्भलगढ़)-पाली, माही, जाखम, मंडूर नदी पर- उदयपुर, सुरानी व कल्याणपुरा-सीकर सहित 100 एनिकटों का निर्माण एवं जीर्णोद्धार।	500 करोड़ रुपये
2.	लघु सिंचाई परियोजना के निर्माण का कार्य- कचनरिया खुर्द, तुमडा (छबड़ा), रानीहेड़ा आदि गांवों में लिफ्ट परियोजना द्वारा सिंचाई सुविधा (किशनगंज)-बारां, भीम व भोपालसागर, सांगठ बांध-राजसमंद	85 करोड़ रुपये
3.	तालाब मरम्मत व जीर्णोद्धार कार्य- लाखोलाव तालाब, हनुवंतिया, छोटा तालाब चाट, जैतगढ़ (नसीराबाद) अजमेर, पछाड तालाब, गोरधपुरा गोशाला के पास तालाब-छीपाबड़ौद (छबड़ा), मेरमाचाह तालाब (अटरू), हरसोली तालाब (अंता),	26 करोड़ 30 लाख रुपये

	छबड़ा सेमला-बारां; डोराई तालाब (बड़ी सादड़ी)-चित्तौड़गढ़; बोर का भाटडा (चौरासी)- डूंगरपुर	
4.	एमएसटी/WHS/Reservoir का निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य- घूघरा में Water Harvesting Structure (WHS) मरम्मत व जीर्णोद्धार कार्य-अजमेर, धावडाझिरी (छबड़ा) -बारां; उमरिया (डग), गागरिन बांध से लिफ्ट से Artificial Reservoir का निर्माण कार्य हेतु DPR-झालावाड़, खैरियादो बांध (धमोतर)-प्रतापगढ़	15 करोड़ 25 लाख रुपये
5.	बाढ़ बचाव सम्बन्धी कार्य- परवन नदी पर कटावर के पास सुरक्षा दीवार का निर्माण (अटरू), बारां शहर में शेष रहे नालों का सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण का कार्य-बारां; सीमलिया कस्बे में Flood Diversion का कार्य, विनोदखुर्द में जल भराव एवं बाढ़ बचाव का कार्य एवं कनवास तहसील (आवां क्षेत्र) में बाढ़ बचाव हेतु DPR (सांगोद)-कोटा	107 करोड़ 40 लाख रुपये
6.	नहरों का निर्माण/मरम्मत कार्य- पुष्कर सरोवर के फीडर्स, बडलिया फीडर, फूलसागर बीर फीडर, कायड फीडर-अजमेर, गुढ़ा बांध दांयी एवं बांयी मुख्य नहर, बटावदी बांध की नहर (केशोरायपाटन), डाबी लघु सिंचाई परियोजना की नहर का जीर्णोद्धार कार्य-बूंदी; परवन लिफ्ट योजना की दायीं मुख्य नहर की लाइनिंग एवं जीर्णोद्धार का कार्य (अटरू), मांगरोल से पार्वती नदी तक बाणगंगा की रिसेक्सनिंग का कार्य (अंता)-बारां; सुजानगंगा नहर-भरतपुर; भीमसागर बांध की नहर, कनवाडा बांध की मुख्य नहर एवं माईनरों की लाईनिंग का कार्य (झालरापाटन)- झालावाड़; कुंडेली बांध/नहर प्रणाली (भीम), माताजी का खेड़ा तालाब की चावण्डिया नहर (नाथद्वारा)- राजसमंद, बुचारा बांध (विराटनगर)-कोटपूतली बहरोड़, सावनभादो (सांगोद)-कोटा, टोडाभीम करौली, टूटिया बांध (सोजत), बांकली बांध (सुमेरपुर) पाली, खरताना बांध (मावली)-उदयपुर, सेलवाड़ा बांध, टोकरा बांध, मुंगथला बांध, मंडार नाला बांध (रेवदर)-सिरोही	107 करोड़ 30 लाख रुपये
7.	बीकानेर केनाल का पंजाब राज्य में स्थित भाग (RD 45 से RD 368) का CC lining, ग्रेवल रोड तथा पट्डों का निर्माण	300 करोड़ रुपये
8.	गुड़गांवा नहर के अधिशेष जल को Homes Canal में अपवर्तन हेतु गुड़गांवा नहर की Tail वितरिका को Homes	50 करोड़ रुपये

	Canal को लिंक करने सम्बन्धी कार्य, गुड़गांवा मुख्य नहर के RD 1210 से RD 1750 तक का जीर्णोद्धार कार्य, तथा नौनेरा, पथवारी, नगला दादूं एवं नगला चाहर इत्यादि के जल भराव क्षेत्रों से जल की निकासी हेतु नई ड्रेन का निर्माण-डीग	
9.	पनोरिया लिफ्ट सिस्टम तथा गुड़ामालानी लिफ्ट माइनर सिस्टम- नर्मदा केनाल प्रोजेक्ट के जीर्णोद्धार एवं मैनेटेनेंस का कार्य-बाड़मेर	8 करोड़ 50 लाख रुपये
10.	राजस्थान फीडर की आरडी 0 से आरडी 179 तक के जीर्णोद्धार कार्यों की DPR	5 करोड़ रुपये
11.	गुलर बांध (सांगानेर) से चंदलाई फीडर (Unlined Section) की दोनों तरफ concrete wall का निर्माण तथा इसके वेस्ट वियर व बांध की पाल की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार, जंगल सफाई का कार्य, Stone Pitching इत्यादि के कार्य-जयपुर	23 करोड़ रुपये
12.	जैसलमेर के बड़ाबाग, गडीसर, मूलसागर तथा अमरसागर जलाशयों का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य हेतु DPR	50 लाख रुपये
13.	बीसलपुर परियोजना की दायीं व बायीं मुख्य नहर व विभिन्न माइनर प्रणालियों की मरम्मत व जीर्णोद्धार के कार्य-टोंक	102 करोड़ 71 लाख रुपये

परिशिष्ट 22

पैरा संख्या 108 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम
1.	* प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायत स्तर पर चरणबद्ध रूप से आगामी 4 वर्षों में Custom Hiring Centres की स्थापना। आगामी वर्ष में, एक हजार Custom Hiring Centres (210 करोड़ रुपये) * आधुनिक तकनीकी आधारित कृषि उपकरणों यथा-Power Tiller, Disc Plough, Cultivator, Harrow, Reaper, ट्रैक्टर चलित यंत्र आदि को उपलब्ध करवाने हेतु 300 करोड़ रुपये का अनुदान। इससे लगभग एक लाख कृषक लाभान्वित होंगे।
2.	* महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कृषि भूमिधारकों, SC/ST/BPL श्रेणी के एक लाख परिवारों को व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी में Farm Ponds, डिग्गी, फलदार पौधारोपण, मेड़बंदी आदि कार्यों पर लगभग 700 करोड़ रुपये की राशि का व्यय
3.	* फसलों के उत्पादन में बीज की किस्म एवं गुणवत्ता की महत्वपूर्ण भूमिका के दृष्टिगत 11 लाख 50 हजार किसानों को संकर मक्का, 8 लाख किसानों को बाजरा, 5 लाख किसानों को मूंग व मोठ, 7 लाख किसानों को सरसों बीज तथा एक लाख 50 हजार जनजातीय कृषकों को सब्जियों हेतु 35 लाख बीज मिनीकिट (180 करोड़ रुपये) * National Mission on High Yielding Seeds के तकनीकी मार्गदर्शन को प्राप्त करते हुए मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना के अन्तर्गत 5 लाख 44 हजार कृषकों को गुणवत्तायुक्त बीज उत्पादन हेतु एक लाख 13 हजार क्विंटल बीज (63 करोड़ रुपये)
4.	* मृदा की Fertility एवं Productivity बनाये रखने की दृष्टि से मृदा शक्ति संवर्धन योजना के अंतर्गत कृषकों को हरी खाद के लिए 3 लाख ढेंचा बीज मिनिकिट एवं 50 हजार किसानों को गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के अन्तर्गत लाभान्वित किया जायेगा।
5.	* कृषि में AI का उपयोग कर उत्पादकता बढ़ाने हेतु 50 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence of Artificial Intelligence in Agriculture की स्थापना * मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि एवं मूल्य संवर्धन हेतु बांसवाड़ा में 20 करोड़ रुपये की लागत से Centre of Excellence for Maize की स्थापना
6.	* प्रदेश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने हेतु प्रतिवर्ष 2 हजार कृषकों को 5 हजार रुपये तक अनुदान के साथ ही आवश्यक प्रशिक्षण हेतु 11 करोड़ रुपये का व्यय * भरतपुर में 15 करोड़ रुपये की लागत से Centre

	of Excellence for Honey Bee-keeping की स्थापना की जायेगी।

परिशिष्ट 23

पैरा संख्या 120 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	कार्य का नाम
1.	विकसित राजस्थान @ 2047 की कार्य योजना अन्तर्गत आगामी 2 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से अजमेर, पावटा-बहरोड़ कोटपूतली, रेवदर-सिरोही सहित विभिन्न मण्डी प्रांगणों में आधुनिक आधारभूत सुविधाओं के कार्य (125 करोड़ रुपये व्यय)
2.	प्रदेश में Food / Agro/Mini Food Parks विकसित किये जाने हेतु 32 स्थानों पर भूमि का आवंटन किया जा चुका है। अनूपगढ़-श्रीगंगानगर में मिनी फूड पार्क, सांचौर-जालोर में एग्रो फूड पार्क बनाये जायेंगे। चूरू, जयपुर, झुंझुनूं, सिरोही, दौसा में भी कृषि प्रसंस्करण की आधारभूत सुविधायें सुलभ करवाये जाने की दृष्टि से निःशुल्क भूमि आवंटन कर PPP Mode पर विकसित किया जायेगा।
3.	मण्डी प्रांगणों एवं समर्थन मूल्य क्रय केन्द्रों पर किसानों द्वारा लायी गई कृषि जिन्सों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु मंडियों में Power Cleaning Machines लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से स्थापना।
4.	महात्मा ज्योतिबा फुले मण्डी श्रमिक कल्याण योजना के अन्तर्गत अनुज्ञाधारी श्रमिकों की दो पुत्रियों की सीमा तक विवाह हेतु सहायता राशि 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये प्रति विवाह।
5.	राज्य के प्रमुख शहरों की मंडियों/सब्जी बाजार में उत्पन्न होने वाले Solid Waste निस्तारण के लिए Bio-composters हेतु Composting Machine लगाने के लिए Corpus Fund.
6.	कृषि उपज मण्डी- बीदासर (सुजानगढ़)- चूरू, भिनाय, रूपनगढ़-अजमेर, टपूकड़ा-खैरथल तिजारा, रामगढ़ पचवारा-दौसा, नावां, खाटू खुर्द-डीडवाना कुचामन, सीमलवाड़ा-डूंगरपुर, राजाखेड़ा-धौलपुर फल-सब्जी मण्डी-जैतारण ब्यावर, सिरोही गौण कृषि मण्डी-बनेठा-टॉक, मण्डार-सिरोही
7.	बारां में लहसुन उत्कृष्टता केन्द्र
8.	100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 मीट्रिक टन क्षमता के गोदामों के पुनर्निर्माण हेतु 12 करोड़ रुपये का अनुदान
9.	500 मीट्रिक टन क्षमता के 100 व 250 मीट्रिक टन क्षमता के 50 गोदामों का ग्राम सेवा/क्रय-विक्रय सहकारी समितियों में निर्माण कार्य हेतु 33 करोड़ रुपये का अनुदान
10.	3 हजार प्याज भंडारगृहों के निर्माण हेतु 26 करोड़ रुपये का अनुदान

परिशिष्ट 24

पैरा संख्या 124 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	जिला दुग्ध संघ एवं पशु आहार संयंत्र सम्बन्धी कार्य	लागत
1.	Milk Plants की processing capacity में वृद्धि- सीकर-झुंझुनूं, श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़, जोधपुर व कोटा	115 करोड़
2.	नवीन दुग्ध संयंत्र अलवर, उदयपुर, बांसवाड़ा, भरतपुर व सवाई माधोपुर	225 करोड़
3.	नवीन बाईपास प्रोटीन पशुआहार संयंत्र- राजसमंद नाथद्वारा व उदयपुर	150 करोड़
4.	पशु आहार संयंत्र का विस्तार-जोधपुर	50 करोड़

परिशिष्ट 25

पैरा संख्या 127 में उल्लिखित विवरण

क्र.सं.	पशु चिकित्सा संस्थान/सुविधायें
1.	**पशु चिकित्सा उपकेन्द्र-** घाट का बराना (केशोरायपाटन) बूंदी, लाम्बी अहीर झुंझुनूं, चौपड़ों की ढाणी (खींवसर)- नागौर सहित 200 ग्राम पंचायतों में नवीन पशु चिकित्सा उप केन्द्र
2.	**पशु चिकित्सा संस्थानों का क्रमोन्नयन-** डेगाना-नागौर, मकराना डीडवाना कुचामन, मुण्डावर खैरथल तिजारा, सांचौर-जालोर, दूदू-जयपुर, शाहपुरा-भीलवाड़ा सहित 25 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों का बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन। निमाज (जैतारण) ब्यावर, गिराब-बाड़मेर, सवाईपुर-भीलवाड़ा, चौमामालियान (सांगोद) कोटा सहित 50 पशु चिकित्सालयों का प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन। आडसर-बीकानेर, रोहिड़ी (शिव) बाड़मेर, छापरेल (जहाजपुर) - भीलवाड़ा, बूटाटी (डेगाना)-नागौर, टिटपुरी (कठूमर) अलवर, हडियाला (तारानगर)-चूरू सहित 50 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन।
3.	**पशु चिकित्सा संस्थान-** हिंगोनिया-जयपुर एवं राजुवास-बीकानेर में पशुओं के लिए 'नेत्र चिकित्सा स्पेशियलिटी सेन्टर' तथा बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय, सांगानेर में 'Animal Prosthetic Centre' पॉलीक्लिनिक, पांचबत्ती जयपुर को Centre of Excellence- Rajasthan Institute of Veterinary Sciences के रूप में विकसित किया जाना। बस्सी-जयपुर में Sex Sorted Semen Lab
4.	**पशु चिकित्सा सम्बन्धी आधारभूत कार्य-** पशु चिकित्सा संस्थाओं, कार्यालयों, प्रयोगशालाओं के भवन निर्माण/मरम्मत, चारदीवारी, उपकरण तथा फर्नीचर हेतु 75 करोड़ रुपये का व्यय

परिशिष्ट 26

पैरा संख्या 129 में उल्लिखित सूची

क्र.सं.	वन एवं वन्यजीवों की परियोजनायें/कार्य
1.	प्रदेश के अधिसूचित 5 बाघ परियोजना क्षेत्रों-रणथम्भौर, सरिस्का, मुकुन्दरा हिल्स, रामगढ़ विषधारी व धौलपुर-करौली में स्थित चौकी, नाका एवं Anti-Poaching Camp में 35 करोड़ रुपये की लागत से मूलभूत सुविधाओं का विकास।
2.	बाघ संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त वन्यजीव अभयारण्यों, Conservation Reserves तथा प्रादेशिक वन क्षेत्रों में Prey-base में वृद्धि हेतु 30 करोड़ रुपये की लागत से 20 Prey-base Augmentation Enclosures स्थापित किये जायेंगे।
3.	घड़ियाल संरक्षण की दृष्टि से सवाई माधोपुर में पालीघाट के निकट घड़ियाल Rearing Centre स्थापित किया जायेगा।
4.	सवाई माधोपुर-करौली क्षेत्र में स्थानीय समुदायों तथा विशेषज्ञों की सहायता से विलुप्त होती सियागोश (Caracal) प्रजाति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु आवश्यक कार्य करवाये जायेंगे।
5.	Man-Animal Conflict से वन्यजीवों को समय पर rescue करने तथा उपयुक्त स्थान पर translocate करने हेतु 5 rescue वाहन मय उपकरण उपलब्ध करवाये जायेंगे।
6.	मुकुन्दरा राष्ट्रीय अभयारण्य में वन्यजीवों के लिए चम्बल नदी से पेयजल उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की जायेगी।
7.	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (घना) भरतपुर में संरक्षण गतिविधियों-Internal Road, पाल मरम्मत आदि विभिन्न कार्य 20 करोड़ रुपये की लागत से करवाये जायेंगे।
8.	अभेड़ा Biological Park, कोटा में Master Plan के अनुसार 35 प्रजातियों हेतु शेष रहे 22 Enclosures बनाये जायेंगे।
9.	अमरख महादेव-उदयपुर व गंगा भैरव घाटी-अजमेर Leopard Conservation Reserves तथा नाहरगढ़ अभयारण्य-जयपुर के बीड़ पापड़ क्षेत्र में Leopard Safari प्रारम्भ की जायेगी।